RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

DR. M. MOHAN RAO
IAS (Retd)
CHAIRMAN

M. ARUNA MOHAN RAO
IPS (Retd)
DIRECTOR (ACADEMICS)

अगस्त–2022

करेन्ट अफेयर्स मैगजीन

- पर्यावरण एवं परिस्थितिकी
- राजव्यवस्था एवं प्रशासन
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- कला और संस्कृति
- अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध
- सामाजिक मुद्दे
- आंतरिक सुरक्षा
- अर्थव्यवस्था
- विविध

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams

R-26, Zone-II, Opp Railway track, M.P. Nagar, Bhopal
Call us
0755-7967814, 7967718, +918319618002

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of RACE)

अगस्त -2022

करेंट अफेयर

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ सं.
कला और संस्कृति	1-9
आषाढ़ी बीज	
जगन्नाथ रथ यात्रा	
क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू	
मानगढ़ पहाड़ी	
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के बारे में	
यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति	
नए संसद भवन के शिखर पर स्थापित राष्ट्रीय चिह्न	
धम्मचक्क दिवस 2022	
भगवान बुद्ध के अवशेष	
संत तुकाराम जी	
बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस	
राजनीति	10-15
उप राष्ट्रपति चुनाव, 2022	
राज्यसभा के मनोनीत सदस्य	
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23:	
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	16-22
भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना	
मिट्टी से बना नॉन-इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट	
मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस	
सिंगल यूज प्लास्टिक बैन	
संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन	
अर्थव्यवस्था	23-33
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड **(USOF)**	
एंजेल फंड के लिए नियामक ढांचा	
MSDE ने **DBT** योजना शुरू की	

RAO'S ACADEMY

राज्यों के अभ्यास 2021 की रैंकिंग

NICDP के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण

विदेशी खरीद के लिए निजी क्षेत्र के बैंक

विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

रेलवे के लिए स्टार्टअप

कैबिनेट ने **IMT/5G** स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने स्थापना दिवस मनाया

विज्ञान और तकनीक 34-50

PSLV-C53

खोजी गई नई सामग्री

तेजी से चार्ज होने वाला ई-साइकिल विकसित हुआ

आदित्य-**L1** साइंस सपोर्ट सेल

विभिन्न पेलोड का विवरण

इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022

भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज **(NIXI)**

कैंसर पैदा करने वाला वायरस एपस्टीन बार वायरस **(EBV)**

बाइनरी सुपर विशाल ब्लैक होल

मंकी पॉक्स का प्रकोप

नई मेमोरी डिवाइस

SARS-CoV-2 के वायरस लोड को नियंत्रित करने वाला **Covaxin**

नव विकसित अल्ट्राथिन हेटरोप्रोटीन फिल्म

इंडियन ऑयल का सूर्य नूतन इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम

सी-डॉट ने जालोर नेटवर्क्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

सामाजिक मुद्दे 51-76

सहकारिता का 100वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस

कोई सेवा शुल्क नहीं

भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन

22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला

eNAM के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म **(POP)** लॉन्च किया गया

बागवानी उत्पादन

मरम्मत के अधिकार पर रूपरेखा (राइट टू रिपेयर)

मिशन शक्ति

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) - वार्षिक रिपोर्ट

भारत में प्रवास, 2020-2021

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने श्जागृतिश की शुरुआत की

उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2022

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

ई-विद्या को यूनेस्को की मान्यता

20वां लोक मेला और 13वां कृषि मेला

निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल **(NIPUN)**

वन नेशन वन राशन कार्ड

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए विनियम

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी)

भारत की टमटम और प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते

सेशेल्स स्वतंत्रता दिवस में भारत की भागीदारी

अंतरराष्ट्रीय संबंध **77-82**

38वां भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती

I2U2 शिखर सम्मेलन

कोलंबो में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र

14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

G7 शिखर सम्मेलन

आंतरिक सुरक्षा **83-86**

स्वायत्त फ्लाइंग विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक

अग्निपथ योजना

विविध **87-94**

आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान

परिमन: एनसीआर के लिए जियो-पोर्टल सार्वजनिक किया गया

नीति आयोग ने अपने सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर का स्वागत किया

कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस)

भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा

रक्षा मंत्रालय ने एक शीर्ष समिति का गठन किया

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के बारे में

44वां शतरंज ओलंपियाड

योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

1.30 लाख छात्र योग प्रशिक्षक के रूप में

बी एंड डब्ल्यूएसएससी के बारे में

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

RAO'S ACADEMY

1 कला और संस्कृति

आषाढ़ी बीज

प्रधानमंत्री ने कच्छी नव वर्ष 'आषाढ़ी बीज' के शुभ अवसर पर सभी को, विशेष रूप से दुनिया भर में फैले जीवंत कच्छी समुदाय को बधाई दी।

आषाढ़ी बीज के बारे में

- आषाढ़ी बीज उत्तर भारत विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य स्थानों में कृषक समुदायों (कच्छी समुदाय) के लिए एक शुभ दिन है।
- यह हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है,
- यह कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है।
- गुजरात के कच्छी समुदाय इस दिन अपना नया साल मनाते हैं।
- आषाढ़ी बीज के समय वातावरण में नमी की जांच की जाती है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि आने वाले मानसून में कौन सी फसल बेहतर होगी।
- भक्त भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य क्षेत्रीय देवताओं की पूजा करते हैं और सत्संग का आयोजन करते हैं।

जगन्नाथ रथ यात्रा

प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा, जिसे रथों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, को दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रथ यात्रा माना जाता है।

- इस वर्ष, यह उत्सव 01 जुलाई को पुरी, ओडिशा में शुरू होकर 12 जुलाई तक चला।

रथ यात्रा के बारे में

- इस यात्रा का हिन्दू धर्म में अत्यधिक महत्व है माना जाता है कि भगवन जगन्नाथ प्रजा से मिलने के लिए पवित्र स्थान से बाहर आते हैं।

RAO'S ACADEMY

- उत्सव हिंदू पवित्र ग्रंथों - ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और कपिला संहिता में प्रलेखित है।
- ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा, पुरी की यात्रा करना चाहती थीं।
- अत: उनकी इच्छा पूरी करने ले लिए भगवान जगन्नाथ, अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र के साथ, बहन देवी सुभद्रा के साथ रथ पर पुरी की यात्रा के लिए निकले।
- तब से, यह त्योहार भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की वार्षिक औपचारिक यात्रा का प्रतीक है।
  - ♦ यह यात्रा उनके गृह मंदिर से शुरू होकर दूसरे मंदिर तक जाती है जो उनकी मौसी का घर माना जाता है।
- जगन्नाथ यात्रा एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसके अनुष्ठान में हिंदू देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करने की अनुमति मिलती है।
- तीनों रथों के अपने-अपने नाम हैं।
- जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदीघोष, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को क्रमश: तलध्वज और दर्पदलन कहा जाता है।

क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू

प्रधान मंत्री ने भीमावरम (आंध्र प्रदेश) में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।

- इसका उद्देश्य उनके द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में योगदानों को प्रकाशित करना है।

अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में:

- यह अवसर अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और उनके नेतृत्व वाले रंपा विद्रोह की शताब्दी का प्रतीक है।
- माना जाता है कि अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश में 4 जुलाई, 1897 को हुआ था।
- कहा जाता है कि वह 18 वर्ष की आयु में सन्यासी बन गए थे।
- एक लड़के के रूप में, जब उन्होंने लोगों के दुखों के बारे में सुना और जाना कि आदिवासी ब्रिटिश शासन के अधीन पीड़ित

थे, तो वे बहुत परेशान हो गये।

- फिर, उन्होंने गंजम, विशाखापत्तनम और गोदावरी में पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ एक अत्यधिक प्रभावी गुरिल्ला युद्ध में बदल दिया।
- औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों की पारंपरिक पोडु (स्थानांतरण) खेती को खतरे में डाल दिया, क्योंकि सरकार ने वन भूमि को सुरक्षित करने की मांग की थी।
- 1882 के वन अधिनियम ने जड़ और पत्तियों जैसी छोटी वन उपज के संग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया।
  - ♦ इस प्रकार, आदिवासी लोगों को औपनिवेशिक सरकार की अधीनता के लिए मजबूर किया गया।
- तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी के विशाखापत्तनम-गोदावरी एजेंसी क्षेत्र में 1922-24 के रम्पा विद्रोह के रूप में युद्ध को प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है।
- अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचाने के बाद, उग्र क्रांतिकारी ने 1924 में 27 साल की छोटी उम्र में मातृभूमि की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
- अल्लूरी सीताराम राजू को "मन्यम वीरुडु" या "जंगल के नायक" के रूप में भी जाना जाता है।
- रम्पा विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन के साथ हुआ था।

मानगढ़ पहाड़ी

हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित करने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

- मानगढ़ पहाड़ी गुजरात-राजस्थान सीमा पर स्थित है।

In Image: Mangarh Hill

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ी एक आदिवासी विद्रोह का स्थल है जहां 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नरसंहार हुआ था।
- गोविन्द गुरु समुदाय के नेतृत्व में आयोजित सभा कर रहे आदिवासियों पर ब्रिटिश सेना ने गोलियां चलाईं।
- इस जगह को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है।

भील जनजाति के बारे में

- भीलों को राजस्थान के धनुष पुरुष के रूप में जाना जाता है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

- ♦ 'भील' नाम विल्लू या बिल्लू शब्द से बना है, जिसे द्रविड़ भाषा के अनुसार 'बो' के नाम से जाना जाता है।
- वे भारत में सबसे व्यापक रूप से वितरित आदिवासी समूह हैं।
- वे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जनजाति हैं।
- भीलों को मुख्य रूप से दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जाता है, केंद्रीय भील और पूर्वी या राजपूत भील।
- भील समुदाय में 1.7 करोड़ से अधिक आबादी (2013 में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार) शामिल है।
  - ♦ वे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और त्रिपुरा सहित भारतीय राज्यों में फैले हुए हैं।
- भीलों की संख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39 प्रतिशत है।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा में उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के बारे में

- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कार्यरत है।
- इसे प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष AMASR (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है।
- स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए NMA को कई कार्य सौंपे गए हैं।
- NMA की इन जिम्मेदारियों में से एक विनियमित क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधि के लिए आवेदकों को अनुमति देने पर विचार करना भी है।
- अधिनियम में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 पूर्णकालिक और 5 अंशकालिक सदस्यों के साथ NMA का गठन करने का प्रावधान है।

यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति

भारत को यूनेस्को के 2003 के सम्मेलन की अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है।

- यह सम्मेलन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए है और भारत का चयन 2022-2026 चक्र के लिए है।

प्रमुख बिंदु

- अंतरसरकारी समिति के चुनाव यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित 2003 के सम्मेलन की 9वीं महासभा के दौरान हुए थे।
- एशिया-प्रशांत समूह के भीतर रिक्त हो रही चार सीटों के लिए, छह देशों ने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की थी।
  - ♦ ये देश, भारत, बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड हैं।
- इस चुनाव में उपस्थित और मतदान कर रहे 155 मतदाताओं के 110 मत प्राप्त हुए।
- 2003 के कन्वेंशन की अंतरसरकारी समिति में 24 सदस्य हैं।
- सदस्यों का चुनाव सम्मेलन की आम सभा में समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व और रोटेशन के सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।
- समिति के सदस्य चार साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं।
- अंतरसरकारी समिति के कुछ मुख्य कार्यों में शामिल हैं:
  - ♦ कन्वेंशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देना,
  - ♦ सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना, और
  - ♦ अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के उपायों पर सिफारिशें करना।
- समिति सूची में अमूर्त विरासत के शिलालेख के लिए सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की भी जांच करती है।

- अतीत में, भारत ने इस कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के सदस्य के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए हैं।
  - ♦ एक 2006 से 2010 तक और दूसरा 2014 से 2018 तक।

नोटः भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की पुष्टि की थी।

- मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 14 शिलालेखों के साथ, भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी उच्च स्थान पर है।
- 2021 में दुर्गा पूजा के बाद, भारत ने 2023 में चर्चा के लिए गुजरात के गरबा के लिए नामांकन भी प्रस्तुत किया है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची- भारत

1. वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, 2008
2. रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, 2008
3. कुटियाट्टम, संस्कृत थियेटर, 2008
4. रमन, धार्मिक उत्सव और गढ़वाल हिमालय का अनुष्ठान थिएटर, 2009
5. मुदियेट्टू, केरल का अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक, 2010
6. राजस्थान के कालबेलिया लोक गीत और नृत्य, 2010
7. छऊ नृत्य, 2010
8. लद्दाख का बौद्ध जप, 2012
9. मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान गायन, ढोल नगाड़ा और नृत्य, 2013
10. जंडियाला गुरु, पंजाब के ठठेरों के बीच बर्तन बनाने का पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प, 2014
11. योग, 2016
12. नवरोज, 2016
13. कुंभ मेला, 2017
14. दुर्गा पूजा, 2021
15. गुजरात का गरबा (2023 में प्रस्तुत)

नए संसद भवन के शिखर पर स्थापित राष्ट्रीय चिह्न

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया।

- यह राष्ट्रीय प्रतीक कांसे से बना है जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है।
- इसे सहारा देने के लिए लगभग 6500 किलोग्राम वजन के स्टील की एक सहायक संरचना का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में

- राज्य प्रतीक सारनाथ में अशोक की लायन कैपिटल का एक रूपांतर है।
- अशोक स्तम्भ की ताजपोशी वाली लायन कैपिटल को पीले बलुआ पत्थर के एक ब्लॉक से उकेरा गया है और इसमें चार एशियाई शेर एक दुसरे से पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं- लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक के द्वि-आयामी प्रतिनिधित्व में केवल 3 को दर्शाया जाता है, क्योंकि चौथा सिंह दृश्य से छिपा हुआ है।
- अबेकस के फ्रेज (कैपिटल के बेस) में एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक बैल और एक शेर का अंकन किया गया हैं, जो धर्म चक्रों के बीच विशिष्ट रूप से दिखाई देता है।
- राष्ट्रीय प्रतीक के 2डी रूप में सामने की ओर केवल एक अशोक चक्र दिखाई देता है, जिसके बाईं ओर दौड़ता हुआ घोड़ा और दाईं ओर बैल होता है।
- वास्तविक लायन कैपिटल एक उल्टे कमल की आकृति पर बैठाया गया है जिसे राष्ट्रीय प्रतीक प्रतिनिधित्व में शामिल नहीं किया गया है।
- केंद्र में धर्म चक्र के साथ अबेकस पर सवार तीन शेरों को दिखाते हुए लायन कैपिटल की रूपरेखा और दायीं ओर बैल और बायीं ओर दौड़ता हुआ घोड़ा है।
    - ♦ 26 जनवरी 1950 को भारत के राज्य प्रतीक के रूप में दायीं और बायीं ओर धर्म चक्रों की रूपरेखा को अपनाया गया।
- आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' जिसका अर्थ है 'सत्य की सदैव जीत' जो लायन कैपिटल के प्रोफाइल के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है, भारत के राज्य प्रतीक का हिस्सा है।
    - ♦ यह मोटो 'मुंडको-उपनिषद' से लिया गया है।
- सारनाथ की सात फीट लंबी मूर्ति साहस, शक्ति और गर्व का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में 250 ईसा पूर्व में बनाया गया था।
- चारों शेरों को चारों दिशाओं - उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का संरक्षक कहा जाता है।
- वे चारों तरफ से एक चक्र से अलग किये गए हैं, जो बौद्ध धर्म के धर्मचक्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- प्रत्येक चक्र या पहिये में 24 तीलियाँ होती हैं। चक्र को बाद में राष्ट्रीय ध्वज के हिस्से के रूप में अपनाया गया था।
- जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, संविधान सभा ने सारनाथ स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में तय किया।
- यह महसूस किया गया कि स्तंभ स्वतंत्र राष्ट्र की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक होगा।
- 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में अशोक की लायन कैपिटल आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गई।
- प्रतीक भारत गणराज्य की मुहर का प्रतिनिधित्व करता है।

धम्मचक्क दिवस 2022

भारत के राष्ट्रपति ने 13 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के सारनाथ में धम्मचक्क दिवस 2022 समारोह को संबोधित किया।

- संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से अषाढ़ पूर्णिमा दिवस मना रहा है।

प्रमुख बिंदु

- धम्म दिवस, एक बौद्ध उत्सव उस दिन को चिह्नित करता है जब भगवान बुद्ध ने भारत के सारनाथ में हिरण पार्क में पांच तपस्वियों को अपना पहला उपदेश दिया था।
- आषाढ़ पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, यह वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के बाद बौद्ध अनुयायियों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पवित्र दिन है।

भगवान बुद्ध के अवशेष

मंगोलियाई बुद्ध पूर्णिमा समारोह के अवसर पर भगवान बुद्ध के चार पवित्र अवशेषों को 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया ले जाया जा रहा है।

- अवशेष उलानबटोर में गंदन मठ परिसर में बटसागान मंदिर में प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- चार अवशेष 22 बुद्ध अवशेषों में से आते हैं, जो वर्तमान में दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं।
- साथ में, उन्हें 'कपिलवस्तु अवशेष' के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे बिहार में एक ऐसे स्थान से हैं जिसे कपिलवस्तु का प्राचीन शहर माना जाता है।
- बौद्ध मान्यताओं के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया।
- कुशीनगर के मल्लों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार एक सार्वभौमिक राजा के अनुरूप समारोहों के साथ किया।
- अंतिम संस्कार से उनके अवशेष एकत्र किए गए और उन्हें आठ भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें निम्नलिखित में बांटा जाएगा:
- मगध के अजातशत्रु,
- वैशाली के लिच्छवी,
- कपिलवस्तु के शाक्य,
- कुशीनगर के मल्ल,
- अल्लकप्पा के बदमाश,
- पावा के मल्ल,
- रामग्राम के कोलिया और
- वेठदीप का एक ब्राह्मण।
- उद्देश्य पवित्र अवशेषों पर स्तूप खड़ा करना था।
- दो और स्तूप बने - एक कलश के ऊपर जिसमें अवशेष एकत्र किए गए थे और दूसरा अंगारों के ऊपर।
- बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर बने स्तूप (सरिरिका स्तूप) सबसे पहले जीवित बौद्ध तीर्थस्थल हैं।
- ऐसा कहा जाता है कि अशोक (272-232 ईसा पूर्व) ने बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी होने के कारण इन आठ स्तूपों में से सात स्तूप खोले।
- उन्होंने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के प्रयास में उनके द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों के भीतर अवशेषों का बड़ा हिस्सा एकत्र किया।

RAO'S ACADEMY

संत तुकाराम जी

प्रधानमंत्री ने पुणे में संत तुकाराम जी को श्रद्धांजलि दी।

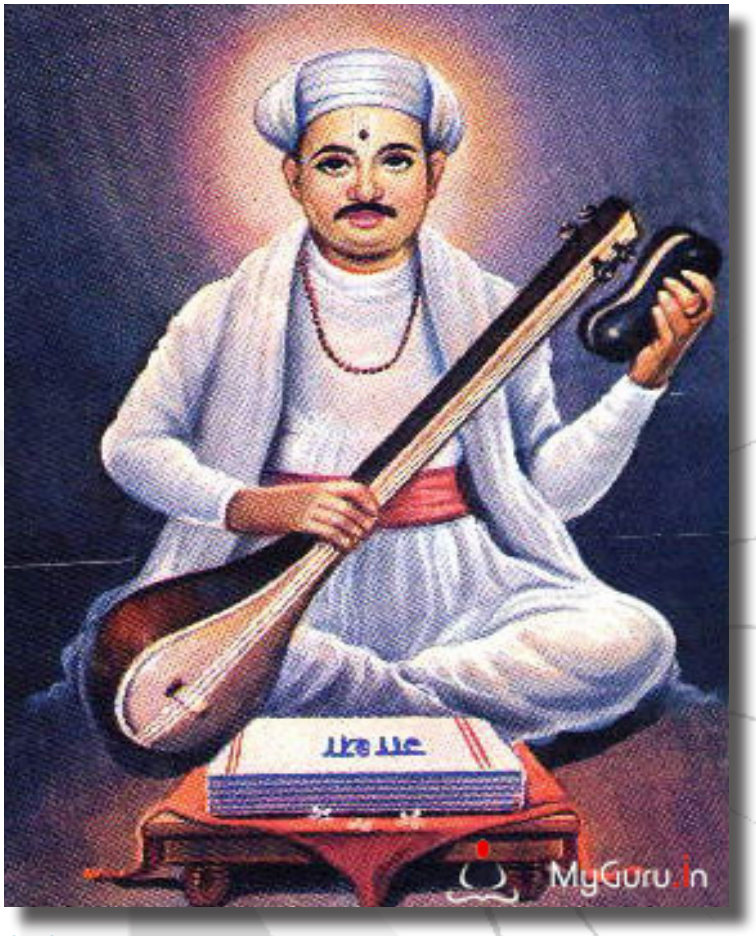

संत तुकाराम जी के बारे में

- संत तुकाराम अभंग का पूरा नाम तुकाराम बोल्होबा अम्बिले है।
- वे 17वीं शताब्दी के मराठी साहित्यकार थे, जिन्हें उनकी भक्ति कविता अभंग और कीर्तन के नाम से जाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के साथ समुदाय-उन्मुख पूजा के लिए जाना जाता था।
- उनकी कविता विट्ठल या विठोबा, हिंदू भगवान विष्णु के एक अवतार को समर्पित थी।
- संत तुकाराम अभंग ने साहस के साथ संसार के सभी सुख-दुख का सामना किया और विट्ठल के चरणों में अपना दृष्टिकोण स्थिर किया।

वारकरी आंदोलन के बारे में

- वारकरी हिंदू धर्म की भक्ति आध्यात्मिक परंपरा के भीतर एक धार्मिक आंदोलन (संप्रदाय) है।
- यह भौगोलिक रूप से भारतीय राज्यों महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक से जुड़ा हुआ है।
- महाराष्ट्र की मराठी भाषा में, वरी का अर्थ है 'तीर्थयात्रा' और एक तीर्थयात्री को वारकरी कहा जाता है।
- हर साल वारकरी सैकड़ों मील पैदल चलकर पवित्र नगरी पंढरपुर में एकादशी के दिन इकट्ठा होते हैं।
- वारकरी पंढरपुर के पीठासीन देवता विठोबा (विट्ठल के नाम से भी जाने जाते हैं) की पूजा करते हैं।
- विठोबा कृष्ण का एक रूप है, विष्णु का अवतार।
- विष्णु के साथ इस संबंध के कारण, वारकरी वैष्णववाद की एक शाखा है।
- अपने इतिहास के माध्यम से आंदोलन की स्थापना और समर्थन के लिए जिम्मेदार शिक्षकों में ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, चोखामेला शामिल हैं।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

बाबा बंदा सिंह बहादुर का शहादत दिवस

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 25 जून, 2022 को महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत का अवलोकन कर रहा है।

बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में

- बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म राजपूत परिवार (1670, राजौरी) में हुआ था।
- वह भारत के मुगल शासकों के खिलाफ आक्रामक युद्ध छेड़ने वाले और सिख क्षेत्र का विस्तार करने वाले पहले सिख सैन्य नेत्रत्वकर्ता थे।
- वे खालसा सेना का सेनापति थे उन्होंने मुगलों को हराकर उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को मुक्त कराया था।
- उसने पंजाब में खालसा शासन की स्थापना की।
- बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया और जमीन के जोतने वालों को संपत्ति के अधिकार प्रदान किए।
- उसे मुगल शासक फर्रुखसियर द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली लाया गया और सबसे अमानवीय तरीके से मार दिया गया।
  - ♦ यह शहादत महरौली में हुई जहां उनकी शहादत की याद में एक स्मारक स्थापित किया गया।
- वे गुरु गोविंद सिंह जी साहिब के एक महान और सच्चे शिष्य भी माने जातें हैं।

RAO'S ACADEMY

2 राजनीति

उप राष्ट्रपति चुनाव, 2022

भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना द्वारा, चुनाव आयोग ने उप-राष्ट्रपति चुनाव के लिए घोषणा की है।

भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में

- उपराष्ट्रपति का देश में दूसरा सर्वोच्च पद होता है।
- उन्हें वरीयता के आधिकारिक वारंट में राष्ट्रपति के बाद एक रैंक दिया गया है।

चुनाव

- उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तरह, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति से चुना जाता है।
- वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं।
- इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं।
- इस प्रकार, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है।

योग्यता

उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए, एक व्यक्ति की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए :

- वह भारत का नागरिक हो।
- 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए।
- उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए।

नोट: उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।

कार्यालय की अवधि:

- उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
- हालांकि, वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
- उन्हें कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया भी जा सकता है।
- उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।
- उसे पूर्ण बहुमत (अर्थात् सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) द्वारा पारित राज्य सभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जा सकती है।
- विशेष रूप से, उन्हें हटाने के लिए संविधान में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।
- वह उस पद के लिए पुन: निर्वाचन के लिए भी पात्र है। वह किसी भी अवधि के लिए चुने जा सकते हैं।

नोट: उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

शक्तियां और कार्य

उपराष्ट्रपति के कार्य दो प्रकार के होते हैं:

- वह राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस क्षमता में, उसकी शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान हैं।
- वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब राष्ट्रपति के कार्यालय में उनके इस्तीफे, हटाने, मृत्यु या अन्यथा के कारण कोई रिक्ति होती है।

नोट: वह केवल छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है जिसके भीतर एक नया राष्ट्रपति चुना जाना है।

- राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए, उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 63: भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति का राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होना।
- अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना।
- अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का चुनाव।

राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

हाल ही में राष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्यसभा के लिए नए सदस्यों को मनोनीत किया।

प्रमुख बिंदु:

- संविधान का अनुच्छेद 80 ("राज्यों की परिषद की संरचना") कहता है, ष्राज्यों की परिषद में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले बारह सदस्य होंगे।
- राष्ट्रपति इस प्रकार कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है।
- नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे का तर्क यह है कि चुनाव की प्रक्रिया से गुजरे बिना प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा में स्थान प्रदान किया जाए।
- नए मनोनीत सदस्य हैं:

1. संगीतकार इलैयाराजा,
2. ट्रैक-एंड-फील्ड आइकन पीटी उषा,
3. तेलुगु पटकथा लेखक वी विजयेंद्र प्रसाद, और
4. परोपकारी और आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश ने फसल बीमा योजना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में फिर से शामिल होने का फैसला किया है।

- आंध्र प्रदेश उन छह राज्यों में से एक था, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में इस योजना के कार्यान्वयन को रोक दिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में:

- प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई थी।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

- इस प्रमुख योजना को एक राष्ट्र-एक योजना के अनुरूप तैयार किया गया था।
- यह तीन पुरानी पहलों की जगह लेता है-
  - ♦ संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस),
  - ♦ मौसम आधारित फसल बीमा योजना और
  - ♦ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS)
- यह योजना कृषि मंत्रालय के तहत कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रशासित की जा रही है।
- **उद्देश्य:**
  - ♦ फसल की विफलता, क्षति और हानि के खिलाफ वहनीय व्यापक बीमा कवर प्रदान करना।
  - ♦ कुल बोए गए क्षेत्र को कवर करने पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ फसल बीमा का विस्तार करना।
  - ♦ किसान की आय को स्थिर करना और कृषि उत्पादन में स्थिरता सुनिश्चित करना।
  - ♦ कृषि क्षेत्र को ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना।
  - ♦ किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

योजना का विवरण

- सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम होगा।
- वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में, किसानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम केवल 5% होगा।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 90% है तो भी यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  - ♦ 95-98.5% बीमांकिक प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है और 1:1 के अनुपात में साझा किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी के उपयोग को काफी हद तक प्रोत्साहित किया जाएगा।
  - ♦ किसानों को दावा भुगतान में देरी को कम करने के लिए फसल कटाई के आंकड़ों को पकड़ने और अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग किया जाएगा।
  - ♦ फसल काटने के प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा।
- मौसम के दौरान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान, जिनका फसल में बीमा योग्य हित है, पात्र हैं।
- खरीफ 2020 सीजन तक, इस योजना के तहत किसानों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए नामांकन अनिवार्य था:
  - ♦ अधिसूचित क्षेत्र के किसान जिनके पास फसल ऋण खाता/केसीसी खाता है (जिन्हें ऋणी किसान कहा जाता है)।

RAO'S ACADEMY YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

- ♦ ऐसे अन्य किसान जिन्हें सरकार समय-समय पर शामिल करने का निर्णय ले।
- ऊपर कवर न किए गए सभी किसानों द्वारा स्वैच्छिक कवरेज प्राप्त किया जा सकता है।
- **योजना के अंतर्गत शामिल जोखिम:**
  - ♦ प्राकृतिक आग और बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, तूफान, तूफान जैसे गैर-रोकथाम योग्य जोखिमों के कारण उपज के नुकसान को कवर करने के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है।
  - ♦ बाढ़ और भूस्खलन, सूखा, शुष्क काल, कीट/बीमारियों के कारण होने वाले जोखिमों को भी कवर किया जाएगा।

नोट: जब 2016 में योजना शुरू की गई थी, तब कुल 5.8 करोड़ किसानों का बीमा किया गया था, जिसमें 75% किसानों को अनिवार्य कवरेज प्राप्त हुआ था और 25% किसानों ने स्वेच्छा से बीमा का विकल्प चुना था।

पीएमएफबीवाई के लिए संशोधित दिशानिर्देश:-

सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए परिचालन दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।

- "अधिसूचित क्षेत्रों" में "अधिसूचित फसलें" उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार किसानों सहित सभी किसान अब कवरेज के लिए पात्र हैं।
- प्रारंभ में, यह योजना ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी; फरवरी 2020 में केंद्र ने इसे सभी किसानों के लिए वैकल्पिक बनाने के लिए संशोधित किया।
- केंद्र ने अपनी प्रीमियम सब्सिडी को असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% (मौजूदा असीमित से) तक सीमित करने का निर्णय लिया।
  - ♦ पहले, केंद्रीय सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी।
- ओलावृष्टि, भूस्खलन और बाढ़ के अलावा स्थानीय आपदाओं में बादल फटना और प्राकृतिक आग को शामिल करना।
- बेमौसम और चक्रवाती बारिश के अलावा फसल के बाद के नुकसान में ओलावृष्टि को शामिल करना
- राज्यों के लिए दंड/प्रोत्साहन का प्रावधान।

As per the data released by the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare under the Ministry of Agriculture, the annual breakdown of value of insurance packages, share in premiums, claims filed, and claims settled are as follows:

Financial Year	Amount Insured (Rs. crore)	Farmers' Share in Premium (Rs. crore)	Govt.'s Share in Premium (Rs. crore)	Claims Filed (Rs. crore)	Claims Paid (Rs. crore)
2016-17	203,120	4,042	17,531	16,773	16,759
2017-18	202,267	4,189	20,463	22,118	22,114
2018-19	230,061	4,853	24,504	28,941	28,004
2019-2020^	142,969	3,018	20,524	20,975	20,090

PMFBY के तहत डेटा अपडेट:

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बीमा पैकेजों के मूल्य, प्रीमियम में हिस्सेदारी, दायर किए गए दावों और निपटान किए गए दावों का वार्षिक विवरण इस प्रकार है:-

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23:

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) किश्तों में जारी करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- सॉवरेन गोल्ड बांड (एसजीबी) की बिक्री निम्नलिखित माध्यमों से की जाएगी:
  - ♦ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर),
  - ♦ स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL),
  - ♦ भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल),
  - ♦ नामित डाकघर,
  - ♦ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड।

योजना की विशेषताएं :

- जारी करना- भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाना है।
- पात्रता- SGB निवासी व्यक्तियों, एचयूएफ, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।
- मूल्यवर्ग- SGB को एक ग्राम की मूल इकाई के साथ सोने के ग्राम (ग्रामों) के गुणकों में मूल्यांकित किया जाएगा।
- अवधि- SGB की अवधि आठ वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसमें 5वें वर्ष के बाद समय से पहले रिडेम्पशन के विकल्प का प्रयोग उस तारीख को किया जाएगा जिस पर ब्याज देय है।
- न्यूनतम आकार- न्यूनतम अनुमेय निवेश एक ग्राम सोना होगा।
- अधिकतम सीमा- सदस्यता की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, HUF के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम होगी।
  - ♦ इस आशय की एक स्व-घोषणा प्राप्त की जाएगी।
  - ♦ वार्षिक सीमा में वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न किश्तों के तहत सब्सक्राइब किए गए एसजीबी और सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए एसजीबी शामिल होंगे।
- ज्वाइंट होल्डर- ज्वाइंट होल्डिंग के मामले में 4 KG की निवेश सीमा पहले आवेदक पर ही लागू होगी।
- निर्गम मूल्य- SGB का मूल्य 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपये में तय किया जाएगा।
  - ♦ यह कॉस्टिंग इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा सदस्यता अवधि से पहले के सप्ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए प्रकाशित की जाती है।
  - ♦ ऑनलाइन सदस्यता लेने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों के लिए SGB का निर्गम मूल्य 50 प्रति ग्राम कम होगा।
- भुगतान विकल्प- SGB के लिए भुगतान नकद भुगतान (अधिकतम 20,000 तक) या डिमांड ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
- जारी करने का फॉर्म- SGB को सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किया जाएगा।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

इसके लिए निवेशकों को होल्डिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

- ♦ एसजीबी डीमैट रूप में रूपांतरण के लिए पात्र होंगे।

- मोचन मूल्य- आईबीजेए लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पिछले तीन कार्य दिवसों के 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर मोचन मूल्य भारतीय रुपये में होगा।
- ब्याज दर - निवेशकों को नाममात्र मूल्य पर अर्ध-वार्षिक रूप से देय 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की निश्चित दर पर मुआवजा दिया जाएगा।
- संपार्श्विक- बांडों का उपयोग ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में किया जा सकता है।
  - ♦ ऋण-से-मूल्य (LTV) अनुपात समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य सामान्य स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाना है।
- कर उपचार- SGB पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के प्रावधान के अनुसार कर योग्य होगा।
  - ♦ किसी व्यक्ति को SGB के मोचन पर उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ कर में छूट है।
  - ♦ बांड के हस्तांतरण पर किसी भी व्यक्ति को होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के लिए इंडेक्सेशन लाभ प्रदान किया जाएगा।
- ट्रेडेबिलिटी - SGB ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
- SLR पात्रता- बैंकों द्वारा केवल ग्रहणाधिकार/दृष्टिबंधक/प्रतिज्ञा लागू करने की प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित किए गए SGB की गणना सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) में की जाएगी।

RAO'S ACADEMY

3 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना

भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र अब तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में पूरी तरह से कार्यरत है।

- 100 मेगावाट (मेगावाट) की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चालू किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- रामागुंडम में 100 मेगावाट सौर पीवी परियोजना के संचालन के साथ, दक्षिणी क्षेत्र में फ्लोटिंग सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया।
- इससे पहले, NTPC ने निम्नलिखित के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की थी:
  - ♦ कायमकुलम (केरल) में 92 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर।

♦ सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) में 25 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर।

- रामागुंडम में 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना उन्नत तकनीक के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से लैस है।

ऐसे सौर संयंत्रों के लाभ

- पर्यावरण के दृष्टिकोण से, सबसे स्पष्ट लाभ न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है जो ज्यादातर संबद्ध निकासी व्यवस्था के लिए है।
- इसके अलावा, तैरते सौर पैनलों की उपस्थिति से, जल निकायों से वाष्पीकरण दर कम हो जाती है, इस प्रकार जल संरक्षण में मदद मिलती है।
- प्रति वर्ष लगभग 32.5 लाख क्यूबिक मीटर पानी के वाष्पीकरण से बचा जा सकता है।
- सौर मॉड्यूल के नीचे का जल निकाय उनके परिवेश के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे उनकी दक्षता और उत्पादन में सुधार होता है।
- इसी तरह, जबकि प्रति वर्ष 1,65,000 टन कोयले की खपत से बचा जा सकता है और प्रति वर्ष 2,10,000 टन के कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से बचा जा सकता है।

मिट्टी से बना नॉन-इलेक्ट्रिक कूलिंग कैबिनेट

भारतीय मानक ब्यूरो (BSI), भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय ने 'मिट्टी से बने गैर-विद्युत शीतलन कैबिनेट' के लिए एक भारतीय मानक, आईएस 17693: 2022 विकसित किया है।

- 'मिट्टीकूल रेफ्रिजरेटर' के रूप में नामित, गुजरात के श्री मनसुख भाई प्रजापति रेफ्रिजरेटर के पीछे नवप्रवर्तनक हैं जो एक पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का प्रोजेक्ट करता है।

प्रमुख बिंदु

- BSI मानक मिट्टी से बने कूलिंग कैबिनेट के निर्माण और प्रदर्शन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है।
- यह वाष्पीकरणीय शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- इन अलमारियाँ का उपयोग बिजली की आवश्यकता के बिना खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को स्टोर करने के

लिए किया जा सकता है।

- यह मानक BSI को 17 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में से 6 को पूरा करने में मदद करता है जैसे-
  - ♦ गरीबी नहीं, शून्य भूख, लैंगिक समानता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, और जिम्मेदार खपत और उत्पादन।
- यह एक प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर है जो मुख्य रूप से मिट्टी से सब्जियों, फलों, दूध को स्टोर करने और पानी को ठंडा करने के लिए बनाया जाता है।
- यह बिना किसी बिजली की आवश्यकता के इसमें संग्रहीत खाद्य पदार्थों को प्राकृतिक शीतलता प्रदान करता है।
- फलों, सब्जियों और दूध को उनकी गुणवत्ता को खराब किए बिना उचित रूप से ताजा रखा जा सकता है।
- यह मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति, परंपरा और विरासत को पुनर्जीवित करने में भी प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है।
- **संभावित लाभ:**
  - ♦ स्थायी खपत को बढ़ावा देना;
  - ♦ निर्धन समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना;
  - ♦ हरी और ठंडी धरती की दिशा में काम करना,
  - ♦ आर्थिक विकास और रोजगार सृजन; तथा
  - ♦ अंततः ग्रामीण महिलाओं के उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में योगदान देना।

मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस

मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जून को आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र दिवस है।

- इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है।

मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के उद्देश्य हैं:

- मुद्दे के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना।
- लोगों को यह बताना कि मरुस्थलीकरण और सूखे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।
  - ♦ इस उद्देश्य के मुख्य साधन सभी स्तरों पर मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सहयोग में निहित है।

- विशेष रूप से अफ्रीका में गंभीर सूखे और/या मरुस्थलीकरण का सामना कर रहे देशों में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कार्यान्वयन को मजबूत करना।
- स्पेन मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 का मेजबान देश है।
- सूखा, विनाशकारी परिणामों को रोकने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई पर ध्यान देने के साथ, मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 का विषय है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- विश्व स्तर पर, 23 प्रतिशत भूमि अब उत्पादक नहीं है।
- 75 प्रतिशत को उसकी प्राकृतिक अवस्था से बदल दिया गया है, ज्यादातर कृषि के लिए।
- भूमि उपयोग में यह परिवर्तन मानव इतिहास में किसी भी समय की तुलना में तेज गति से हो रहा है और पिछले 50 वर्षों में इसमें तेजी आई है।
- पिछले दो दशकों (WMO 2021) की तुलना में 2000 से सूखे की संख्या और अवधि में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
    - ♦ जबकि 2.3 अरब से अधिक लोग पहले से ही पानी के संकट का सामना कर रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़ी समस्या है।
- हम में से अधिक से अधिक लोग पानी की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में रह रहे होंगे, जिसमें 2040 तक चार बच्चों में से एक अनुमानित (यूनिसेफ) शामिल है।
- अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 5.5 करोड़ लोग सूखे से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं।
- 2050 तक, सूखा विश्व की तीन-चौथाई आबादी को प्रभावित कर सकता है।
- 1900 और 2019 के बीच, सूखे ने दुनिया में 2.7 बिलियन लोगों को प्रभावित किया और 11.7 मिलियन लोगों की मौत हुई।

मरुस्थलीकरण क्या है?

- मरुस्थलीकरण शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण है।
- यह मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है।
- मरुस्थलीकरण का तात्पर्य मौजूदा मरुस्थलों के विस्तार से नहीं है।
- ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र, जो दुनिया के एक तिहाई भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, अतिदोहन और अनुपयुक्त भूमि उपयोग के लिए बेहद संवेदनशील हैं।
- गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और खराब सिंचाई प्रथाएं सभी भूमि की उत्पादकता को कम कर सकती हैं।

UNCCD के बारे में

मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD), 1994 में अपनाया गया था।

- यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है।
- कन्वेंशन विशेष रूप से शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिन्हें शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है।
- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के दलों के सम्मेलन (सीओपी 14) का चौदहवां सत्र भारत में आयोजित किया गया था।
- नया UNCCD 2018-2030 रणनीतिक ढांचा भूमि क्षरण तटस्थता (LDN) प्राप्त करने के लिए सबसे व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धता है।

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन

CPCB ने 30 जून, 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक (SUP) वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक उपाय किए हैं।

प्रमुख बिंदु

- अपनी व्यापक कार्य योजना के हिस्से के रूप में CPCB के बहु-आयामी दृष्टिकोण में एसयूपी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:
  - ♦ कच्चे माल की आपूर्ति को कम करने के लिए,
  - ♦ प्लास्टिक की मांग को कम करने के लिए मांग पक्ष के उपाय,
  - ♦ एसयूपी के विकल्पों को बढ़ावा देने के उपायों को सक्षम बनाना,
  - ♦ कुशल निगरानी और जागरूकता पैदा करने के लिए डिजिटल हस्तक्षेप, और
  - ♦ निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य बोर्डों को मार्गदर्शन।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्लूएम) नियम, 2016 के अनुसार, प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है।
  - ♦ गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए पाउच के उपयोग पर प्रतिबंध है।
- पीडब्लूएम (संशोधित) नियम, 2021 के अनुसार,
  - ♦ पचहत्तर माइक्रोन से कम के नव या पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बने कैरी बैग का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, 12 अगस्त 2021 की अधिसूचना, निम्नलिखित चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करती है:
  - ♦ प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियाँ, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे,
  - ♦ सजावट के लिए कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन [थर्मोकोल];
  - ♦ प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग या मिठाई बक्से के चारों ओर फिल्म पैक करना,
  - ♦ निमंत्रण कार्ड, और सिगरेट के पैकेट, प्लास्टिक या पीवीसी बैनर 100 माइक्रोन से कम, स्टिरर।
- चिन्हित वस्तुओं की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं।
  - ♦ उदाहरण के लिए, सभी प्रमुख पेट्रोकेमिकल उद्योग प्रतिबंधित एसयूपी उत्पादन में लगे उद्योगों को प्लास्टिक कच्चे माल की आपूर्ति नहीं करते हैं।

- ♦ सीमा शुल्क प्राधिकरण को प्रतिबंधित एसयूपी वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए कहा गया है।
- मौजूदा आपूर्ति के विकल्प के रूप में, एसयूपी के विकल्प को बढ़ावा देने के उपायों को सक्रिय रूप से अपनाया जा रहा है।
- CPCB ने कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के लगभग 200 निर्माताओं को पहले ही एकमुश्त प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।
  - ♦ इन प्रमाणपत्रों को नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है जो सरकार की व्यापार करने में आसानी की नीति के अनुरूप है।
- इसके अलावा, इन विनिर्माताओं के प्रमाणन की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
- MSMEs को समर्थन देने के लिए, CPCB, CIPET के सहयोग से MSMEs के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।
- मांग पक्ष पर ई-कॉमर्स कंपनियों, प्रमुख सिंगल यूज प्लास्टिक विक्रेताओं/उपयोगकर्ताओं और प्लास्टिक कच्चे माल के निर्माताओं को निर्देश जारी किए गए हैं।
  - ♦ यह पहचान की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में है।
- नागरिकों की भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए, एक SUP लोक शिकायत ऐप भी लॉन्च किया गया है।

CPCB के बारे में

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एक सांविधिक संगठन है।
- इसका गठन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत सितंबर, 1974 में किया गया था।
- इसके अलावा, CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे।
- यह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने और समुद्र के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए विज्ञान आधारित समाधान खोजने का एक अनूठा अवसर है।

- सम्मेलन की सह-मेजबानी पुर्तगाल और केन्या द्वारा की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- दुनिया भर के 130 से अधिक देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता खोजने के लिए पांच दिनों तक विचार-विमर्श करेंगे।
- महासागर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ रहा है क्योंकि दुनिया एसडीजी लक्ष्य 14 को प्राप्त करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश कर रही है।
  - ♦ SDG लक्ष्य 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कहता है।
- सम्मेलन का समग्र विषय है: "लक्ष्य 14 के कार्यान्वयन के लिए विज्ञान और नवाचार पर आधारित समुद्री कार्रवाई को बढ़ाना: स्टॉकटेकिंग, साझेदारी और समाधान।"
- महासागर संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहलें:
  - ♦ समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) का उचित कार्यान्वयन।
  - ♦ 2030 तक कम से कम 30% महासागर की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध होना।
  - ♦ राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे समुद्री क्षेत्रों में गहरे समुद्र में खनिज दोहन पर रोक लगाने का आह्वान करना।
  - ♦ समुद्री और तटीय प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) में निवेश बढ़ाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए।
  - ♦ प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर बातचीत करना।
  - ♦ प्रभावी प्रबंधन और नीतियों को सूचित करने के आधार के रूप में महासागर विज्ञान को बढ़ावा देना।
  - ♦ सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए।
  - ♦ संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान के एक दशक (2021-2030) की भी घोषणा की है।

नोट: पहला संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित हुआ था।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

4 अर्थव्यवस्था

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)

दूरसंचार विभाग यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के तहत पायलट परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा।

- दूरसंचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग ने भारतीय टेलीफोन उद्योग (ITI) लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- समझौता ई-बैंड, एलटीई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की पायलट परियोजनाओं को निधि देने के लिए है जिसमें सी-डॉट कोर के साथ 4G/5G प्रोटोटाइप का एकीकरण शामिल है।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) के बारे में

नई दूरसंचार नीति - 1999 (NTP'99) ने प्रावधान किया कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (USO) को पूरा करने के लिए संसाधन 'यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (ULL)' के माध्यम से जुटाए जाएंगे।

- यह विभिन्न लाइसेंसों के तहत ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व का एक प्रतिशत होगा।
- यूनिवर्सल सर्विस सपोर्ट पॉलिसी 01.04.2002 से लागू हुई।
- भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को वैधानिक दर्जा दिया।
- **उद्देश्य:**
  - ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी अछूते क्षेत्रों को सार्वभौमिक सेवा के प्रावधानों के बीच संतुलन प्रदान करना।
  - देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम उच्च स्तरीय सेवाएं प्रदान करना, और
  - देश के दूरस्थ, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।
- यह एक गैर-व्यपगत निधि है, अर्थात, लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च नहीं की गई राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिए अर्जित की जाती है।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अनुसार, इस निधि का उपयोग विशेष रूप से सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाना है।
- यह निधि भारत की संचित निधि में जमा की जाती है और भारतीय संसद के अनुमोदन पर भेजी जाती है।

एंजेल फंड के लिए नियामक ढांचा

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) ने IFSCA (फंड प्रबंधन) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया था।

- यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के अपने जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए था।

प्रमुख बिंदु

उक्त ढांचे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- IFSC में एक फंड मैनेजमेंट एंटिटी (FME) एंजेल फंड लॉन्च करने में सक्षम होगी।

यह एक ग्रीन चौनल के तहत प्राधिकरण के साथ एक नियुक्ति ज्ञापन दाखिल करके किया जा सकता है।

इसका मतलब यह है कि प्राधिकरण के साथ प्लेसमेंट ज्ञापन दाखिल करने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा योजनाएँ सदस्यता के

लिए खोली जा सकती हैं।

- एंजेल फंड मान्यता प्राप्त निवेशकों या निवेशकों से निवेश स्वीकार करेंगे जो 5 वर्षों में कम से कम 40,000 अमेरिकी डॉलर देने के इच्छुक हैं।
- एंजेल फंड को IFSC, भारत में स्टार्ट-अप के साथ-साथ अन्य विनियमित एंजेल योजनाओं में निवेश करने की अनुमति है।
- एक एंजेल फंड द्वारा एक स्टार्ट-अप में निवेश की सीमा 1,500,000 अमेरिकी डॉलर है।
  - ♦ हालांकि, एंजेल फंड को स्टार्ट-अप द्वारा फंड जुटाने के बाद के दौर में निवेश करने की अनुमति है।
  - ♦ यह कुछ शर्तों के अधीन, इसकी शेयरधारिता को कमजोर पड़ने से बचाने के लिए किया गया है।

एंजेल निवेशक क्या हैं?

एक एंजेल निवेशक आमतौर पर एक उच्च-निवल-मूल्य वाला व्यक्ति होता है जो शुरुआती चरणों में स्टार्टअप को धन देता है।

- एंजेल निवेशक को निजी निवेशक, बीज निवेशक या एंजेल फंडर के रूप में भी जाना जाता है।
- एक एंजेल निवेशक छोटे स्टार्टअप या उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है (आमतौर पर कंपनी में स्वामित्व इक्विटी के बदले)।

MSDE ने DBT योजना शुरू की

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS) प्रत्यक्ष लाभार्थी स्थानांतरण (DBT) योजना का एक हिस्सा होगी।

- NAPS में DBT सभी प्रशिक्षुओं को सीधे सरकारी लाभ प्रदान करने में मदद करेगा।

प्रमुख बिंदु

- पहले कंपनियां प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थीं और फिर सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग करती थीं।
- DBT योजना के शुभारंभ के साथ, सरकार अपने योगदान को सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर देगी।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (NAPS) के बारे में

- वित्तीय प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और समर्थन प्रदान करके देश में शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 2016 में NAPS शुरू किया गया था।
- योजना के अनुसार, भारत सरकार निर्धारित वजीफा का 25% हिस्सा अधिकतम नियोक्ताओं के साथ प्रति प्रशिक्षु 1500 रू. प्रति माह प्रदान किया जाएगा ।
- भारत सरकार बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ बुनियादी प्रशिक्षण की लागत के रूप में प्रति फ्रेशर अपरेंटिस अधिकतम 7500 रुपये भी साझा करेगी।
- 1 अक्टूबर, 2016 से पहले प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को केवल 1 अक्टूबर, 2016 से योजना का लाभ मिलेगा।
- राज्य शिक्षुता सलाहकार (SAA) और क्षेत्रीय शिक्षुता निदेशालय (RDAT) अपने-अपने राज्यों/क्षेत्रों में कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे।
- उद्देश्य: शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और 2020 तक प्रशिक्षुओं की व्यस्तता को वर्तमान 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना।
- बजट 2021 में सरकार ने प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 3000 करोड़ रुपये।

RAO'S ACADEMY

राज्यों के अभ्यास 2021 की रैंकिंग

स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए गए।

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) 2018 से राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग अभ्यास का आयोजन कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- रैंकिंग के प्रयोजनों के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात,
  - ♦ सर्वश्रेष्ठ कलाकार,
  - ♦ शीर्ष कलाकार,
  - ♦ नेताओं,
  - ♦ आकांक्षी नेता और
  - ♦ उभरते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र।
- गुजरात और कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे, जिसमें दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल था।
- मेघालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी (NE-) राज्यों में शीर्ष सम्मान जीता।
- जबकि केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना को राज्यों में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता का पुरस्कार मिला;
  - ♦ केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू और कश्मीर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा।
- असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को राज्यों में नेता वर्ग में विजेता घोषित किया गया;
  - ♦ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ने केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में नेताओं का सम्मान हासिल किया।
- छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान को राज्यों में आकांक्षी नेता घोषित किया गया।
- चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के आकांक्षी नेता थे।
- राज्यों की श्रेणी से आंध्र प्रदेश और बिहार और केंद्र शासित प्रदेशों/पूर्वोत्तर राज्यों से मिजोरम और लद्दाख को इमर्जिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के तहत क्लब किया गया था।

नोट: राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग अभ्यास का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में सहायता करना और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना है।

- पिछले तीन संस्करणों में इस अभ्यास का प्रभाव बढ़ा है, जिसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस संस्करण में भाग लिया है, जो अब तक का सबसे अधिक है।

NICDP के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण

हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) की गतिविधियों की समीक्षा के लिए गठित शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की पहली बैठक हुई।

- शीर्ष निगरानी प्राधिकरण का नेतृत्व वित्त मंत्री करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- शीर्ष निगरानी प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ♦ वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में,
  - ♦ प्रभारी मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्री,
  - ♦ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, जहाजरानी मंत्री,

- ♦ उपाध्यक्ष, नीति आयोग, और
- ♦ संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री।

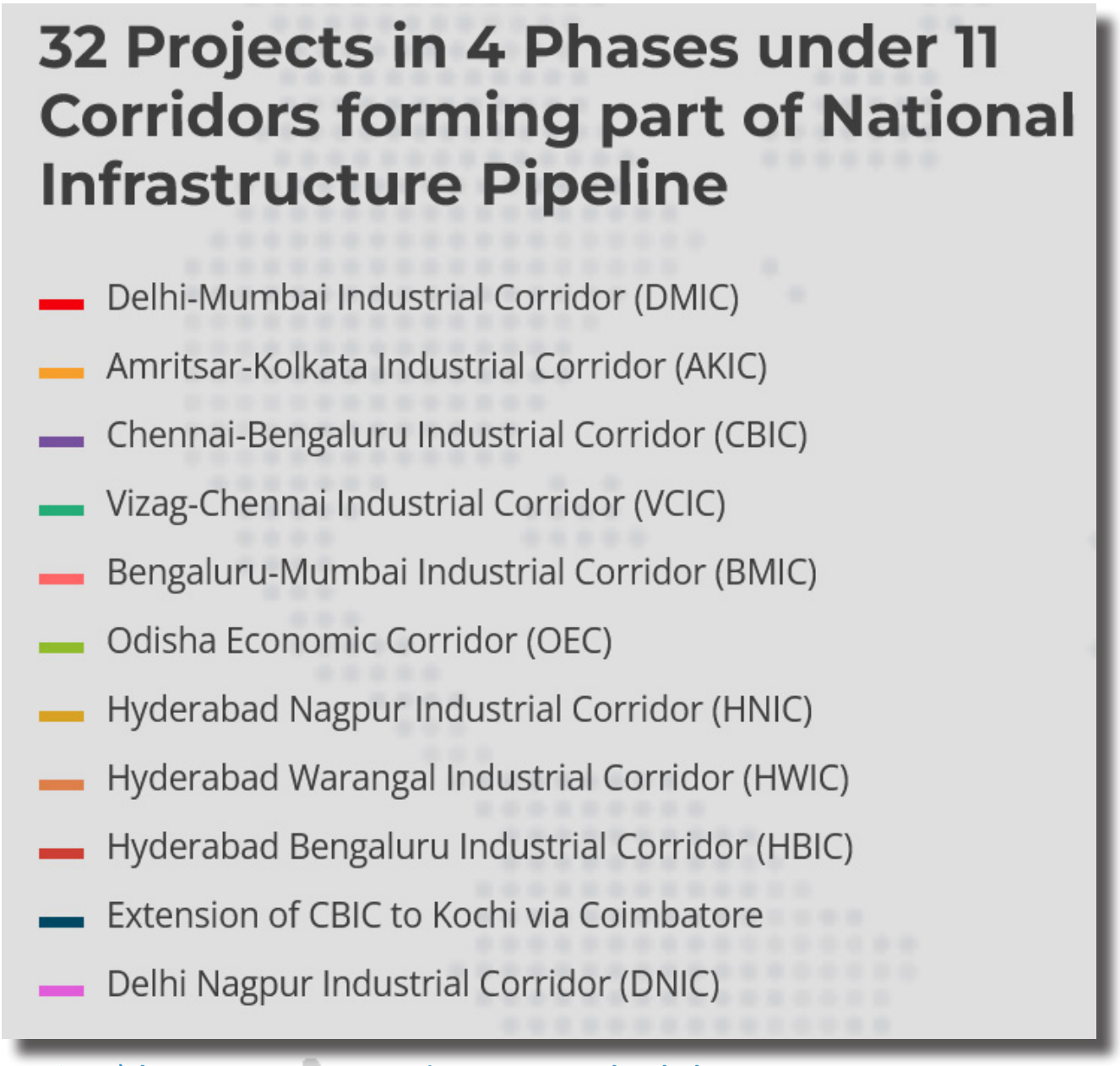

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के बारे में

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट सिटी" के रूप में विकसित करना है।

- यह बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को परिवर्तित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना है। ताकि वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
- इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास होगा जिससे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
- सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम (NICP) के हिस्से के रूप में चार चरणों में 32 परियोजनाओं के साथ 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को मंजूरी दी है।

RAO'S ACADEMY

- दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा 2011 में विकास के लिए लिया गया पहला गलियारा था।
- इसके बाद, अन्य औद्योगिक गलियारे अर्थात अमृतसर-कोलकाता, चेन्नई-बेंगलुरू, विजाग-चेन्नई, पूर्वी तट आदि को NICP की छत्रछाया का हिस्सा बनने के लिए जोड़ा गया।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के तहत, 2024-25 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए 111 लाख करोड़ रूपये के निवेश की अनुमानित की आवश्यकता है।
- NICP का व्यापक उद्देश्य बड़े पैमाने पर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए प्लग एंड प्ले ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना है।
- DPIIT के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) कार्यक्रम को लागू करने के लिए व्यापक संस्थागत ढांचा है।

विदेशी खरीद के लिए निजी क्षेत्र के बैंक

डवक ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है।

- यह वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी व्यवसाय के आवंटन को और खोलने के अनुरूप है।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा मंत्रालय ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को मंत्रालय द्वारा विदेशी खरीद के लिए साख पत्र और प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण व्यवसाय प्रदान करने के लिए सौंपा है।
  - ♦ निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक हैं।
- अब तक, रक्षा मंत्रालय को ये सेवाएं प्रदान करने के लिए केवल अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ही उपयोग किया जाता था।
- इसके साथ पहली बार तीन निजी बैंकों को भी रक्षा मंत्रालय द्वारा विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
- इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।

लेटर ऑफ क्रेडिट (साख पत्र) क्या है?

- साख पत्र अनिवार्य रूप से एक बैंक, एक बैंक के ग्राहक और एक लाभार्थी के बीच एक वित्तीय अनुबंध है।
- आम तौर पर एक आयातक के बैंक द्वारा जारी किया जाता है, साख पत्र की शर्तों को पूरा करने के बाद लाभार्थी को क्रेडिट गारंटी के पत्र का भुगतान किया जाएगा।
- साख पत्र अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार उद्योग के भीतर उपयोग किए जाते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में जोखिम को कम करता है जहां खरीदार और विक्रेता एक दूसरे को नहीं जानते हैं।
- यदि आप एक निर्यातक हैं तो क्रेडिट पत्र बीमा है यदि खरीदार आपके द्वारा भेजे गए माल के लिए भुगतान करने में विफल रहता है। ऐसे मामले में, वित्तीय संस्थान बकाया राशि को कवर करेगा।
- निर्यातकों के लिए, आपके ऑर्डर को भरने में आपकी मदद करने के लिए कार्यशील पूंजी ऋणों के प्रति संपार्श्विक के रूप में ऋण पत्र भी गिरवी रखा जा सकता है।

विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) 12 से 17 जून 2022 तक जिनेवा में WTO मुख्यालय में हुआ।

- सम्मेलन की सह-मेजबानी कजाकिस्तान ने की।

प्रमुख बिंदु

- हानि पहुंचाने वाले मत्स्य पालन सब्सिडी को कम करने पर समझौता,
- विश्व व्यापार संगठन ने एक बहुपक्षीय समझौता पारित किया जो अगले चार वर्षों के लिए अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर 'हानिकारक' सब्सिडी पर अंकुश लगाएगा।

- ♦ 2001 से, सदस्य राज्य अत्यधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।
- ♦ मौजूदा समझौता, जो नए व्यापार नियम स्थापित करता है, विश्व व्यापार संगठन के इतिहास में दूसरा बहुपक्षीय समझौता है।

- भारत और अन्य विकासशील देश इस समझौते में कुछ रियायतें हासिल करने में सफल रहे।
  - ♦ उन्होंने प्रस्ताव के एक हिस्से को हटाने के लिए सफलतापूर्वक पैरवी की जिससे कुछ सब्सिडी को खतरा हो सकता था।
  - ♦ इन सब्सिडी का उद्देश्य छोटे पैमाने पर कारीगर मछली पकड़ने में सहायता करना था।

वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर समझौता

- सदस्य संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए भोजन को किसी भी निर्यात प्रतिबंध से छूट देने के लिए एक बाध्यकारी निर्णय पर सहमत हुए।
- समूह के सदस्यों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में व्यापार के महत्व पर एक घोषणा जारी की और कहा कि वे खाद्य निर्यात पर प्रतिबंध से बचेंगे।
- तथापि, घरेलू खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए देशों को खाद्य आपूर्ति को प्रतिबंधित करने की अनुमति होगी।
- भारत की प्रमुख मांग यह थी कि वह अपने सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से अन्य देशों में खाद्य निर्यात करने की अनुमति दे।
- इस मांग पर 2023 में अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कथित तौर पर चर्चा की जाएगी।

'कोविड-19' वैक्सीन उत्पादन पर समझौता

- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 5 साल के लिए पेटेंट धारक की सहमति के बिना कोविड -19 टीकों पर बौद्धिक संपदा पेटेंट को अस्थायी रूप से माफ करने पर सहमत हुए।
  - ♦ वर्तमान समझौता 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा किए गए मूल प्रस्ताव का एक सरल संस्करण है।

ई-कॉमर्स लेनदेन पर समझौता

- भारत ने विश्व व्यापार संगठन से ई-कॉमर्स लेनदेन पर सीमा शुल्क पर स्थगन के विस्तार की समीक्षा करने के लिए भी कहा है।
  - ♦ ई-कॉमर्स लेनदेन में डिजिटली ट्रेडेड सामान और सेवाएं शामिल हैं।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने पहली बार 1998 में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क नहीं लगाने पर सहमति व्यक्त की थी।
  - ♦ तब से स्थगन को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।
  - ♦ सभी सदस्य ई-कॉमर्स प्रसारण पर सीमा शुल्क पर लंबे समय से चली आ रही रोक को जारी रखने पर सहमत हुए।

विश्व व्यापार संगठन और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बारे में

- विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है।
- 1995 में स्थापित, विश्व व्यापार संगठन इसके 164 सदस्यों द्वारा चलाया जाता है।
- इसका उद्देश्य मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, जो व्यापार समझौतों के माध्यम से किया जाता है जिन पर सदस्य राज्यों द्वारा चर्चा और हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन देशों को व्यापार नियमों पर बातचीत करने और उनके बीच आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।
- मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय है और आमतौर पर हर दो साल में इसकी बैठक होती है।

- विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य MC में शामिल हैं और वे किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों पर निर्णय ले सकते हैं।

नोट: WTO ने द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर बनाए गए टैरिफ और व्यापार (GATT) **पर 1947 के सामान्य समझौते को रद्द कर दिया।**

रेलवे के लिए स्टार्टअप

भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने स्टार्ट-अप और अन्य संस्थाओं की भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है।

- रेल मंत्रालय ने नवीन तकनीकी समाधानों के लिए 1.5 करोड़ तक की धनराशि प्रदान करने के लिए 'रेलवे के लिए स्टार्टअप' नामक एक योजना शुरू की।

प्रमुख बिंदु

इस नीति का उद्देश्य बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में पैमाने और दक्षता लाना है।

- रेलवे के विभिन्न मंडलों, क्षेत्रीय कार्यालयों/जोनों से 100 से अधिक समस्या विवरण प्राप्त हुए थे।
- इन 100 समस्या बयानों में से 11 इस कार्यक्रम के चरण 1 के लिए रेल फ्रैक्चर, हेडवे रिडक्शन आदि को लिया गया है।
- इन्हें नवोन्मेषी समाधान खोजने के लिए स्टार्ट अप के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं :

- मील के पत्थर-वार भुगतान के प्रावधान के साथ समान साझेदारी के आधार पर नवप्रवर्तनक को 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
- समस्या विवरण के तैरने से लेकर प्रोटोटाइप के विकास तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
  - ♦ प्रक्रिया को पारदर्शी और वस्तुपरक बनाने के लिए एक परिभाषित समय-सीमा भी है।
- रेलवे में प्रोटोटाइप का ट्रायल किया जाएगा।

- प्रोटोटाइप के सफल प्रदर्शन पर परिनियोजन को बढ़ाने के लिए उन्नत वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा।
- नवोन्मेषकों का चयन एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली द्वारा किया जाएगा जिसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निपटाया जाएगा।
- विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नवप्रवर्तनक के पास ही रहेंगे।
- नवप्रवर्तनक को विकासात्मक आदेश का आश्वासन दिया।
- विलम्ब से बचने के लिए संभागीय स्तर पर संपूर्ण उत्पाद विकास प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण।

कैबिनेट ने IMT/5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

- नीलामी के माध्यम से सफल बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा।

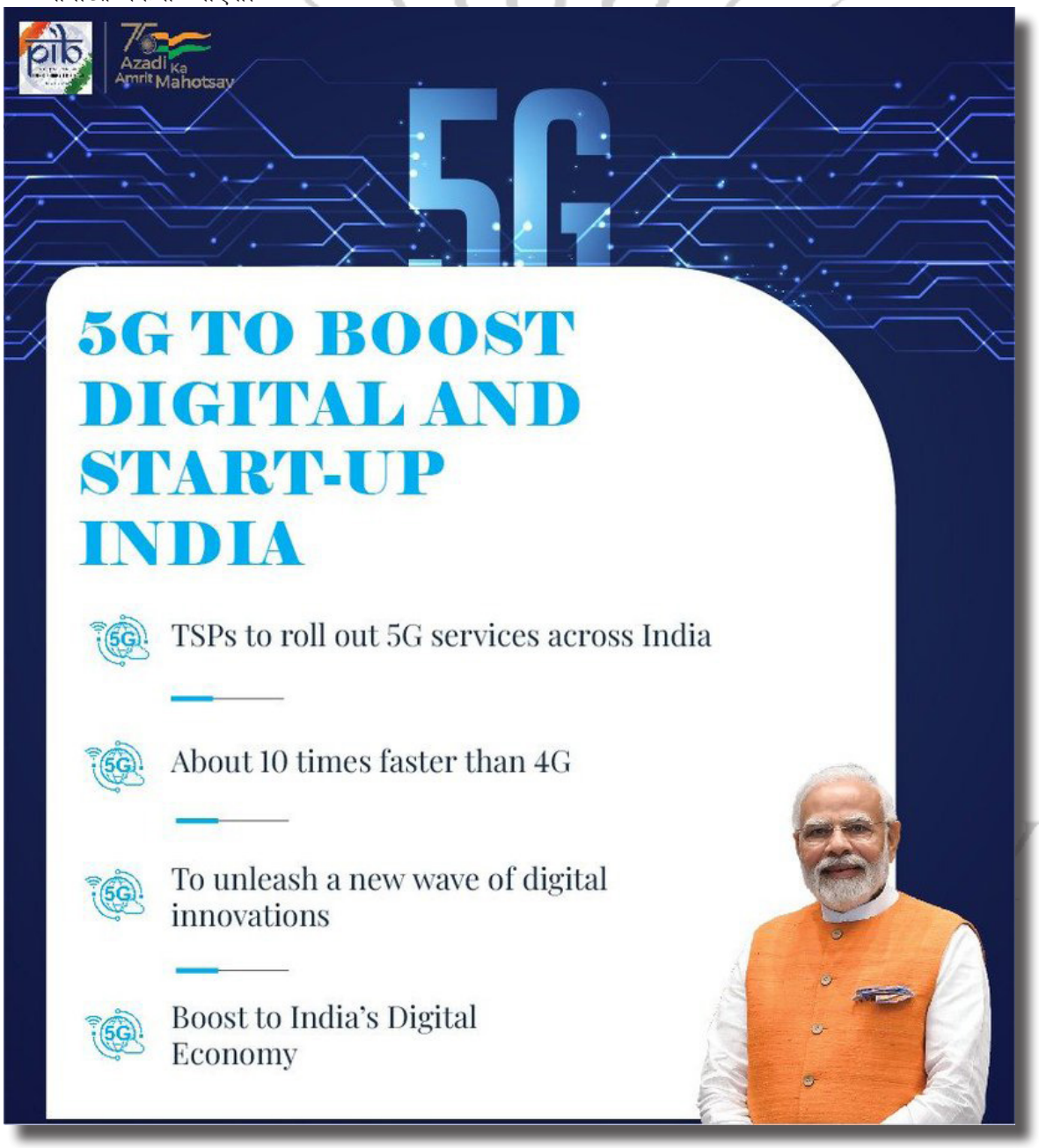

प्रमुख बिंदु

- ब्रॉडबैंड, विशेष रूप से मोबाइल ब्रॉडबैंड, नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है।
- 2015 से देश भर में 4G सेवाओं के तेजी से विस्तार के माध्यम से इसे एक बड़ा बढ़ावा मिला है।
- 2014 में दस करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज 80 करोड़ ग्राहकों के पास ब्रॉडबैंड की पहुंच है।
- देश में निर्मित 4G पारिस्थितिकी तंत्र अब 5G स्वदेशी विकास की ओर अग्रसर है।
- भारत के 8 शीर्ष प्रौद्योगिकी संस्थानों में 5जी परीक्षण बेड की स्थापना भारत में घरेलू 5G प्रौद्योगिकी के शुभारंभ में तेजी ला रही है।
- स्पेक्ट्रम पूरे 5G पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है।
- 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी।
- विभिन्न बैंडों में स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी आयोजित की जाएगी जैसे: कम (600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज), मध्य (3300 मेगाहर्ट्ज) और उच्च (26 मेगाहर्ट्ज) आवृत्ति बैंड।
- यह उम्मीद की जाती है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 5जी प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को शुरू करने के लिए मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाएगा।
  - ये सेवाएं वर्तमान 4G सेवाओं के माध्यम से संभव से लगभग 10 गुना अधिक गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम होंगी।
- स्पेक्ट्रम नीलामी को सितंबर, 2021 में घोषित दूरसंचार क्षेत्र के सुधारों से भी लाभ होगा।
  - सुधारों में आगामी नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम पर शून्य स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) शामिल है।
  - यह दूरसंचार नेटवर्क की परिचालन लागत के मामले में सेवा प्रदाताओं को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा।
  - इसके अलावा, एक वार्षिक किस्त के बराबर वित्तीय बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।
  - इसके अलावा, पहली बार सफल बोलीदाताओं द्वारा अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।
  - स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किश्तों में प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
  - इससे नकदी प्रवाह की आवश्यकताओं में उल्लेखनीय रूप से कमी आने और इस क्षेत्र में व्यवसाय करने की लागत कम होने की उम्मीद है।
  - बोलीदाताओं को शेष किश्तों के संबंध में भविष्य की देनदारियों के बिना 10 वर्षों के बाद स्पेक्ट्रम सरेंडर करने का विकल्प दिया जाएगा।
- 5जी सेवाओं को शुरू करने के लिए पर्याप्त बैकहॉल स्पेक्ट्रम की उपलब्धता भी आवश्यक है।
- बैकहॉल की मांग को पूरा करने के लिए, मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ई-बैंड में प्रत्येक 250 मेगाहर्ट्ज के 2 वाहकों को अनंतिम रूप से आवंटित करने का निर्णय लिया है।
- कैबिनेट ने 13, 15, 18 और 21 गीगाहर्ट्ज बैंड के मौजूदा फ्रीक्वेंसी बैंड में पारंपरिक माइक्रोवेव बैकहॉल कैरियर्स की संख्या को दोगुना करने का भी निर्णय लिया।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल दूरसंचार (IMT) शब्द ITU (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) समुदाय द्वारा ब्रॉडबैंड मोबाइल सिस्टम को नामित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य शब्द है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने स्थापना दिवस मनाया

भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ने "आजादी का अमृत महोत्सव" के एक भाग के रूप में अपना स्थापना दिवस मनाया।

- भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद जुलाई में 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का आयोजन कर रही है।

भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के बारे में

- भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद (ISEPC) की स्थापना 1983 में निर्यातकों, निर्माताओं, व्यापारियों के शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी।
- यह भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा विधिवत प्रायोजित कंपनी अधिनियम के तहत लाभ के लिए नहीं, परिषद है।
- आईएसईपीसी रेशम क्षेत्र से संबंधित नीति निर्माण पर भारत सरकार के साथ मिलकर काम करता है।
- यह व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करता है, भारत में रेशम उद्योग के लिए वैश्विक व्यापार के अवसरों को बढ़ाता है।
- **परिषद की मुख्य गतिविधियां:**
  - ♦ बाजारों का अन्वेषण करें और बाजार सर्वेक्षण करके निर्यात क्षमता की पेशकश करने वाली वस्तुओं की पहचान करें।
  - ♦ भारतीय रेशम उत्पादों में रुचि पैदा करने के लिए संभावित खरीदारों के साथ संपर्क स्थापित करना।
  - ♦ विदेशों में विभिन्न बाजारों में प्रायोजक व्यापार प्रतिनिधिमंडल, अध्ययन दल और बिक्री दल।
  - ♦ अपने सदस्य निर्यातकों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करें।
  - ♦ भारत में रेशम मेलों और प्रदर्शनी का आयोजन करना।
  - ♦ व्यापार विवादों का समाधान।
  - ♦ भारत से रेशम उत्पादों का सामान्य प्रचार शुरू करना।
  - ♦ विभिन्न व्यापार और नीति संबंधी मुद्दों पर कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

5 विज्ञान और तकनीक

PSLV-C53

IN-SPACe और ISRO ने PSLV C53 मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप के दो पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

- इसरो ने 30 जून, 2022 को PSLV-C53/DS-EO मिशन शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

- PSLV-C53 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है।
- इसे सिंगापुर के दो अन्य सह-यात्री उपग्रहों के साथ DS-EO उपग्रह की परिक्रमा करने के लिए डिजाइन

किया गया है।

- यह PSLV का 55वां मिशन है और PSLV-कोर अलोन वैरिएंट का उपयोग करने वाला 15वां मिशन है।
- यह दूसरे लॉन्च पैड से 16वां PSLV प्रक्षेपण है।
- मिशन उपग्रहों के पृथक्करण के बाद वैज्ञानिक नीतभारों के लिए एक स्थिर मंच के रूप में प्रक्षेपण यान के खर्च किए गए ऊपरी चरण के उपयोग को प्रदर्शित करने का प्रस्ताव करता है।
- DS-EO में इलेक्ट्रो-ऑप्टिक, मल्टी-स्पेक्ट्रल पेलोड होता है जो भूमि वर्गीकरण के लिए पूर्ण रंगीन चित्र प्रदान करेगा, और मानवीय सहायता और आपदा राहत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

IN-SPACE के बारे में

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe या INSPACe) अंतरिक्ष विभाग के तहत एक एकल-खिड़की स्वायत्त एजेंसी है।

- यह अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति देने और एनजीपीई (गैर-सरकारी-निजी-संस्थाओं) द्वारा डॉस के स्वामित्व वाली सुविधाओं के उपयोग के साथ-साथ लॉन्च मैनिफेस्ट को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है।
- यह अंतरिक्ष गतिविधियों में एनजीपीई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन और हैंड होल्डिंग, प्रौद्योगिकी साझा करने और विशेषज्ञता के लिए एक उपयुक्त तंत्र तैयार करेगा।

खोजी गई नई सामग्री

वैज्ञानिकों ने एक नई सामग्री की खोज की है जो उच्च दक्षता के साथ अवरक्त प्रकाश का उत्सर्जन, पता लगा सकती है और उसे संशोधित कर सकती है।

- यह सामग्री को सौर और तापीय ऊर्जा संचयन और ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए उपयोगी बनाता है।

प्रमुख बिंदु

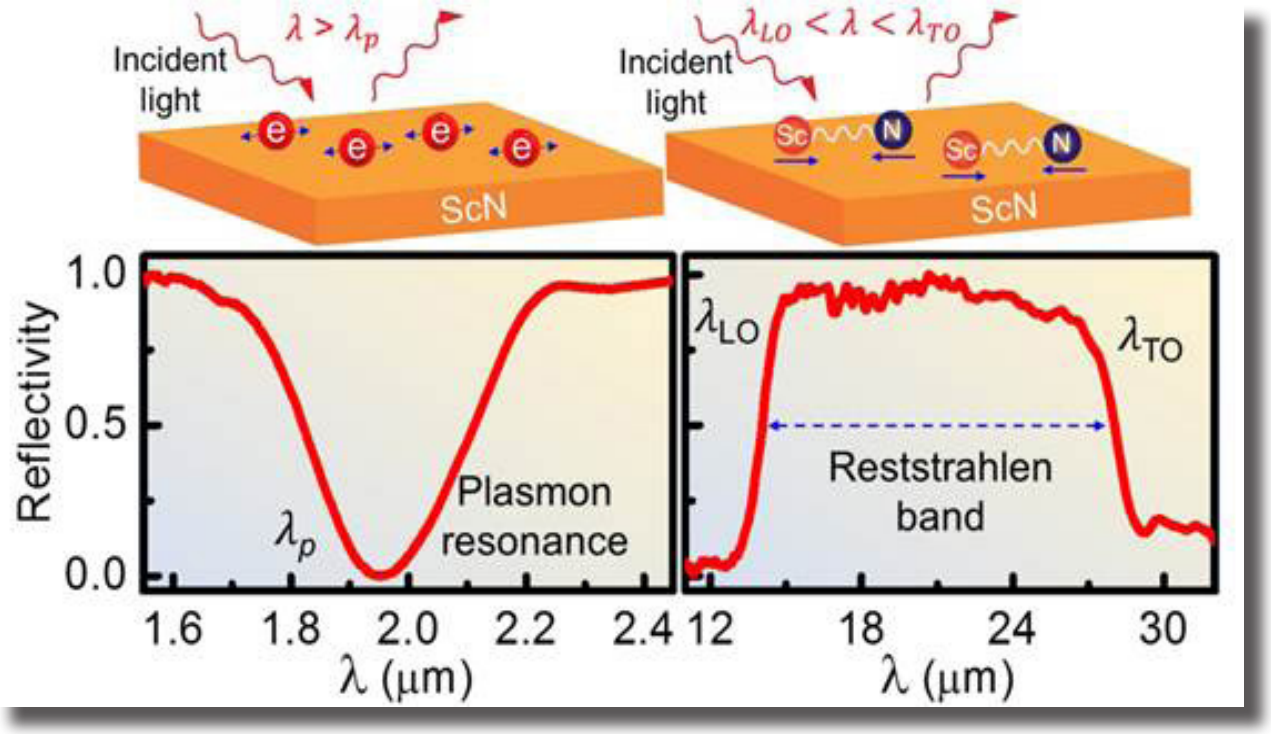

- विद्युत चुंबकीय तरंगें एक अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं।
- उनका उपयोग बिजली उत्पादन, दूरसंचार, रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, सेंसर और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है।

- वैज्ञानिक ऐसी तरंगों को सटीक रूप से हेरफेर करने के लिए उच्च-तकनीकी विधियों का उपयोग करते हैं - ऐसे आयामों में जो मानव बाल से हजारों गुना छोटे होते हैं, विशेष सामग्री का उपयोग करते हुए।
- हालांकि, प्रकाश की सभी तरंग दैर्ध्य (विद्युत चुम्बकीय तरंगों) का उपयोग करना आसान नहीं है, विशेष रूप से अवरक्त प्रकाश, क्योंकि इसका पता लगाना और संशोधित करना मुश्किल है।
- एक महत्वपूर्ण विकास में, शोधकर्ताओं ने सिंगल-क्रिस्टलीय स्कैंडियम नाइट्राइड (ScN) नामक एक नई सामग्री की खोज की है।
    - ♦ यह सामग्री जो उच्च दक्षता के साथ अवरक्त प्रकाश का उत्सर्जन, पता लगा सकती है और उसे संशोधित कर सकती है।
- उनके पास पोलरिटोन (एक अर्ध-कण) को उत्तेजित करने और मजबूत प्रकाश-पदार्थ अंत:क्रिया को प्राप्त करने के लिए भौतिक गुणों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है।
- ScN में इन विदेशी पोलरिटोन का उपयोग सौर और तापीय ऊर्जा संचयन के लिए किया जा सकता है।
- इसके अलावा, गैलियम नाइट्राइड (GaN) जैसी सामग्री के एक ही परिवार से संबंधित;
    - ♦ स्कैंडियम नाइट्राइड आधुनिक पूरक-धातु-ऑक्साइड-सेमीकंडक्टर (CMOS) या सी-चिप तकनीक के साथ संगत है और इसलिए, ऑन-चिप ऑप्टिकल संचार उपकरणों के लिए आसानी से एकीकृत किया जा सकता है।

चित्र में: नैनोस्केल आयाम पर सामूहिक मुक्त इलेक्ट्रॉन दोलन (प्लास्मोन) और जाली दोलन (ऑप्टिकल फोनन) सहित सामग्री के आवेश वाहकों (विद्युत द्विध्रुव) के माध्यम से प्रकाश हेरफेर।

नोट: अनुसंधान दल बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) से संबंधित है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त संस्थान है।

तेजी से चार्ज होने वाला ई-साइकिल विकसित हुआ

तेजी से चार्ज होने वाले ई-साइकिल विकसित वैज्ञानिकों ने Na-ion आधारित बैटरी और सुपरकैपेसिटर विकसित करने के लिए नैनो-सामग्री का उपयोग किया है।

- इन Na-ion-आधारित बैटरियों को तेजी से चार्ज किया जा सकता है और इन्हें ई-साइकिल में एकीकृत किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

- कम लागत वाली ना-आयन आधारित प्रौद्योगिकियां सस्ती होंगी और इससे ई-साइकिल की लागत में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
- यह सोडियम की उच्च प्राकृतिक प्रचुरता और परिणामस्वरूप Na-ion बैटरी की कम लागत के कारण है।
- ये सोडियम सामग्री ली-आधारित सामग्री की तुलना में सस्ती हैं, उच्च प्रदर्शन करती हैं, और इन्हें औद्योगिक स्तर के उत्पादन तक बढ़ाया जा सकता है।
- Na-ion सेल को भी कैपेसिटर की तरह जीरो वोल्ट में पूरी तरह से डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिससे यह कई अन्य स्टोरेज तकनीकों की तुलना में एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है।
- इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि Na-ion बैटरियों को तेजी से चार्ज किया जा सकता है, वैज्ञानिकों ने इसे ई-साइकिल में भी एकीकृत किया है।
- आगे के विकास के साथ, इन वाहनों की कीमत रुपये की सीमा तक लाया जा सकता है। 10-15 हजार, जिससे वे लगभग 25% सस्ते हो गए।

आदित्य-L1 साइंस सपोर्ट सेल

भारत भर के संस्थानों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को आदित्य-एल1 मिशन के माध्यम से सूर्य पर होने वाली बुनियादी प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया।

- छात्रों को अवलोकन संबंधी डेटा विश्लेषण के साथ-साथ वर्तमान खुली समस्याओं को भी दिखाया गया जो इस विषय पर युवा शोधकर्ता संबोधित कर सकते हैं।
- यह कार्यशाला आदित्य-L1 विज्ञान सहायता प्रकोष्ठ (AL1 SSC) द्वारा आयोजित की गई थी।

आदित्य-L1 मिशन के बारे में

- आदित्य-L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष यान मिशन है।
- यह सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं की व्यापक समझ को सक्षम करेगा और सौर भौतिकी और हेलियोफिजिक्स में कुछ उत्कृष्ट समस्याओं का समाधान करेगा।
- आदित्य-एल1 की कल्पना मूल रूप से आदित्य-1 मिशन के रूप में की गई थी, जो एक 400 किग्रा वर्ग का उपग्रह है जो एक पेलोड, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनग्राफ (YELC) ले जाता है।
  - ♦ इसे 800 किमी निचली पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित करने की योजना थी।
- उपग्रह को अब सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु 1 (L1) के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
  - ♦ कक्षा को बिना किसी गुप्त ग्रहण/ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का प्रमुख लाभ है।
- इसलिए, आदित्य-1 मिशन को अब "आदित्य-L1 मिशन" में संशोधित किया गया है।
- इसे L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है।
- उपग्रह उन्नत विज्ञान क्षेत्र और उद्देश्यों के साथ अतिरिक्त छह नीतभार वहन करता है।
- आदित्य-L1 अतिरिक्त प्रयोगों के साथ अब सूर्य के कोरोना (नरम और कठोर एक्स-रे, दृश्य में उत्सर्जन रेखाएं और एनआईआर) का अवलोकन प्रदान कर सकता है।

यह क्रोमोस्फीयर (UV) और फोटोस्फीयर (ब्रॉडबैंड फिल्टर) के अवलोकन भी प्रदान कर सकता है।

- इसके अलावा, कण नीतभार सूर्य से निकलने वाले और L1 कक्षा में पहुंचने वाले कण प्रवाह का अध्ययन करेंगे,
  - ♦ मैग्नेटोमीटर पेलोड L1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत में भिन्नता को मापेगा।
- इन नीतभारों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप से बाहर रखा जाना चाहिए और पृथ्वी की निचली कक्षा में उपयोगी नहीं हो सकते हैं।

विभिन्न पेलोड का विवरण

- विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC):
  - ♦ सौर कोरोना के निदानकारी मापदंडों और गतिशीलता और कोरोनल मास इजेक्शन की उत्पत्ति का अध्ययन करना।
- सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT):
  - ♦ निकट पराबैंगनी (200-400 NM) में स्थानिक रूप से हल किए गए सौर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की छवि बनाने और सौर विकिरण विविधताओं को मापने के लिए।
- आदित्य सौर पवन कण प्रयोग (ASPEX) :
  - ♦ सौर पवन गुणों की भिन्नता के साथ-साथ इसके वितरण और वर्णक्रमीय विशेषताओं का अध्ययन करना।
- आदित्य (PAPA) के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज:

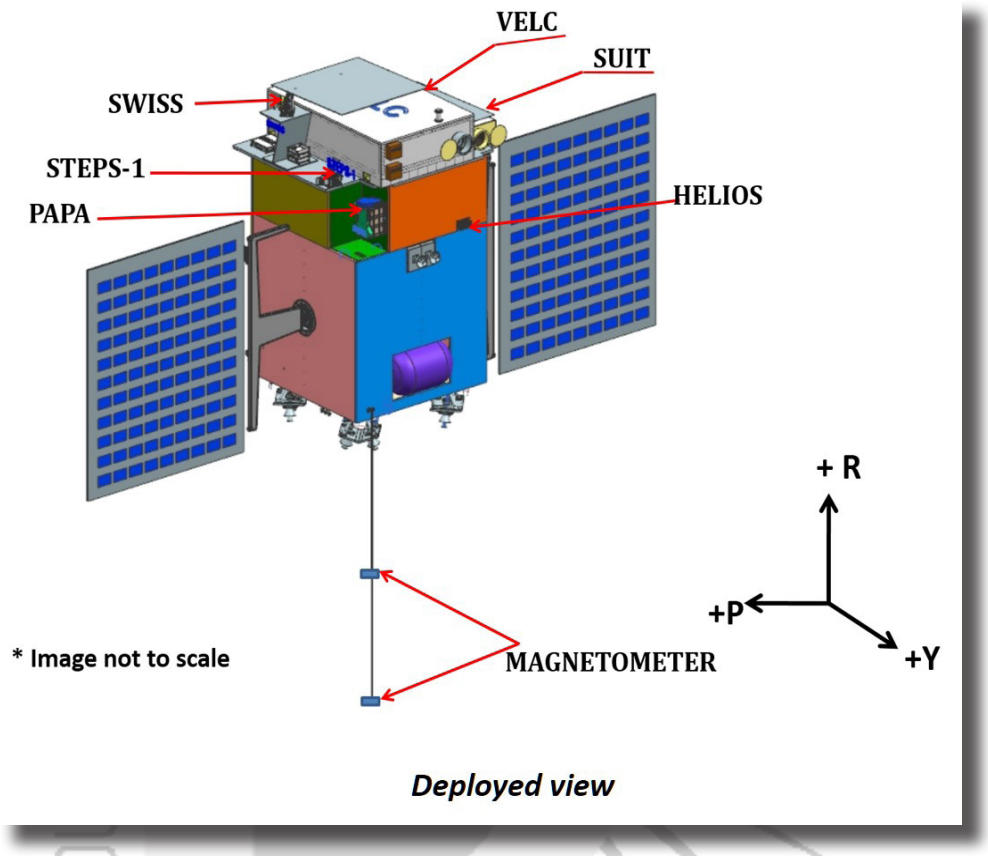

- ♦ सौर पवन की संरचना और उसके ऊर्जा वितरण को समझना।
- सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS):
  - ♦ सौर कोरोना के ताप तंत्र का अध्ययन करने के लिए एक्स-रे फ्लेयर्स की निगरानी करना।
- उच्च ऊर्जा L1 परिक्रमा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS):
  - ♦ सौर कोरोना में गतिशील घटनाओं का निरीक्षण करना और विस्फोट की घटनाओं के दौरान कणों को तेज करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का अनुमान प्रदान करना।
- मैग्नेटोमीटर:
  - ♦ अंतरग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और प्रकृति को मापने के लिए।

इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज 2022

डिजिटल इंडिया वीक 2022 समारोह के हिस्से के रूप में, इंडिया स्टैक नॉलेज एक्सचेंज पर 3 दिवसीय लंबा वर्चुअल इवेंट भी शुरू किया गया था।

- यह आयोजन डिजिटल दुनिया में भारत के सबसे महत्वपूर्ण योगदान - इंडिया स्टैक को प्रदर्शित करने का एक अवसर है।

इंडिया स्टैक क्या है?

इंडिया स्टैक भारत की आबादी को डिजिटल युग में लाने के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को संदर्भित करता है।

- यह खुले एपीआई और डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं के एक सेट के लिए उपनाम है जिसका उद्देश्य जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक आदिमताओं को अनलॉक करना है।

- इंडिया स्टैक का आधार, भारत के राष्ट्रीय पहचान कार्यक्रम के आसपास केंद्रित डिजिटल पहचान उत्पादों का एक समूह है।
- प्रदान की गई चार विशिष्ट प्रौद्योगिकी परतें हैं:
  - **उपस्थिति-रहित परत:** जहां एक सार्वभौमिक बायोमेट्रिक डिजिटल पहचान लोगों को देश में कहीं से भी किसी भी सेवा में भाग लेने की अनुमति देती है।
  - **पेपरलेस लेयर:** जहां डिजिटल रिकॉर्ड किसी व्यक्ति की डिजिटल पहचान के साथ चलते हैं, जिससे भारी मात्रा में पेपर संग्रह और भंडारण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
  - **कैशलेस लेयर:** जहां भुगतान को लोकतांत्रिक बनाने के लिए देश के सभी बैंक खातों और वॉलेट के लिए एक ही इंटरफेस।
  - **सहमति परत:** जो डेटा के लिए बाजार को लोकतांत्रिक बनाने के लिए डेटा को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है।
- निम्नलिखित एपीआई को इंडिया स्टैक का मुख्य भाग माना जाता है:
  - आधार प्रमाणीकरण
  - आधार ई-केवाईसी
  - ई-साइन
  - डिजिटल लॉकर
  - एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)
  - डिजिटल उपयोगकर्ता सहमति - अभी भी कार्य प्रगति पर है।

Statistics of success

Technology for 1.2 Billion Indians

67 billion	5.47 trillion	2.8 billion	4
Total number of digital identity verifications	INR total value of monthly real-time mobile payments	Total volume of monthly real-time mobile payments	Operational Account Aggregators

द टाइमलाइन: इंडिया स्टैक बिल्ड-अप एंड सक्सेस

- 2009- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAE) का गठन किया गया।
- 2010- सबसे पहले आधार कार्ड जारी किया जाता है।
- 2011- एनपीसीआई ने आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे सरकारी सब्सिडी को चौनल करने के लिए आधार भुगतान ब्रिज और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली शुरू की।
- 2012- यूआईडीएआई ने ईकेवाईसी की शुरुआत की जो बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानें की लागत ~+23 से घटाकर ~+0.15 कर देता है
- 2015- CCA ने खुले एपीआई के रूप में ई-साइन लॉन्च किया, जिससे आधार धारक किसी भी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं।
- 2015- एमईआईटीवाई ने डिजिलॉकर लॉन्च किया।

RAO'S ACADEMY

- 2016- आधार धारकों की संख्या 1 अरब के पार।
- 2016- NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लॉन्च किया, जो रीयल-टाइम मोबाइल भुगतान में एक क्रांति है।
- 2018- UPI का उपयोग करके किए गए मोबाइल भुगतान की संख्या 1 बिलियन को पार कर गई।
- 2019- UPI मासिक लेनदेन की मात्रा 1 बिलियन के पार।
- 2021- UPI मासिक लेनदेन की मात्रा 4 बिलियन को पार कर गई।
- 2021- 8 बैंकों के साथ अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लाइव हो गया।

अकाउंट एग्रीगेटर क्या है?

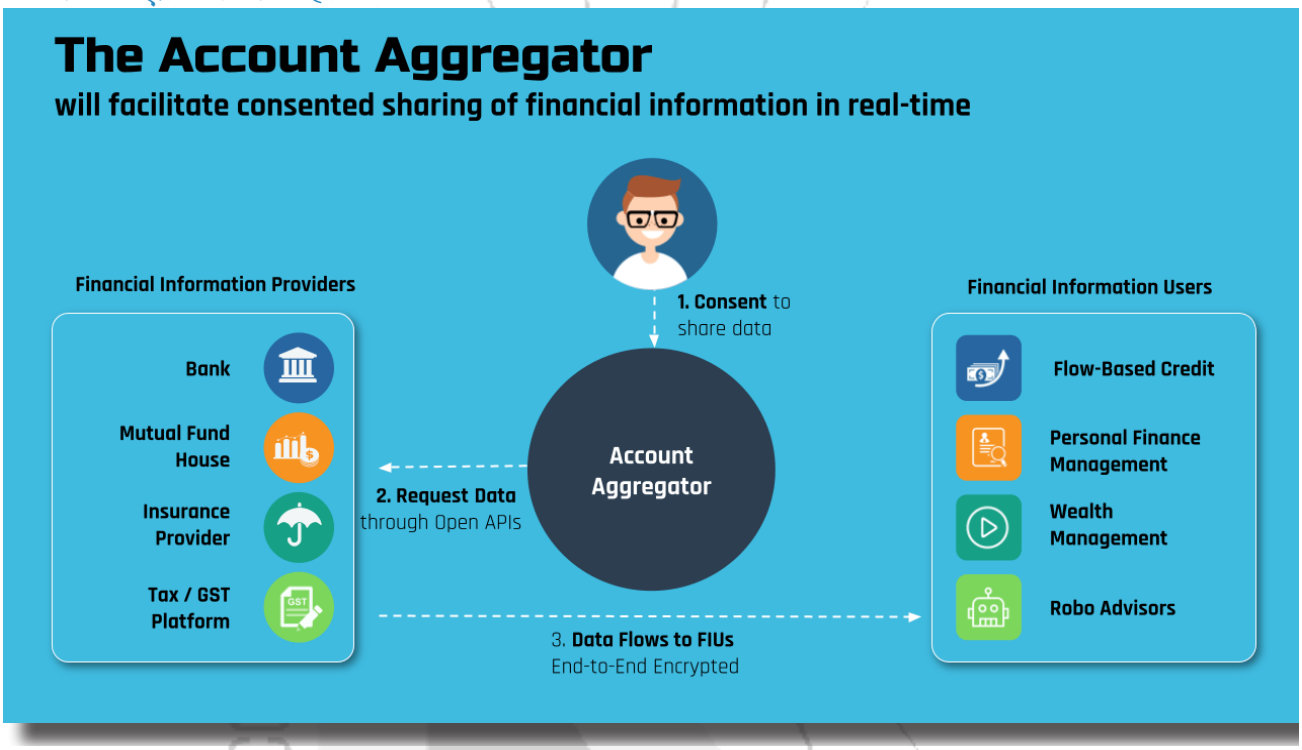

- एकाउंट एग्रीगेटर (AA) आरबीआई द्वारा विनियमित इकाई का एक प्रकार है (NBFC-AA लाइसेंस के साथ)A
- एए किसी व्यक्ति को सुरक्षित रूप से और डिजिटल रूप से एक्सेस करने और एक वित्तीय संस्थान से जानकारी साझा करने में मदद करेगा जिसका एए नेटवर्क में किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ खाता है।
- व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा साझा नहीं किया जा सकता है।
- खाता एग्रीगेटर आपके डेटा के प्रत्येक उपयोग के लिए 'रिक्त चेक' स्वीकृति के लंबे नियम और शर्तों के रूप को एक बारीक, चरण-दर-चरण अनुमति और नियंत्रण से बदल देता है।
- एए के साथ, उपभोक्ता अपने सभी सहमति समझौतों को एक ही स्थान पर स्वीकृत/प्रबंधित/निरस्त कर सकते हैं।
- संपूर्ण AA सिस्टम डिजाइन द्वारा इंटरऑपरेबल है, इसलिए एक सेवा प्रदाता जो एक AA ऐप के साथ एकीकृत होता है, वह किसी अन्य ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए भी डेटा अनुरोध कर सकता है।

भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI)

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने पश्चिम बंगाल में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए दुर्गापुर और बर्धमान में इंटरनेट एक्सचेंज की शुरुआत की।

- यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के विजन 1000 दिनों के तहत एक पहल है।

प्रमुख बिंदु

- कोलकाता में राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज भी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) द्वारा चलाया

जाता है।

- अब यह दुर्गापुर और बर्धमान में दो नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट लॉन्च करके राज्य में अपने पदचिह्न का विस्तार कर रहा है।
- इन नए IXPs के खुलने से राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्टार्टअप, इकोसिस्टम से लेकर MSMEs और अन्य व्यावसायिक वर्टिकल तक के हर क्षेत्र को लाभ होगा।
- NIXI की निकट भविष्य में टियर-2 और टियर-3 शहरों में ऐसे इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है।
  - ♦ **उद्देश्य:** समग्र भारतीय इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को बेहतर गति के साथ कम कीमत पर इसकी पहुंच प्रदान करना।

MeitY के विजन-1000 डेज के बारे में :

- एमईआईटीवाई के विजन 1000 डेज ने आत्मनिर्भर भारत के लिए +1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- इस संबंध में MeitY ने 'भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि और जीवीसी में हिस्सेदारी' पर एक विजन दस्तावेज भी जारी किया है।
- इसे उद्योग के परामर्श से इंडियन सेल्युलर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) द्वारा तैयार किया गया है।
- विजन दस्तावेज अल्पकालिक (1-4 वर्ष) और दीर्घकालिक (5-10 वर्ष) रणनीतियों पर सिफारिशें करता है।

NIXI के बारे में

- NIXI कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभ के लिए नहीं संगठन है, और 19 जून, 2003 को पंजीकृत किया गया था।
- NIXI की स्थापना आईएसपी को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी ताकि देश के भीतर घरेलू यातायात को अमेरिका/विदेश में ले जाने के बजाय उसे रूट किया जा सके।
- इसके परिणामस्वरूप सेवा की बेहतर गुणवत्ता (कम विलंबता) होती है और अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ पर बचत करके आईएसपी के लिए बैंडविड्थ शुल्क कम होता है।
- IN भारत का कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन (CCTLD) है।
- भारत सरकार ने 2004 में INR रजिस्ट्री के संचालन को NIXI को सौंप दिया।
- आईएनआर रजिस्ट्री भारत के IN ccTLD का संचालन और प्रबंधन करती है।

कैंसर पैदा करने वाला वायरस एपस्टीन बार वायरस (EBV)

वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैंसर पैदा करने वाला वायरस एपस्टीन बार वायरस (EBV) न्यूरोनल कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है।

- इस तरह वे फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन घटकों जैसे जैव अणुओं में विभिन्न परिवर्तन कर सकते हैं।
- फिर इन परिवर्तनों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रोगों के साथ-साथ मस्तिष्क कैंसर भी हो सकता है।

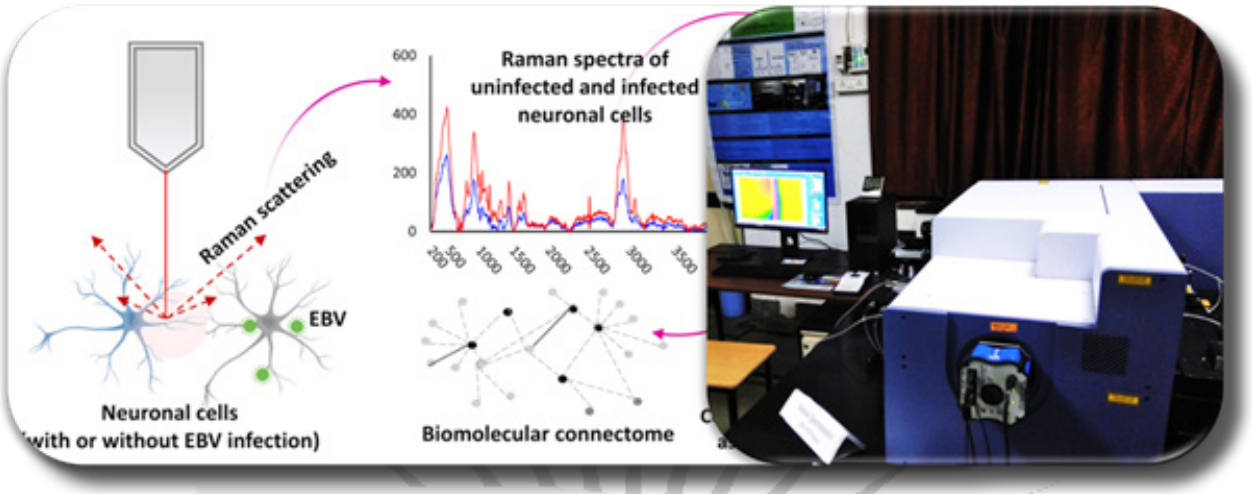

The Raman Spectrometer and Spectra received from brain cells

प्रमुख बिंदु

- मानव आबादी में EBV वायरस व्यापक रूप से मौजूद पाया गया है।
- यह आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कुछ असामान्य स्थितियों जैसे प्रतिरक्षाविज्ञानी तनाव या प्रतिरक्षा क्षमता में वायरस शरीर के अंदर पुनः सक्रिय हो जाता है।
- यह आगे चलकर विभिन्न प्रकार की जटिलताएं पैदा कर सकता है जैसे बुर्किट लिंफोमा नामक एक प्रकार का रक्त कैंसर, पेट का कैंसर, मल्टीपल स्केलेरोसिस, इत्यादि।
- पहले के अध्ययनों ने विभिन्न न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों में EBV की भागीदारी के लिंक प्रदान किए।
- हालांकि, यह वायरस मस्तिष्क की कोशिकाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है और उनमें हेरफेर कैसे कर सकता है, इसका अभी पता नहीं चला है।
- IIT इंदौर के एक शोध दल ने मस्तिष्क कोशिकाओं पर कैंसर पैदा करने वाले वायरस के संभावित प्रभावों का पता लगाने के लिए रमन माइक्रो-स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया।
- अध्ययन से पता चलता है कि वायरल प्रभाव के तहत न्यूरोनल कोशिकाओं में विभिन्न जैव-अणुओं में समय पर और क्रमिक परिवर्तन हो सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, ये परिवर्तन अन्य सहायक मस्तिष्क कोशिकाओं (अर्थात, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लिया) में देखे गए परिवर्तनों की तुलना में भिन्न थे।
- उन्होंने देखा कि वायरल प्रभाव के तहत कोशिकाओं में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलाइन और ग्लूकोज अणुओं में वृद्धि हुई है।
- ये जैव-आणविक इकाइयाँ अंततः कोशिकाओं के वायरल हड़पने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- इसके अलावा, अध्ययन ने यह भी अंतर्दृष्टि प्रदान की कि क्या इन जैव-आणविक परिवर्तनों को वायरस से जुड़े प्रभावों से जोड़ा जा सकता है और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं से जोड़ा जा सकता है।

एपस्टीन बार वायरस (EBV) के बारे में

- एपस्टीन-बार वायरस (EBV), जिसे ह्यूमन हर्पीसवायरस 4 के नाम से भी जाना जाता है, हर्पीज वायरस परिवार का सदस्य है।
- यह सबसे आम मानव विषाणुओं में से एक है।
- EBV पूरी दुनिया में पाया जाता है।
- अधिकांश लोग अपने जीवन में कभी न कभी EBV से संक्रमित हो जाते हैं।
- पहली बार जब कोई व्यक्ति EBV (प्राथमिक EBV संक्रमण) से संक्रमित होता है, तो वह हफ्तों तक और

आपके लक्षण दिखने से पहले भी वायरस फैला सकता है।

- EBV आमतौर पर शारीरिक तरल पदार्थ, मुख्य रूप से लार के माध्यम से फैलता है।
- हालांकि, EBV यौन संपर्क, रक्त आधान और अंग प्रत्यारोपण के दौरान रक्त और वीर्य के माध्यम से भी फैल सकता है।
- EBV संक्रामक मोनोन्यूक्लिओसिस, जिसे मोनो भी कहा जाता है, और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है।
- एक बार जब वायरस आपके शरीर में आ जाता है, तो यह वहां एक गुप्त (निष्क्रिय) अवस्था में रहता है।
- यदि वायरस पुनः सक्रिय हो जाता है, तो आप संभावित रूप से EBV को दूसरों तक फैला सकते हैं, भले ही प्रारंभिक संक्रमण के बाद कितना भी समय बीत चुका हो।
- **निदान:**
  - ♦ ईबीवी संक्रमण का निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि लक्षण अन्य बीमारियों के समान होते हैं।
  - ♦ एंटीबॉडी का पता लगाने वाले रक्त परीक्षण से ईबीवी संक्रमण की पुष्टि की जा सकती है।
- ईबीवी संक्रमण से बचाव के लिए कोई टीका नहीं है।

बाइनरी सुपर विशाल ब्लैक होल

खगोलविदों के एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग ने एक प्रणाली में एक द्विआधारी सुपर विशाल ब्लैक होल की खोज की है जो भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों (GW) का पता लगाने के लिए एक मजबूत उम्मीदवार होगा।

प्रमुख बिंदु

- अर्जेंटीना, स्पेन, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के खगोलविदों के एक समूह ने गुरुत्वाकर्षण लेंस वाले ब्लेजर AO 0235+164 में एक द्विआधारी सुपर विशाल ब्लैक होल प्रणाली की खोज की है।
  - ♦ यह पिछले 4 दशकों (1982 - 2019) के दौरान दुनिया भर में किए गए व्यापक ऑप्टिकल फोटोमेट्रिक अवलोकनों का उपयोग करके किया गया है।
- उन्होंने लगभग 8 वर्षों के अंतराल पर आवधिक डबल-पीक फ्लेरिंग घटनाओं की खोज की।
  - ♦ इन ज्वालामुखियों की दो चोटियों के बीच की दूरी लगभग 2 वर्ष है।
- ऐसे पांच आवधिक पैटर्न का पता लगाया गया था, और यह भविष्यवाणी की गई थी कि इस तरह की अगली भड़कीली घटना नवंबर 2022 और मई 2025 के बीच होगी।

ब्लेजर क्या है?

छवि में: सेंटोरस ए, एक सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक जो अपने केंद्र से सामग्री को बाहर निकालता है, एक्स-रे, माइक्रोवेव और दृश्य प्रकाश छवियों को जोड़ता है।

- अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में – हमारी अपनी आकाशगंगा सहित – एक विशाल ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान लाखों या अरबों सूर्यों का भी हो सकता है।
- कुछ आकाशगंगाओं में, यह सुपरमैसिव ब्लैक होल खाने के लिए अपने चारों ओर गैस, धूल और तारकीय मलबे की एक घूमती हुई डिस्क एकत्र कर सकता है।
- जैसे ही डिस्क में सामग्री ब्लैक होल की ओर गिरती है, इसकी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित किया जा सकता है।
  - ♦ यह इन आकाशगंगाओं के केंद्रों को बहुत उज्ज्वल बनाता है और उन्हें लेई देता है जो प्रकाश की गति के करीब यात्रा करने वाली सामग्री के विशाल जेट को भी बाहर निकालता है।
  - ♦ वैज्ञानिक इसे क्वासर कहते हैं।
- लेकिन जब कोई आकाशगंगा उन्मुख होती है तो जेट पृथ्वी की ओर इशारा करते हैं- इसे ब्लेजर कहा जाता है।
- यह क्वासर के समान ही है, बस एक अलग कोण पर इंगित किया गया है।
- ब्लेजर एक दूर की आकाशगंगा के मध्य में एक फीडिंग सुपर-मैसिव ब्लैक-होल (SMBH) है जो पृथ्वी से एक उच्च-ऊर्जा जेट को आमने-सामने देखने का उत्पादन करता है।

ब्लैक होल क्या है?

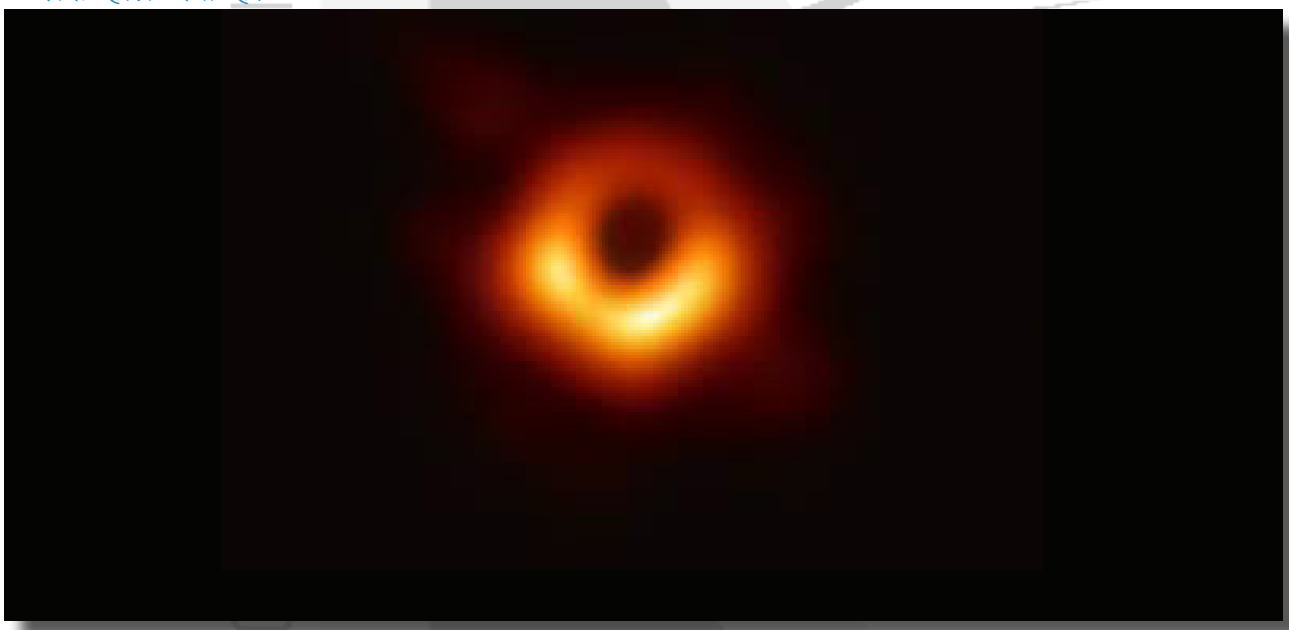

- ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक खींचता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता।
- गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है क्योंकि पदार्थ को एक छोटे से स्थान में दबा दिया गया है।
- ऐसा तब हो सकता है जब कोई तारा मर रहा हो।
- क्योंकि कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, लोग ब्लैक होल नहीं देख सकते।
- वे अदृश्य अंतरिक्ष दूरबीन हैं जो विशेष उपकरणों के साथ ब्लैक होल को खोजने में मदद कर सकते हैं।

RAO'S ACADEMY

मंकी पॉक्स का प्रकोप

WHO दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकीपॉक्स का पहला मामला भारत से सामने आया है, जो मध्य पूर्व से आए एक 35 वर्षीय व्यक्ति में है।

- देश मंकीपॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से पता लगाने और उचित उपाय करने के उपाय कर रहे हैं।

मंकीपॉक्स के बारे में

WHO ने कहा है कि वर्तमान में एक बहु-देशीय प्रकोप चल रहा है, जिसमें उन जगहों को भी शामिल किया गया है जहां यह बीमारी आमतौर पर पहले नहीं पाई गई है।

- मंकीपॉक्स, मंकीपॉक्स वायरस के कारण होता है, जो पोक्सविरिडे परिवार में ऑर्थोपॉक्सवायरस जीनस का एक सदस्य है।
- यह एक वायरल जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी-कभी अन्य क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है।
- मंकीपॉक्स वायरस घावों, शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और बिस्तर जैसी दूषित सामग्री के निकट संपर्क से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है।
- मंकीपॉक्स संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क के माध्यम से या वायरस से दूषित सामग्री के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।
- मंकीपॉक्स आमतौर पर 2 से 4 सप्ताह तक चलने वाले लक्षणों के साथ एक स्व-सीमित बीमारी है।
  - ♦ गंभीर मामले हो सकते हैं। हाल के दिनों में, मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3-6% रहा है।
- चेचक के इलाज के लिए विकसित एक एंटीवायरल एजेंट को भी मंकीपॉक्स के इलाज के लिए लाइसेंस दिया गया है।
- मंकीपॉक्स आमतौर पर चिकित्सकीय रूप से बुखार, दाने और सूजी हुई लिम्फ नोड्स के साथ पेश करता है और इससे कई तरह की चिकित्सीय जटिलताएं हो सकती हैं।
- मानव मंकीपॉक्स की पहचान सबसे पहले 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 9 महीने के एक लड़के में हुई थी।
- कुछ समूह संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जो कुछ कठिन चरणों को पेश कर सकते हैं, खासकर अगर यह फेफड़ों और आंखों को संक्रमित करता है।
- उच्च जोखिम वाले समूह में बच्चे, गर्भवती महिलाएं और मधुमेह से पीड़ित रोगियों सहित प्रतिरक्षा-समझौता वाले रोगी शामिल हैं।

RAO'S ACADEMY

नई मेमोरी डिवाइस

वैज्ञानिकों ने डेटा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए उत्कृष्ट स्विचिंग विशेषताओं और कम बिजली की आवश्यकताओं के साथ एक मेमोरी डिवाइस विकसित किया है।

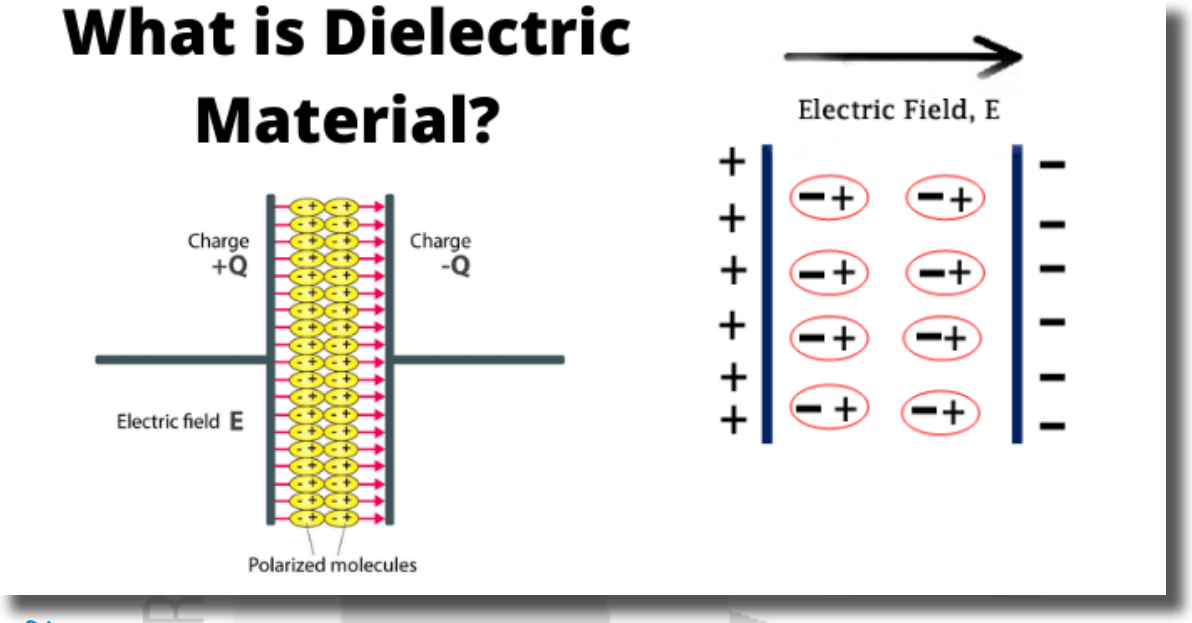

प्रमुख बिंदु

- प्रतिरोधक मेमोरी डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच इंसुलेटिंग फिल्म होती है-
  - ♦ इस तरह के उपकरण डेटा भंडारण के लिए कम बिजली की आवश्यकताओं के साथ उच्च-प्रदर्शन, और उच्च-घनत्व वाली यादों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
- वे प्रतिरोधक स्विचिंग विशेषताओं वाले उपकरण हैं।
- यह उस भौतिक घटना को संदर्भित करता है जिसमें एक ढांकता हुआ अचानक एक मजबूत धारा की क्रिया के तहत अपने (दो टर्मिनल) प्रतिरोध को बदल देता है।
- सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज (CENS) की सुश्री स्वाति एस.पी. और डॉ. एस. अंगप्पन ने उत्कृष्ट स्विचिंग विशेषताओं के साथ एक कम-शक्ति वाली मेमोरी डिवाइस विकसित की है।
- डिवाइस डेटा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए, रासायनिक हेफनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड के प्रतिस्थापन से बनाया गया है।
- सीईएनएस शोधकर्ता इन प्रतिरोधक स्मृति उपकरणों को लघु रूपों में परिवर्तित कर रहे हैं।

SARS-CoV-2 के वायरस लोड को नियंत्रित करने वाला Covaxin

वैज्ञानिकों ने पाया है कि **Covaxin**, **SARS-CoV**-2 और चिंता के प्रकारों के लिए मजबूत प्रतिरक्षा स्मृति को प्रेरित करता है।

- यह वायरस के भार को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और इस प्रकार, रोग की गंभीरता को कम कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- BBV152/Covaxin वैक्सीन Asp614Gly वैरिएंट पर आधारित है और फिटकरी में सोखने वाले टोल-जैसे रिसेप्टर (TLR) 7/8 एगोनिस्ट अणु (इमिडाजोक्विनोलिन) के साथ तैयार किया गया है।
- यह भारत में उत्पादित पहला फिटकरी-इमिडाजोक्विनोलिन सहायक टीका था।
- इसे बड़ी आबादी में उपयोग के लिए WHO से आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण भी प्राप्त हुआ था।

- हालांकि वैक्सीन की प्रभावशीलता के लिए नैदानिक परीक्षण के आंकड़े उपलब्ध थे, विशेष रूप से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रहे।
- **इन सवालों में शामिल हैं:**
  - ♦ क्या टीका प्रतिरक्षा स्मृति को प्रेरित करता है?
  - ♦ टीके से प्रेरित स्मृति कितने समय तक बनी रहती है? तथा
  - ♦ क्या ये मेमोरी प्रतिक्रियाएं SARS-CoV-2 वेरिएंट के खिलाफ टिकने में सक्षम हैं?
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (एनआईआई), नई दिल्ली ने उन 97 सार्स-सीओवी-2 की जांच की, जिन्हें 2 खुराक के टीकाकरण के 6 महीने बाद तक वैक्सीन नहीं मिली थी।
- वैक्सीन-प्रेरित प्रतिक्रियाओं की तुलना हल्के COVID-19 से बरामद 99 व्यक्तियों में प्रतिरक्षा स्मृति के साथ की गई थी।

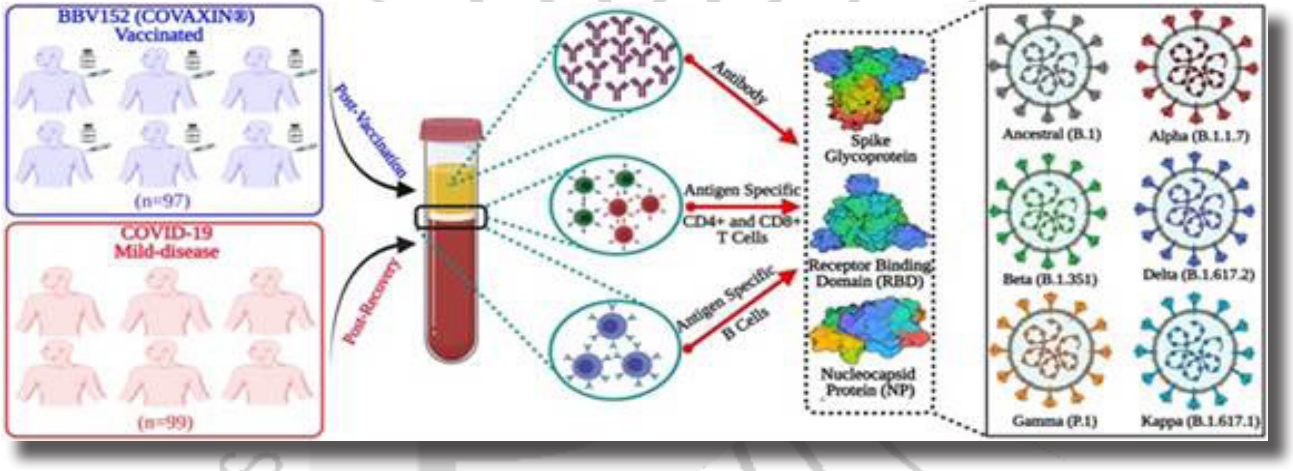

अध्ययन में पाया गया कि वैक्सीन वायरस के संक्रमण की तरह ही वायरस के स्पाइक, आरबीडी और न्यूक्लियोप्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करती है।

- हालांकि, बाध्यकारी और तटस्थ एंटीबॉडी दोनों के विश्लेषण से डेल्टा (भारत), बीटा (एस अफ्रीका), और अल्फा (यूके) जैसे चिंता के रूपों की कम पहचान का पता चला।
- इस अध्ययन से पता चला है कि टीका स्मृति बी कोशिकाओं को प्रेरित करने में सक्षम है।
- उन्होंने इसे संतोषजनक पाया क्योंकि एंटीबॉडी समय के साथ कम हो सकती हैं, लेकिन ये मेमोरी बी कोशिकाएं जब भी आवश्यक हो, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को फिर से भर सकती हैं।

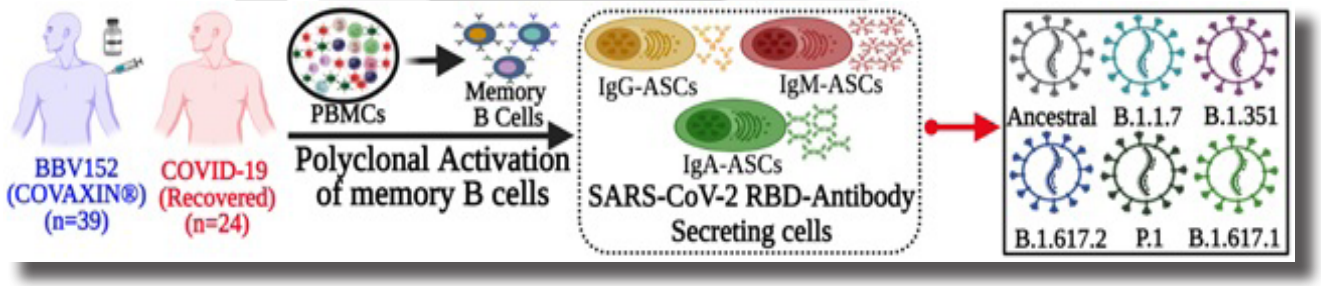

उनके अध्ययन ने एक निष्क्रिय वायरस टीके के जवाब में मानव में उत्पन्न प्रतिरक्षा स्मृति के विस्तृत लक्षणों का पहला सबूत प्रदान किया।

- टीम ने यह भी पाया कि टीके ने SARS-CoV-2-विशिष्ट T कोशिकाओं के उत्पादन की क्षमता दिखाई है।
- महत्वपूर्ण रूप से, और एंटीबॉडी के विपरीत, टी कोशिकाओं की प्रभावशीलता को वेरिएंट के खिलाफ अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था।

नव विकसित अल्ट्राथिन हेटरोप्रोटीन फिल्म

वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट थर्मल, मैकेनिकल और पीएच स्थिरता के साथ अति पतली हेटरोप्रोटीन फिल्में विकसित की हैं।

- यह बायोमेडिकल और खाद्य पैकेजिंग उद्योगों में पतली फिल्मों के अनुप्रयोगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

प्रमुख बिंदु

- ये फिल्में अन्य प्रोटीन या प्लास्टिक फिल्मों की तुलना में काफी पतली होती हैं।
- वे नरम और पतले होते हैं और अन्य फिल्मों की तुलना में अधिक लचीले होने का फायदा होता है।
- इन अल्ट्राथिन मोनोलेयर प्रोटीन फिल्मों में दो गोलाकार प्रोटीन होते हैं: गोजातीय सीरम एल्ब्यूमिन (BSA) और लाइसोजाइम (LIS)।
- उन्होंने लैंगमुइर-ब्लॉडगेट (LB) तकनीक का उपयोग करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया जो फिल्मों को नैनोमीटर के क्रम में मोटाई देता है।
- BSA और LIM के ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फिल्में अत्यधिक स्थिर बायोडिग्रेडेबल पतली फिल्म के निर्माण के लिए उपयोगी हो सकती हैं।

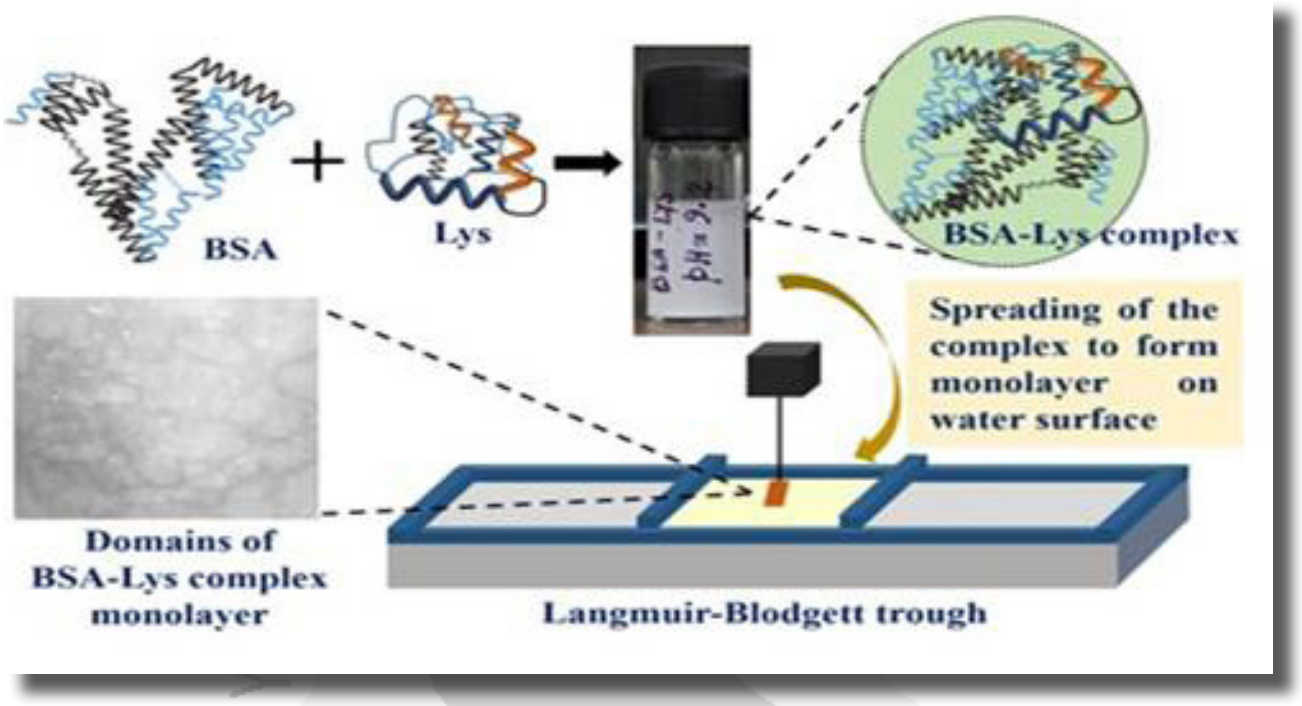

इंडियन ऑयल का सूर्य नूतन इनडोर सोलर कुकिंग सिस्टम

इंडियन ऑयल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक स्वदेशी सोलर कुक टॉप "सूर्य नूतन" विकसित किया है।

- सूर्य नूतन एक स्थिर, रिचार्जेबल और हमेशा रसोई से जुड़ा इनडोर सोलर कुकिंग है।

प्रमुख बिंदु

- सूर्य नूतन इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र, फरीदाबाद द्वारा डिजाइन और विकसित एक पेटेंट उत्पाद है।
- यह सूर्य के माध्यम से चार्ज करते समय ऑनलाइन खाना पकाने का तरीका प्रदान करता है जो सिस्टम दक्षता को अधिकतम करता है और सूर्य से ऊर्जा का उच्च उपयोग सुनिश्चित करता है।

RAO'S ACADEMY

- यह एक हाइब्रिड मोड पर भी काम करता है (अर्थात सौर और सहायक ऊर्जा स्रोत दोनों पर एक साथ काम कर सकता है)।
  - ♦ यह सूर्य नूतन को सभी मौसमों के लिए एक विश्वसनीय खाना पकाने का समाधान बनाता है।
- सूर्य नूतन का इन्सुलेशन डिजाइन विकिरण और प्रवाहकीय गर्मी के नुकसान को कम करता है।
- सूर्य नूतन तीन अलग-अलग मॉडलों में उपलब्ध है।
- शुरुआत में, बेस मॉडल के लिए उत्पाद की लागत लगभग 12,000 रुपये और टॉप मॉडल के लिए 23,000 रुपये है।

- हालांकि, पैमाने की किफायत के साथ लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है।
- टॉप मॉडल के लिए 12,000-14,000/- रुपये की कीमत पर, 6-8 एलपीजी सिलेंडर की वार्षिक खपत को मानते हुए, यह उत्पाद खरीदार को पहले 1-2 वर्षों में ही वापस भुगतान कर सकता है।
- यह एक मॉड्यूलर प्रणाली है और इसे आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकारों में डिजाइन किया जा सकता है।

सी-डॉट ने जालोर नेटवर्क्स के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए

सी-डॉट और गैलोर नेटवर्क्स ने एंड-टू-एंड 5जी आरएएन उत्पादों और समाधानों के सहयोगात्मक विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह 5G के स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए है।

प्रमुख बिंदु

- टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी-डॉट) स्वदेशी 5जी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न हितधारकों के साथ मजबूत साझेदारी बनाने का इच्छुक है।
- यह भारतीय अनुसंधान एवं विकास और उद्योग की तकनीकी दक्षताओं और पूरक शक्तियों को एक एकीकृत मंच पर लाएगा।
- इसके बदले में स्वदेशी बौद्धिक संपदा (IP) परिसंपत्तियों का निर्माण होगा।

यह वैश्विक स्तर पर घरेलू प्रौद्योगिकियों की व्यापक पहुंच और व्यावसायीकरण के लिए नए रास्ते पैदा कर सकता है।

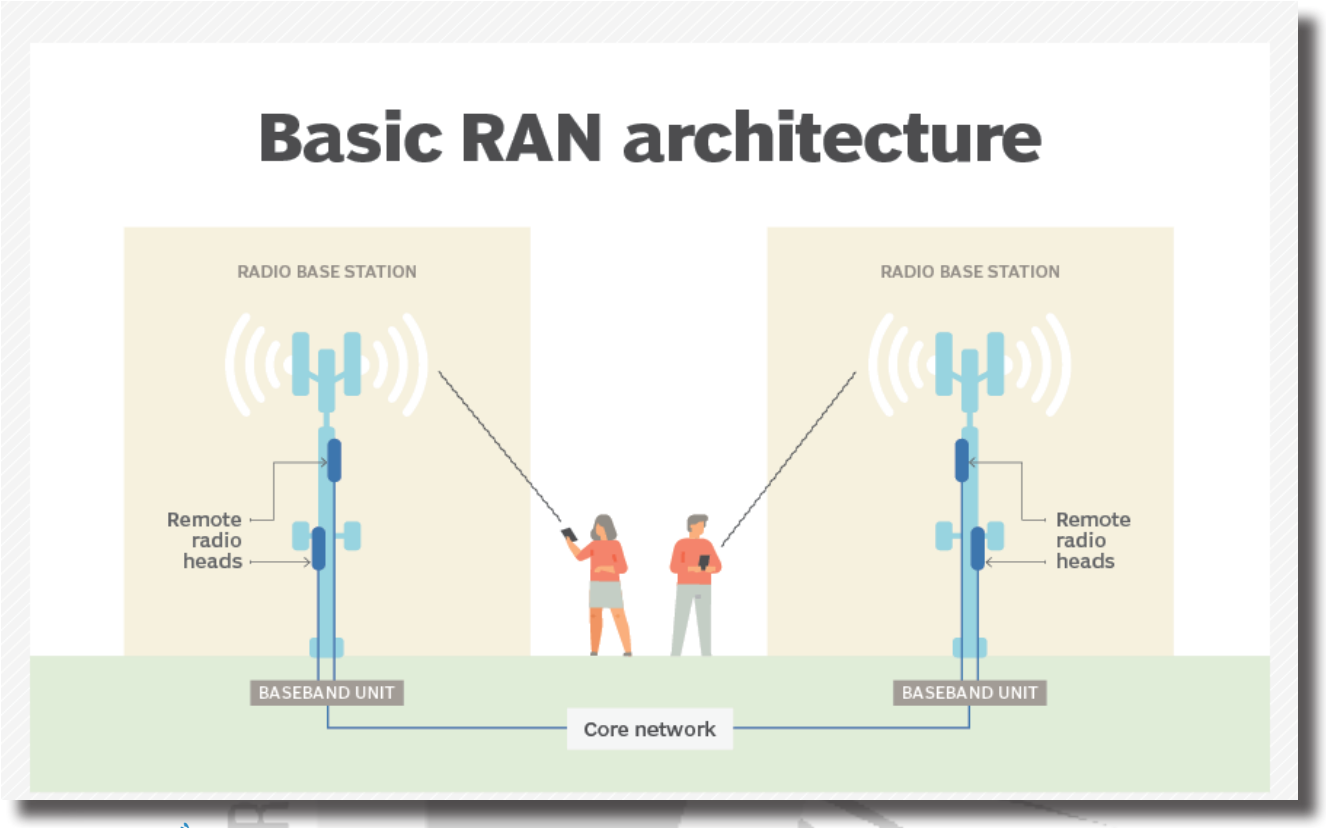

RAN क्या है?

- एक रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) रेडियो कनेक्शन के माध्यम से व्यक्तिगत उपकरणों को नेटवर्क के अन्य भागों से जोड़ता है।
- RAN उपयोगकर्ता उपकरण, जैसे सेलफोन, कंप्यूटर या कोई दूर से नियंत्रित मशीन, को फाइबर या वायरलेस बैकहॉल कनेक्शन से जोड़ता है।
- यह आधुनिक दूरसंचार का एक प्रमुख घटक है जिसमें मोबाइल नेटवर्किंग की विभिन्न पीढ़ियां 1G से 5G तक विकसित हो रही हैं।
- RAN में एक बेस स्टेशन और एंटेना शामिल होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र को उसकी क्षमता, डिजाइन और प्रसार के अनुसार कवर करते हैं।

सी-डॉट के बारे में

टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी-डॉट) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय का प्रमुख अनुसंधान एवं विकास केंद्र है।

- सी-डॉट ने विभिन्न अत्याधुनिक दूरसंचार प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है।
- सी-डॉट ने अपना स्वदेशी 4जी समाधान विकसित किया है और 5जी के क्षेत्र में उत्सुकता से काम कर रहा है।

RAO'S ACADEMY

6 सामाजिक मुद्दे

सहकारिता का 100वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस

2 जुलाई को, दुनिया भर की सहकारिताएं सहकारिता का 100वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस (सहकारिता दिवस) मनाएंगी।

- इस वर्ष का #CoopsDay नारा है – "सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है"।

प्रमुख बिंदु

- यह वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा के एक दशक का प्रतीक है।
- सहकारिता मंत्रालय और NCUI "सहकारिता एक आत्मानिर्भर भारत और एक बेहतर दुनिया का निर्माणष विषय के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।
- भारत में विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन है।
- 8.5 लाख से अधिक के नेटवर्क के साथ 90 प्रतिशत गांवों में सहकारिता अब भारत में प्रमुख संस्थाएं हैं।
- भारत में कुछ प्रसिद्ध सहकारी सफलता की कहानियों में अमूल, इफको, कृभको, नेफेड और अन्य शामिल हैं।
- केंद्र सरकार ने भी सहकारिता क्षेत्र को उचित गति प्रदान करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की थी।

एक सहकारी क्या है?

एक सहकारिता को व्यक्तियों के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।

- सहकारिता स्व-सहायता, स्व-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, समानता और एकजुटता के मूल्यों पर आधारित है।
- तो, यह आम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों का एक सदस्य-संचालित और लोकतांत्रिक रूप से स्व-प्रबंधित संघ है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

भारत में सहकारी आंदोलन का इतिहास

- भारत में सहकारिता आंदोलन का जन्म 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में व्याप्त संकट और उथल-पुथल से हुआ था।
- औद्योगिक क्रांति ने ग्रामोद्योगों को बरबादी का झटका दिया था।
- औपचारिक सहकारी ढांचे के अस्तित्व में आने से पहले भी एक कानून पारित किया गया था-
  - ♦ सहयोग और सहकारी गतिविधियों की अवधारणा की प्रथा भारत के कई हिस्सों में प्रचलित थी।
- सहकारी समितियों के प्रारंभिक रूप दक्षिणी भारत में निधियों और चिट फंडों का संगठन थे।
- यह भी दर्ज है कि 1892 में सर फ्रेडरिक निकोलसन को यूरोप में सहकारी समितियों के ढांचे का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था।
- उन्होंने ही रायफिसेन नामक जर्मन पद्धति को अपनाते हुए ग्रामीण सहकारी साख समितियों के गठन की सिफारिश की थी।
- तब भारत सरकार द्वारा सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 के अधिनियमन के साथ प्राथमिक ऋण समितियों का भी गठन किया गया था।
- सहकारी समिति अधिनियम 1912 के साथ सरकार ने देश में गैर-ऋण समितियों और संघीय सहकारी संगठनों का भी गठन किया।
- 1915 में, सर एडवर्ड मैकलागन की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई थी।
  - ♦ उद्देश्य: यह अध्ययन करना और रिपोर्ट करना कि क्या सहकारिता आंदोलन मितव्ययता और आर्थिक रूप से सुदृढ़ आधार पर आगे बढ़ रहा था।
- भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार, सहकारी समितियां एक स्थानांतरित विषय में बदल गईं।
  - ♦ कई प्रांतों ने अपने स्वयं के सहकारी समिति अधिनियम को अधिनियमित करना शुरू कर दिया।
- फिर से, भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ, ये सहकारी समितियां राज्य की विषय वस्तु बन गईं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समिति (AIRCC) की नियुक्ति की जिसने वर्ष 1954 मंर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- समिति ने ग्राम सोसायटियों की आर्थिक व्यवहार्यता के उत्थान की दृष्टि से संचालन के व्यापक क्षेत्रों की सिफारिश की।

सहकारिता के संवैधानिक प्रावधान

संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगरपा. लिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा।

- "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (भाग IV) में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया।
- "सहकारिता" शब्द संविधान के भाग III के तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में "यूनियन और संघों" के बाद जोड़ा गया था।

कोई सेवा शुल्क नहीं

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

- यह होटल और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में है।

प्रमुख बिंदु

- सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से या

डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे।

- सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से नहीं की जाएगी।
- कोई भी होटल या रेस्तरां किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है।
- सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाएगा।
- खाद्य बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर GST लगाकर सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है–

फिर उपभोक्ता बिल की राशि से सर्विस चार्ज हटाने के लिए संबंधित होटल या रेस्तरां से अनुरोध कर सकता है।

- साथ ही, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर शिकायत दर्ज करा सकता है।
  - ♦ एनसीएच 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्व-मुकदमेबाजी स्तर पर वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में काम करता है।
- उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है।

इसके त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल www-e&daakhil-nic-in के माध्यम से भी शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के बारे में

प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10(1) के तहत किया गया है।

- सीसीपीए उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करेगा।
- सीसीपीए में एक महानिदेशक की अध्यक्षता में एक जांच विंग होगा, जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या जांच कर सकता है।
- **कार्य:**
  - ♦ उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, छानबीन और उचित मंच पर अभियोजन शुरू करना;
  - ♦ सामान वापस लेने या खतरनाक सेवाओं को वापस लेने के आदेश पारित करना, भुगतान की गई कीमत की प्रतिपूर्ति, और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करना, जैसा कि बिल में परिभाषित किया गया है;
  - ♦ संबंधित व्यापारी/निर्माता/अनुमोदक/विज्ञापनदाता/प्रकाशक को किसी झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने, या इसे संशोधित करने के लिए निर्देश जारी करना;

RAO'S ACADEMY

- ♦ दंड लगाना, और;
- ♦ असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के खिलाफ उपभोक्ताओं को सुरक्षा नोटिस जारी करना।

- सीसीपीए झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माता या समर्थनकर्ता पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की कैद लगा सकता है। बाद के अपराध के मामले में, जुर्माना 50 लाख रुपये तक और पांच साल तक की कैद हो सकती है।
- सीसीपीए भ्रामक विज्ञापन के समर्थनकर्ता को एक वर्ष तक की अवधि के लिए उस विशेष उत्पाद या सेवा का समर्थन करने से भी रोक सकता है।
- उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग:
  - ♦ जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRCs) भी स्थापित किए गए हैं।

एक उपभोक्ता कौन है?

- उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी वस्तु को खरीदता है या प्रतिफल के लिए किसी सेवा का लाभ उठाता है।
- इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनर्विक्रय के लिए वस्तु या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कोई वस्तु या सेवा प्राप्त करता है।
- यह ऑफलाइन, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों, टेलीशॉपिंग, मल्टी-लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ऑनलाइन सहित सभी तरीकों से लेनदेन को कवर करता है।

भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन

पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में NASC परिसर में आयोजित किया गया था।

- लक्ष्य देश के खाद्य और पोषण सुरक्षा, ग्रामीण आय और समृद्धि, और समग्र आर्थिक विकास के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया।
- खाद्य सुरक्षा, पोषण और समग्र स्थिरता के संदर्भ में, पशु और पशु उत्पाद देश के विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं।
- देश में कुल पशुधन संख्या 535.78 मिलियन है, जो 2012 की पशुधन गणना से 4.6 प्रतिशत अधिक है।
- 2019 में कुल गोजातीय आबादी 302.79 मिलियन थी, जो पिछली जनगणना से 1.0 प्रतिशत अधिक है।
- भारत में सबसे ज्यादा मवेशी हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, लेकिन प्रति पशु उत्पादकता कम रहती है।
- कम उत्पादकता विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पशु स्वास्थ्य है, जिसका उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के बीच जटिल अंत:क्रियाओं के परिणामस्वरूप जूनोटिक रोग वैश्विक स्वास्थ्य खतरों के रूप में उभरे हैं।
- पशुओं में रोग की निगरानी में शीघ्र निदान के माध्यम से मनुष्यों की रक्षा करने का अतिरिक्त लाभ होता है।
- पशु स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने और राज्यों में सरकारी प्रयासों को बढ़ाने के लिए,
  - ♦ एक स्थायी पशु स्वास्थ्य क्षेत्र बनाने के लिए इस तरह के आयोजन का आयोजन किया जा रहा है।

22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया।

- हर साल 10 जुलाई को देश भर के सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है।

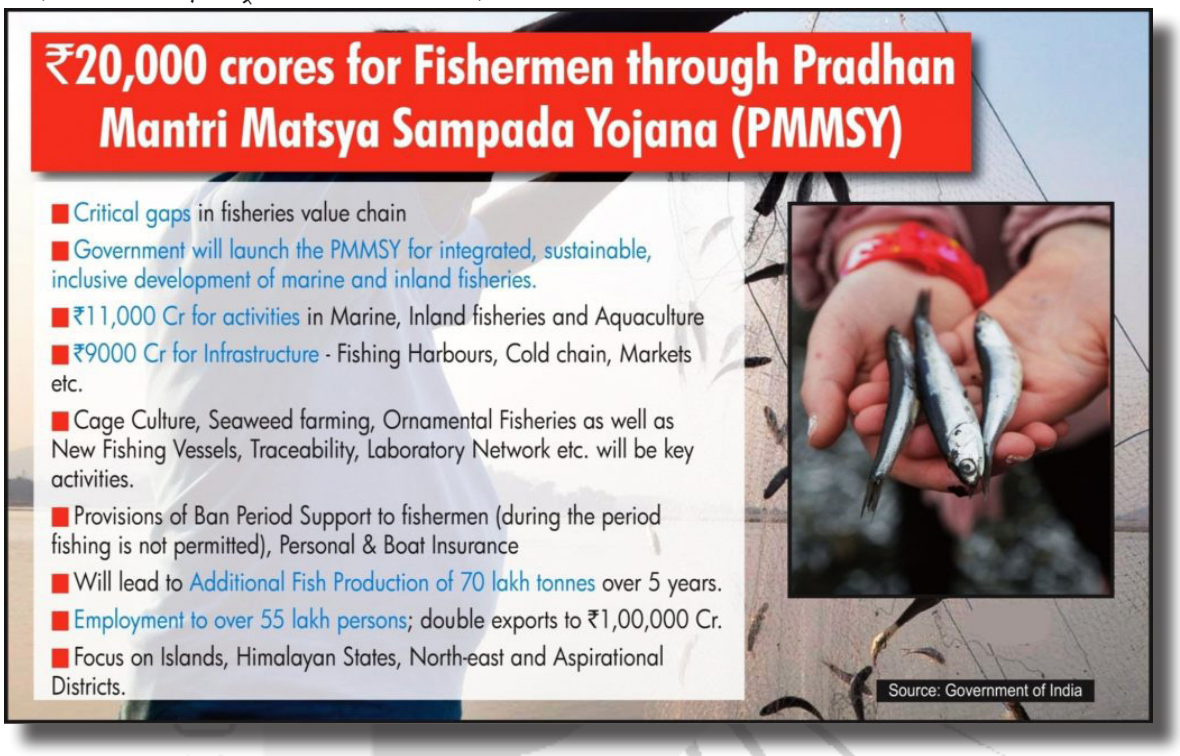

प्रमुख बिंदु

- यह वार्षिक कार्यक्रम प्रोफेसर डॉ हीरालाल चौधरी और उनके सहयोगी डॉ अलीकुन्ही को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
- उन्होंने 10 जुलाई 1957 को ओडिशा के अंगुल में देश में पहली बार प्रमुख कार्प के सफल प्रेरित प्रजनन को प्राप्त करने में मदद की।
- यह मेजर कार्प्स के प्रजनन में कार्प पिट्यूटरी हार्मोन के अर्क के प्रशासन के माध्यम से किया गया था।
- बाद में, पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन के लिए सिंथेटिक हार्मोन विकसित करके प्रौद्योगिकी को मानकीकृत और परिष्कृत किया गया।
- वर्षों से, प्रेरित प्रजनन में इस अग्रणी कार्य ने जलीय कृषि क्षेत्र के विकास को पारंपरिक से गहन जलीय कृषि प्रथाओं में बदल दिया है। इस प्रकार, आधुनिक जलीय कृषि उद्योग की सफलता के परिणामस्वरूप।
- भारत सरकार नीली क्रांति लाने का प्रयास कर रही है।

नीली क्रांति क्या है?

- नीली क्रांति, नील क्रांति मिशन में देश और मछुआरों और मछली किसानों की आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का दृष्टिकोण है।
    - ♦ इसका उद्देश्य सतत रूप से मत्स्य विकास के लिए जल संसाधनों के पूर्ण संभावित उपयोग के माध्यम से खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करना है।
- **उद्देश्य**

आर्थिक समृद्धि के लिए जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से समग्र मछली उत्पादन में वृद्धि करना।

- ♦ नई तकनीकों पर विशेष ध्यान देते हुए मात्स्यिकी का आधुनिकीकरण करना।
- ♦ खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ♦ रोजगार और निर्यात आय उत्पन्न करने के लिए।
- ♦ समावेशी विकास सुनिश्चित करना और मछुआरों और जलीय कृषि किसानों को सशक्त बनाना।

- भारत सरकार ने मई, 2020 में "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)" को मंजूरी दी।
  - ♦ मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना।
  - ♦ इस योजना में 20050 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय अब हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन करेगा।

- इसका उद्देश्य युवाओं को कॉरपोरेट्स के भीतर ऑन-ग्राउंड प्रशिक्षण के अधिक अवसरों से जोड़ना और रोजगार पाने का एक मौका देना है।

प्रमुख बिंदु

- पीएम राष्ट्रीय शिक्षुता मेला भारत में 200 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।
- 36+ क्षेत्रों की 1000 से अधिक कंपनियां मेले में भाग लेंगी, जो कंपनियों के भीतर एक प्रशिक्षु के रूप में काम पर रखने के अवसर प्रदान करेंगी।
- निम्नलिखित वाले व्यक्ति इन ट्रेडों/अवसरों में साक्षात्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं:
  - ♦ 5वीं-12वीं कक्षा पास प्रमाणपत्र,
  - ♦ एक कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र,
  - ♦ एक आईटीआई डिप्लोमा,
  - ♦ स्नातक की डिग्री।
- उम्मीदवारों को 500 + ट्रेडों का विकल्प दिया जाएगा, जिसमें वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटीशियन, मैकेनिक और अन्य शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य इन शहरों से प्रशिक्षुओं की भर्ती को प्रोत्साहित करना है।
- साथ ही, यह नियोक्ताओं को प्रशिक्षण और व्यावहारिक कौशलों के माध्यम से उनकी क्षमता को पहचानने और विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा जो उनके कार्यस्थल पर मूल्य लाएंगे।
- उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षुता प्रमाणपत्र भी प्राप्त होगा।
- मेलों में भाग लेने वाले संगठनों को एक साझा मंच पर संभावित प्रशिक्षुओं से मिलने और मौके पर ही उम्मीदवारों का चयन करने का अवसर मिलता है।
- इसके अलावा, कम से कम चार कर्मचारियों वाले लघु उद्योग इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को नियुक्त कर सकते हैं।
- जल्द ही एक क्रेडिट बैंक अवधारणा भी पेश की जाएगी।
  - ♦ यह शिक्षार्थियों द्वारा जमा किए गए विभिन्न क्रेडिट का एक डिपॉजिटरी होगा जिसका उपयोग भविष्य के शैक्षणिक मार्गों के लिए किया जा सकता है।

eNAM के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (POP) लॉन्च किया गया

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म (POP) लॉन्च किया।

- पीओपी की शुरुआत से किसानों को अपने राज्य की सीमाओं के बाहर उत्पाद बेचने में सुविधा होगी।

प्रमुख बिंदु

- इससे कई बाजारों, खरीदारों और सेवा प्रदाताओं तक किसानों की डिजिटल पहुंच बढ़ेगी।
- यह मूल्य खोज तंत्र और गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य प्राप्ति में सुधार के उद्देश्य से व्यावसायिक लेनदेन में पारदर्शिता लाने में भी मदद करेगा।
- विभिन्न प्लेटफॉर्मों के 41 सेवा प्रदाता पीओपी के अंतर्गत आते हैं।
- विभिन्न मूल्य श्रृंखला सेवाएं शामिल हैं जैसे व्यापार, गुणवत्ता जांच, भंडारण, फिनटेक, बाजार की जानकारी, परिवहन आदि।
- पीओपी एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा, जो कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न खंडों में विभिन्न प्लेटफार्मों की विशेषज्ञता से लाभान्वित होगा।
- e-NAM सेवा प्रदाताओं के प्लेटफॉर्म को "प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म" के रूप में एकीकृत करता है।
- **इस एकीकरण में शामिल हैं:**
  - ♦ समग्र सेवा प्रदाता (सेवा प्रदाता जो गुणवत्ता विश्लेषण, व्यापार, भुगतान प्रणाली और रसद सहित कृषि उपज

के व्यापार के लिए समग्र सेवाएं प्रदान करते हैं),

- ♦ रसद सेवा प्रदाता,
- ♦ गुणवत्ता आश्वासन सेवा प्रदाता,
- ♦ सफाई, ग्रेडिंग, छँटाई और पैकेजिंग सेवा प्रदाता,
- ♦ वेयरहाउसिंग सुविधा सेवा प्रदाता,
- ♦ कृषि इनपुट सेवा प्रदाता,
- ♦ प्रौद्योगिकी समर्थित वित्त और बीमा सेवा प्रदाता,
- ♦ सूचना प्रसार पोर्टल (सलाहकार सेवाएं, फसल पूर्वानुमान, मौसम अद्यतन, किसानों के लिए क्षमता निर्माण आदि)
- ♦ अन्य प्लेटफॉर्म (ई-कॉमर्स, अंतरराष्ट्रीय कृषि-व्यवसाय प्लेटफॉर्म, वस्तु विनिमय, निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि)।

- विभिन्न सेवा प्रदाताओं को शामिल करने से न केवल ई-नाम प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि होती है;
  - ♦ लेकिन विभिन्न सेवा प्रदाताओं से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को विकल्प भी देता है।
- यह किसानों, एफपीओ, व्यापारियों और अन्य हितधारकों को एकल खिड़की के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है।
- पीओपी को ई-नाम मोबाइल एप के जरिए एक्सेस किया जा सकता है जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

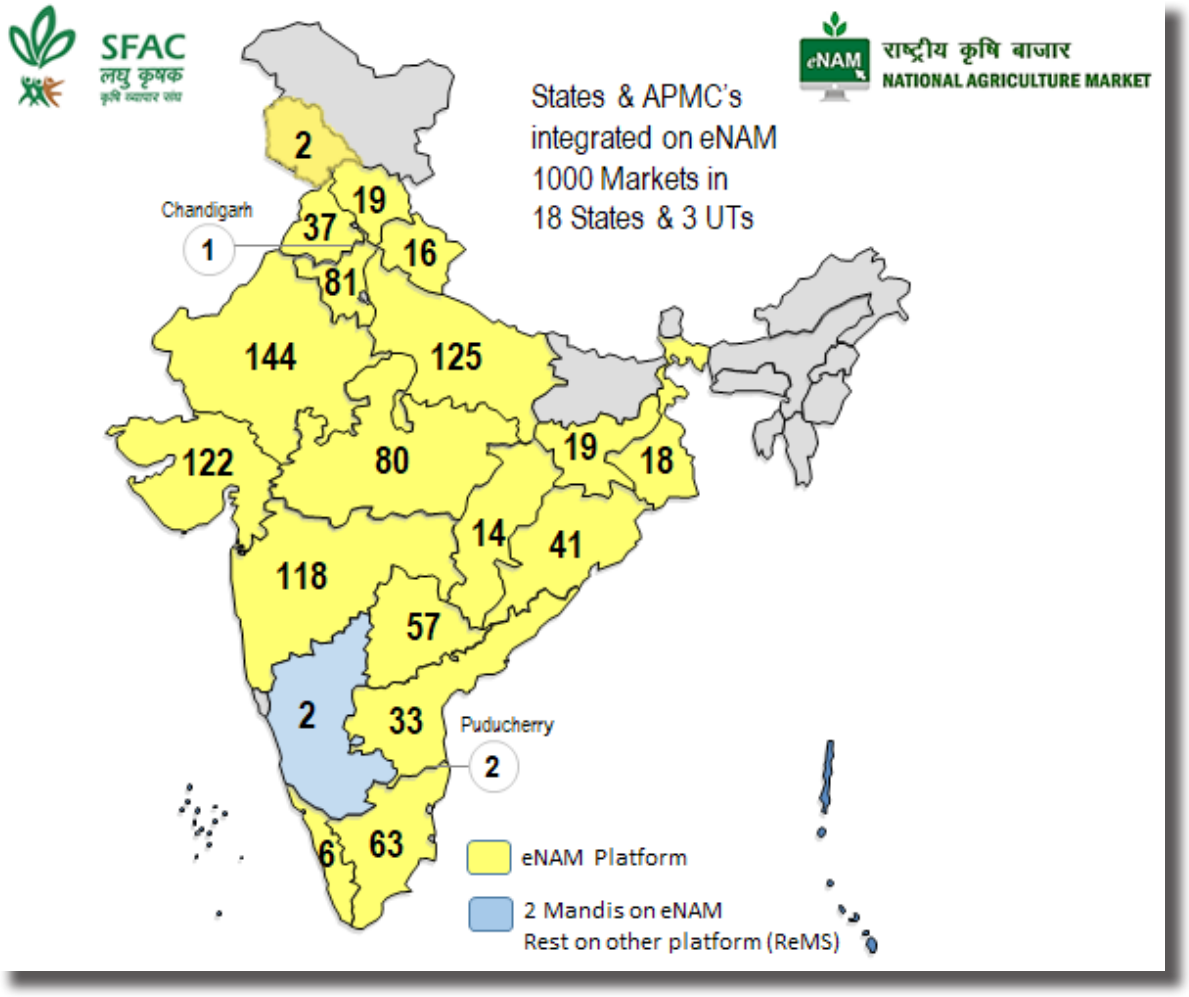

e&NAM क्या है?

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क करता है।

- लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में e-NAM को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
- **दृष्टि: कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना-**
  - ♦ एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके,
  - ♦ खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करके,
  - ♦ वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य खोज को बढ़ावा देना।
- मिशन: एक आम ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से देश भर में APMC का एकीकरण-
  - ♦ कृषि वस्तुओं में अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिए,
  - ♦ समय पर ऑनलाइन भुगतान के साथ-साथ उपज की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बेहतर कीमत की खोज प्रदान करना।

बागवानी उत्पादन

कृषि और किसान कल्याण विभाग ने 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया।

- इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य सरकारी स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित किया जाता है।

Total Horticulture	2020-21 (Final)	2021-22 (1st Adv. Est.)	2021-22 (2nd Adv. Est.)
Area(in Million Ha)	27.48	27.56	27.74
Production(in Million Tonne)	334.60	333.25	341.63

प्रमुख बिंदु

- 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 341.63 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 की तुलना में लगभग 7.03 मिलियन टन (2.10%) की वृद्धि है।
- फलों, सब्जियों और शहद के उत्पादन में वृद्धि।
  - ♦ पिछले वर्ष की तुलना में मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है।

मरम्मत के अधिकार पर रूपरेखा (राइट टू रिपेयर)

उपभोक्ता मामले विभाग ने मरम्मत के अधिकार पर व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए समिति का गठन किया।

- यह टिकाऊ खपत के माध्यम से जीवन शैली (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) आंदोलन पर जोर देने के लिए किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में राइट टू रिपेयर पर एक ढांचा विकसित करने का उद्देश्य है:
  - ♦ स्थानीय बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पाद खरीदारों को सशक्त बनाने के लिए,

- ♦ मूल उपकरण निर्माताओं और तीसरे पक्ष के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करना,
- ♦ उत्पादों की सतत खपत को विकसित करने पर जोर देना,
- ♦ ई-कचरे में कमी।

- एक बार इसे भारत में रोल आउट करने के बाद, यह गेम-चेंजर बन जाएगा।
  - ♦ यह उत्पादों की स्थिरता प्रदान करेगा।
  - ♦ तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति देकर आत्मानिर्भर भारत के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करें।

समिति द्वारा उठाए गए मुद्दे

- जिन प्रासंगिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया उनमें यह शामिल है कि कंपनियां मैनुअल के प्रकाशन से बचती हैं जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से रिपेयर करने में मदद कर सकती हैं।
- स्पेयर पार्ट्स पर निर्माताओं का मालिकाना नियंत्रण होता है (स्क्रू और अन्य के लिए वे जिस तरह के डिजाइन का उपयोग करते हैं उसके संबंध में)।
- मरम्मत प्रक्रियाओं पर एकाधिकार ग्राहक के "चुनने के अधिकार" का उल्लंघन करता है।
- डिजिटल वारंटी कार्ड, उदाहरण के लिए, यह सुनिश्चित करते हैं कि "गैर-मान्यता प्राप्त" संगठन से उत्पाद प्राप्त करने से, ग्राहक वारंटी का दावा करने का अधिकार खो देता है।
- निर्माता 'नियोजित अप्रचलन' की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी गैजेट का डिजाइन ऐसा होता है कि वह एक विशेष समय तक ही चलता है।
  - ♦ उस विशेष अवधि के बाद इसे अनिवार्य रूप से बदलना होगा।

समाधान के लिए सुझाव

- तकनीकी कंपनियों को मैनुअल, स्कीमैटिक्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए पूर्ण ज्ञान और पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- नैदानिक उपकरणों सहित सेवा उपकरणों के पुर्जे और उपकरण व्यक्तियों सहित तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- " राइट टू रिपेयर " के पीछे तर्क यह है कि जब हम कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हमें उसका पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए।

ऐसा होने के लिए उपभोक्ताओं को आसानी से और उचित कीमत पर उत्पाद की मरम्मत और संशोधन करने में सक्षम होना चाहिए। वह भी मरम्मत के लिए निर्माताओं की सनक के अधीन हुए बिना।

नोट: यू.एस.ए., यू.के. और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के कई देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है।

मिशन शक्ति

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'मिशन शक्ति' योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- मिशन शक्ति योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण के लिए 'मिशन शक्ति' - एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की छत्र योजना शुरू की है।

- 'मिशन शक्ति' मिशन मोड में एक योजना है जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, बचाव और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है।
- 'मिशन शक्ति' की दो उप-योजनाएं हैं - 'संबल' और 'समर्थ'।
- जहां "संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वहीं "समर्थ" उप-योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है।
- 'संबल' उप-योजना के घटकों में पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल हैं जैसे:
  - ♦ वन स्टॉप सेंटर (OSC),
  - ♦ महिला हेल्पलाइन (WHL),
  - ♦ बेटी बचाओ-बेटी पढाओ (BB-BP),
  - ♦ नारी अदालतों का एक नया घटक - समाज में और परिवारों के भीतर वैकल्पिक विवाद समाधान और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने के लिए महिला समूह।
- 'समर्थ्य' उप-योजना के घटकों में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
  - ♦ उज्जवला,

RAO'S ACADEMY

- ♦ स्वाधार गृह,
- ♦ कामकाजी महिला छात्रावास को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है।
- ♦ इसके अलावा, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना की मौजूदा योजनाएं,
- ♦ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) को छत्र ICDS के तहत अब समर्थ में शामिल किया गया है।
- ♦ आर्थिक अधिकारिता के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक भी समर्थ योजना में जोड़ा गया है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) - वार्षिक रिपोर्ट

एनएसओ द्वारा चौथी वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2020-जून 2021 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर लाई जा रही है।

- इन सर्वेक्षणों में सामान्य स्थिति (PS+SS) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) दोनों में रोजगार और बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मानकों का अनुमान शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- इससे पहले, रोजगार और बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का अनुमान देते हुए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करते हुए तीन वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई थी।
- ये तीन वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2017- जून 2018, जुलाई 2018-जून 2019 और जुलाई 2019-जून 2020 के दौरान पीएलएफएस में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर लाई गई थीं।

महत्वपूर्ण अवधारणाएं

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):
  - ♦ LFPR को जनसंख्या में श्रम बल (अर्थात काम करने वाले या तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध) में व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):
  - ♦ WPR को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- बेरोजगारी दर (UR):
  - ♦ UR को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- गतिविधि स्थिति- सामान्य स्थिति:

- ♦ किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति उस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- ♦ जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित की जाती है-
- ♦ फिर, इसे व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति के रूप में जाना जाता है।

- गतिविधि की स्थिति- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस):
  - ♦ सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि पर निर्धारित गतिविधि की स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता है।
- प्रधान गतिविधि की स्थिति-
  - ♦ गतिविधि की स्थिति जिस पर एक व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तारीख से पहले के 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (मुख्य समय मानदंड) बिताया।
- सहायक आर्थिक गतिविधि की स्थिति-

गतिविधि की स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी सामान्य प्रमुख स्थिति के अलावा, सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के लिए 30 दिनों या उससे अधिक के लिए कुछ आर्थिक गतिविधि करता है।

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

- कम से कम माध्यमिक शिक्षा के साथ 25 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या का प्रतिशत- 50.2%।
- सामान्य स्थिति (ps+ss) में श्रम शक्ति में 15-64 वर्ष की महिला का सामान्य स्थिति में श्रम बल में 15-64 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का अनुपात (ps+ss) - 29.8%।
- विधायिका, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधकों के रूप में कार्यरत सामान्य स्थिति (PS+SS) में महिला कामगारों का अनुपात- 22.2%।
- पेशेवर और तकनीकी कामगारों के रूप में काम करने वाली सामान्य स्थिति (PS+SS) में महिला कामगारों का पुरुष कामगारों से अनुपात- 50.4%।
- प्रबंधकीय पदों पर कार्यरत सामान्य स्थिति (PS+SS) में कुल कामगारों से महिला कामगारों का अनुपात- 18.0%।
- कुल नियोजित महिलाओं में उन्नत डिग्री के साथ कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत- 2.4%।
- ज्ञान प्रधान रोजगार में सामान्य स्थिति (PS+SS) में कामगारों का प्रतिशत- 15.7%।
- सामान्य स्थिति (PS+SS) में वेतनभोगी और वेतनभोगी महिला कामगारों का सामान्य स्थिति में वेतनभोगी और वेतनभोगी पुरुष कामगारों से अनुपात (PS+SS)- 0.9.
- सामान्य स्थिति (PS+SS) में श्रम बल में 15 से 64 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रतिशत का अनुपात समान स्थिति में पुरुषों के प्रतिशत से - 0.4।

भारत में प्रवास, 2020-2021

भारत में प्रवासन, 2020-2021 रिपोर्ट में जुलाई 2020- जून 2021 के दौरान PLFS में एकत्रित जानकारी के आधार पर संकेतकों के अनुमान शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में कुछ अतिरिक्त जानकारी शामिल है जो प्रवासन से संबंधित थी।
- ये अतिरिक्त आंकड़े निम्नलिखित पहलुओं पर एकत्र किए गए:
  - ♦ परिवार के सदस्यों के प्रवास विवरण की जानकारी।
  - ♦ मार्च 2020 के बाद घर में आने वाले अस्थायी आगंतुकों की जानकारी और लगातार 15 दिन या उससे

अधिक लेकिन 6 महीने से कम की अवधि के लिए घर में रहा।

महत्वपूर्ण अवधारणाएं

- सामान्य निवास स्थान (UPR):
  - ♦ किसी व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान (UPR) वह स्थान (गांव/कस्बा) होता है, जहां व्यक्ति कम से कम छह महीने से लगातार रह रहा हो।
  - ♦ यदि कोई व्यक्ति छह माह से लगातार गांव/कस्बे में नहीं रह रहा था, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान वहां लगातार छह महीने या उससे अधिक समय तक रहने के इरादे से वहां रहता पाया गया तो वह स्थान उसकी यूपीआर के रूप में था।
- **प्रवासी:**
  - ♦ घर का एक सदस्य जिसका अंतिम सामान्य निवास स्थान, अतीत में किसी भी समय, गणना के वर्तमान स्थान से भिन्न था।
  - ♦ ऐसे व्यक्ति को घर में प्रवासी सदस्य माना जाता है।
- **प्रवासन दर:**

किसी भी श्रेणी के व्यक्ति (जैसे, ग्रामीण या शहरी, पुरुष या महिला) के लिए प्रवासन दर, उस श्रेणी के व्यक्तियों से संबंधित प्रवासियों का प्रतिशत है।

- **अस्थायी आगंतुक:**
  - ♦ घर में अस्थायी आगंतुक वे हैं जो मार्च 2020 के बाद आए और लगातार 15 दिन या उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम की अवधि के लिए घर में रहे।

महत्वपूर्ण डेटा

व्यक्तियों की श्रेणी ग्रामीण शहरी ग्रामीण+शहरी

- ♦ पुरुष 5.9 22.5 10.7
- ♦ महिला 48.0 47.8 47.9
- ♦ पुरुष + महिला 26.5 34.9 28.9

- जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच कुल 48.9 प्रतिशत अस्थायी आगंतुक परिवार/रिश्तेदारों/दोस्तों से मिलने चले गए।

ऐसे 15.7 प्रतिशत अस्थायी आगंतुक स्वास्थ्य संबंधी कारणों से चले गए।

- ♦ 12.2 अस्थायी आगंतुकों का प्रतिशत नौकरी छूटने/इकाई बंद होने/रोजगार के अवसरों की कमी के कारण स्थानांतरित हुआ

- देश की आबादी का 0.7 प्रतिशत घरों में 'अस्थायी आगंतुक' के रूप में दर्ज किया गया था।
  - ♦ यानी 85 लाख 'अस्थायी आगंतुक' घरों में।
- जुलाई 2020-जून 2021 के लिए अखिल भारतीय प्रवास दर 28.9 प्रतिशत थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 34.9 प्रतिशत प्रवास था।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 48 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 47.8 प्रतिशत के साथ महिलाओं ने प्रवासन दर में 47.9 प्रतिशत की उच्च हिस्सेदारी दर्ज की।
- पुरुषों के लिए प्रवासन दर 10.7 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 5.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 22.5 प्रतिशत के साथ देखी गई।
- महिलाओं में, विवाह के लिए प्रवास दर का उच्चतम स्तर 86.8 प्रतिशत देखा गया, जबकि 49.6 प्रतिशत पुरुष

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAU'S ACADEMY

रोजगार की तलाश में पलायन कर गए।

- परिवार के माता-पिता/कमाऊ सदस्य के प्रवास के कारण 9.2 प्रतिशत व्यक्ति पलायन कर गए, इस कारण 17.5 प्रतिशत पुरुष और 7.3 प्रतिशत महिलाएं पलायन कर गईं।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने श्जागृतिश की शुरुआत की

उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर "जागृति" लॉन्च की है।

- जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैला रहा है और समस्या का समाधान कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- विभाग के विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए "जागृति" शुभंकर का उपयोग किया जाएगा।
- इन विषयों में इस तरह के मामले शामिल होंगे:
  - ♦ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान,
  - ♦ हॉलमार्किंग,
  - ♦ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915,
  - ♦ बाट और माप अधिनियम के प्रावधान,
  - ♦ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय
  - ♦ शिकायत निवारण पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रशंसापत्र।
- जागृति शुभंकर लाकर, DoCA का लक्ष्य डिजिटल दुनिया में भी अपने उपभोक्ता जागरूकता अभियान की उपस्थिति को मजबूत करना है।
- जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन "जागो ग्राहक जागो" के साथ दिखाया जाएगा।

उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2022

केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने भारत रैंकिंग 2022 जारी की।

- मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग के लिए एक मजबूत और वस्तुनिष्ठ ढांचा उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में गुणवत्ता बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

प्रमुख बिंदु

रैंकिंग प्रणाली के कुछ मुख्य आकर्षण और कुछ संभावित परिवर्तन:

- प्रत्यायन और मूल्यांकन अनिवार्य होगा, और प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का प्रत्यायन होना आवश्यक है।
  - ♦ स्व-घोषणा और पारदर्शिता मूल्यांकन और प्रत्यायन का आधार होगी।
- सभी संस्थान भी एनआईआरएफ रैंकिंग प्रणाली का हिस्सा होंगे।
- अगले वर्ष तक शिक्षा मंत्रालय नैक द्वारा वर्तमान में किए जा रहे संस्थागत मान्यता और एनबीए द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यक्रम प्रत्यायन को एकीकृत करेगा।
  - ♦ AICTE द्वारा पहले किए गए नवाचार पर रैंकिंग को अब NIRF के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- अगले साल से एनआईआरएफ रैंकिंग श्रेणियों में नवाचार और उद्यमिता भी शामिल होगी।
- आईटीआई और पॉलिटेक्निक की रैंकिंग पर पहले से ही काम चल रहा है।
- जल्द ही एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां प्रत्येक स्कूल को भी मान्यता दी जाएगी।

RAO'S ACADEMY

- प्रत्यायन और रैंकिंग विदेशी संस्थानों को इसका हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।

पैरामीटर्स और वेटेज की पांच व्यापक श्रेणियां:

एनआईआरएफ में पहचाने गए मापदंडों की पांच व्यापक श्रेणियां और 10 के पैमाने पर उनका भार नीचे दिया गया है:

क्रमांक सं.	पैरामीटर	मार्क्स	वेटेज
1.	शिक्षण, सीखना और संसाधन	100	0.30
2.	अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास	100	0.30
3.	स्नातक परिणाम	100	0.20
4.	आउटरीच और समावेशिता 100	0.10	
5.	धारणा	100	0.10

- इन पांच मापदंडों में से प्रत्येक में 2 से 5 उप-पैरामीटर हैं।
- विभिन्न श्रेणियों और विषय डोमेन में एचईआई की रैंकिंग के लिए कुल 18 - 21 उप-पैरामीटर का उपयोग किया जाता है।

रैंकिंग की मुख्य विशेषताएं

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार चौथे वर्ष समग्र श्रेणी में और लगातार सातवें वर्ष इंजीनियरिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु लगातार सातवें वर्ष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर है।
  - ♦ यह लगातार दूसरे वर्ष अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा।
- आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन विषय में लगातार तीसरे वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखते हुए अव्वल रहा।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली लगातार पांचवें वर्ष चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर है।
- इसके अलावा, एम्स को पहली बार समग्र श्रेणी में 9वें स्थान पर रखा गया है।
- जामिया हमदर्द लगातार चौथे वर्ष फार्मेसी में रैंकिंग में शीर्ष पर है।
- मिरांडा हाउस लगातार छठे वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखता है।
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु लगातार पांचवें वर्ष कानून में अपना पहला स्थान बरकरार रखता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण मूल्यांकन आयोजित किया गया था।

- यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है।

सत्यमेव जयते

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES

प्रमुख बिंदु

- मूल्यांकन किए गए सभी सरकारी पोर्टलों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था-
  - ♦ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/केंद्रीय मंत्रालय पोर्टल
  - ♦ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल।
- आकलन के चार मुख्य मानदंड थे:-
  - ♦ सरल उपयोग
  - ♦ सामग्री उपलब्धता
  - ♦ उपयोग में आसानी और सूचना सुरक्षा
  - ♦ केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता
- केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों के लिए अतिरिक्त तीन मापदंडों का भी उपयोग किया गया - अंतिम सेवा वितरण, एकीकृत सेवा वितरण और स्थिति और अनुरोध ट्रैकिंग।
- केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय (MHA) की वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया है।
- केंद्रीय मंत्रालय सेवा पोर्टल के तहत डिजिटल पुलिस पोर्टल को 2 पर रखा गया है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR-PG) के बारे में

- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR-PG) प्रशासनिक सुधारों के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।
- इसलिए, वे सामान्य रूप से राज्यों से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों और विशेष रूप से केंद्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए काम करते हैं।
- विभाग सार्वजनिक सेवा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग के क्षेत्र में भी गतिविधियों का संचालन करता है।
- DAR-PG कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन है और इसके अध्यक्ष सचिव हैं।

ई-विद्या को यूनेस्को की मान्यता

यूनेस्को ने स्कूली शिक्षा में पीएम ई-विद्या योजना के तहत आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के भारत के उपयोग को मान्यता दी है।

- केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (CIET) को 2021 संस्करण के लिए यूनेस्को के किंग हामिद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह पुरस्कार सभी के लिए शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने के लिए नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोणों को मान्यता देता है।
- यह सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 के अनुरूप है।
- यह बहरीन साम्राज्य के सहयोग से 2005 में स्थापित किया गया था।
- पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं:-
  - ♦ डिजिटल युग में सीखने, सिखाने और समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए।

पीएम ई-विद्या के बारे में

- कोरोना वायरस संक्रमण के समय में बच्चों की शिक्षा के नुकसान को कम करने के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत पीएम ई-विद्या की शुरुआत की गई है।
- इसे मई 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्म निर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है।
- यह सीखने के नुकसान को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है।
- PM eVidya की प्रमुख पहलों में से एक 12 e-Vidya TV चौनल हैं जो कक्षा 1 से 12 के लिए 'वन क्लास-वन चौनल' लाइन पर आधारित हैं।
  - ♦ चौनल संबंधित कक्षाओं से संबंधित शैक्षिक सामग्री प्रसारित करते हैं।
  - ♦ 12 e-Vidya DTH चौनल विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं।

ये चौनल एनसीईआरटी और अन्य एजेंसियों जैसे सीबीएसई, केवीएस, एनआईओएस, रोटरी, आदि द्वारा विकसित पाठ्यक्रम-आधारित शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करते हैं।

- एक वर्ग एक टीवी कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा पीएम ईविद्या कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी तक किया जाएगा।
- इसके अलावा, विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब और 75 स्किल लैब होंगे।
- दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए सरकार रेडियो पॉडकास्ट भी करेगी।
- पीएम ईविद्या कार्यक्रम में ई-कंटेंट 'दीक्षा' और क्यूआर कोडेड एनर्जेटिक बुक शामिल होगी।
- इसे छात्रों की सभी सीखने की जरूरतों के लिए एक ही स्थान पर समाधान के रूप में देखा गया है

नोट: CIET भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की एक घटक इकाई है।

20वां लोक मेला और 13वां कृषि मेला

जनजातीय मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री ने ओडिशा के पुरी में सारधबली में 20वें लोक मेले और 13वें कृषि मेले 2022 का उद्घाटन किया।

- दो मेलों का उद्देश्य जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करना और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना है।

प्रमुख बिंदु

- 20वें लोक मेले 2022 का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति के महत्व पर जोर देना और इसकी मौलिकता और विशिष्टता स्थापित करना है।

- मेले के माध्यम से जनजातीय समुदायों के समूहों और व्यक्तियों को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने में अपनी प्रतिभा दिखाने में मदद करने का प्रयास किया जा रहा है।
- 13वां कृषि मेला कृषि से संबंधित नवाचारों, उत्पादों, समाधानों और सेवाओं के साथ सभी संगठनों और कंपनियों के लिए एक मंच है।

- प्रदर्शनी में कृषि और संबद्ध उद्योग के पूरे स्पेक्ट्रम के प्रतिनिधि शामिल हैं।
  - ♦ प्रतिनिधियों में कृषि, फूलों की खेती, जलीय कृषि, रेशम उत्पादन और अन्य क्षेत्रों में निर्माता, डीलर, व्यापारी, निर्यातक और सलाहकार शामिल हैं।

निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल (NIPUN)

आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 'NIPUN(निपुण)' नामक निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक अभिनव परियोजना शुरू की।

- परियोजना NIPUN दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) की अपनी प्रमुख योजना के तहत MoHUA की एक पहल है।

RAO'S ACADEMY

प्रमुख बिंदु

- इसका उद्देश्य नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करना है। और उन्हें विदेशों में भी काम के अवसर प्रदान करता है।
- यह पहल निर्माण उद्योग में भविष्य के रुझानों को अपनाने के दौरान निर्माण श्रमिकों को अधिक अनुभवी और कुशल बनाने में सक्षम बनाएगी।

क्वाल-छन्स्ड . के बारे में

- दीन दयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) का उद्देश्य कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर शहरी गरीब लोगों का उत्थान करना है।
- आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय 1997 से एक केंद्र प्रायोजित योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) लागू कर रहा था।
- इस योजना को सितंबर, 2013 में दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- मिशन का उद्देश्य: शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और कमजोरियों को कम करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करना:
  - ♦ उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना,
  - ♦ मजबूत जमीनी स्तर के निर्माण के माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में उल्लेखनीय सुधार लाना।
  - ♦ शहरी बेघरों को चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना।
  - ♦ उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करके शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंता का समाधान करना।
  - ♦ उभरते बाजार के अवसरों तक पहुँचने के लिए शहरी स्ट्रीट वेंडर को कौशल प्रदान करना।
- डीएवाई-एनयूएलएम के घटक: इस योजना के दो घटक हैं एक शहरी भारत के लिए और दूसरा ग्रामीण भारत के लिए।
  - ♦ दीन दयाल अंत्योदय योजना के रूप में नामित शहरी घटक को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाएगा।
  - ♦ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना नामक ग्रामीण घटक को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) का मूल विश्वास यह है कि गरीब उद्यमी होते हैं और उनमें गरीबी से बाहर आने की जन्मजात इच्छा होती है।
  - ♦ चुनौती सार्थक और सतत आजीविका उत्पन्न करने के लिए उनकी क्षमताओं को उजागर करने की है।

RAO'S ACADEMY

वन नेशन वन राशन कार्ड

असम वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) को लागू करने वाला 36 वां राज्य / केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

- इसके साथ, ONORC योजना को सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पूरे देश में खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- अगस्त 2019 में इसकी स्थापना के बाद से, ओएनओआरसी के तहत लगभग 71 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन (43.6 करोड़ एनएफएसए और 27.8 करोड़ पीएम-जीकेएवाई लेनदेन) हुए हैं।
- इससे लगभग 40,000 करोड़ रुपये के बराबर खाद्यान्न सुवाह्यता के माध्यम से खाद्य सब्सिडी में पहुंचाया गया है।
- इसके अतिरिक्त, एक प्रमुख संकेतक के रूप में, वर्तमान में लगभग 3 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन का मासिक औसत दर्ज किया जा रहा है।

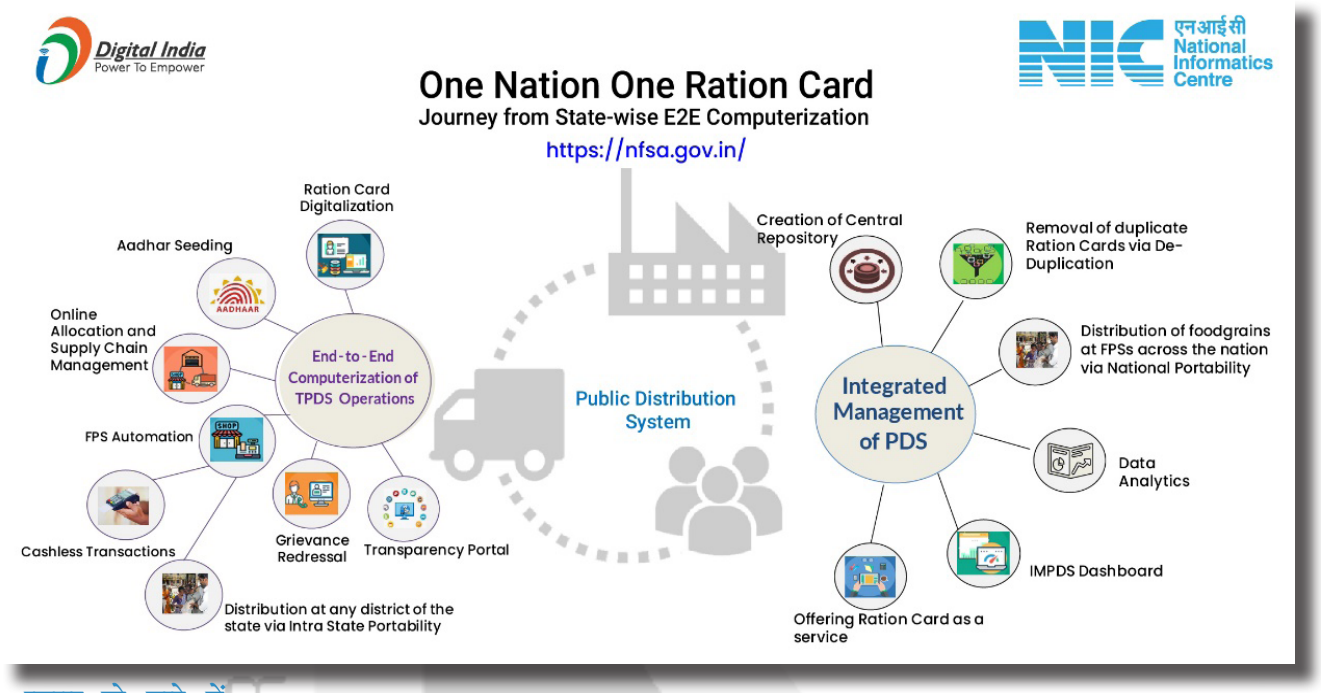

व्छव्ब के बारे में

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता के लिए विभाग द्वारा ओएनओआरसी योजना लागू की जा रही है।
- इसके माध्यम से एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र राशन कार्ड धारक/लाभार्थी देश में कहीं से भी अपनी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं।
- यह प्रणाली सभी एनएफएसए लाभार्थियों, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से पूर्ण या आंशिक खाद्यान्न का दावा करने की अनुमति देती है।
- यह मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण के साथ सहज तरीके से किया जा सकता है।
- यह प्रणाली उनके परिवार के सदस्यों को घर वापस आने की अनुमति देती है, यदि कोई हो तो उसी राशन कार्ड पर शेष खाद्यान्न का दावा करने के लिए।
- ओएनओआरसी योजना के तहत एक अन्य आयाम 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे ओएनओआरसी योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए शुरू किया गया है।
- मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी रीयल टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है।

भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए विनियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत एनसीएपी (नई कार आकलन कार्यक्रम) शुरू करने के लिए मसौदा अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।

- ऐसा CMVR (केंद्रीय मोटर वाहन नियम), 1989 में एक नया नियम 126म डालकर किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत एनसीएपी 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा।
- प्रयोज्यता: यह श्रेणी M1 के मोटर वाहनों पर लागू है।
  - ♦ यह ऐसे मोटर वाहन हैं जिनका उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है, जिसमें चालक की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं होती हैं,
  - ♦ 3.5 टन से कम सकल वाहन भार के साथ,
  - ♦ समय-समय पर संशोधित ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार देश में निर्मित या आयातित।
- भारत एनसीएपी रेटिंग उपभोक्ताओं को रहने वालों को दी जाने वाली सुरक्षा के स्तर का एक संकेत प्रदान करेगी। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में वाहन का मूल्यांकन करके किया जाएगा:
  (a) वयस्क अधिभोगी संरक्षण (एओपी)
  (b) चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (सीओपी)
  (c) सुरक्षा सहायता प्रौद्योगिकी (एसएटी)।
- एआईएस 197 के अनुसार किए गए विभिन्न परीक्षणों के खिलाफ स्कोरिंग के आधार पर वाहन को एक से पांच स्टार तक स्टार रेटिंग दी जाएगी।
- भारत एनसीएपी यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा पेश करता है और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।
- यह देश में उत्पादित कारों की निर्यात योग्यता को बढ़ावा देगा और इन वाहनों में घरेलू ग्राहकों का विश्वास बढ़ाएगा।
- इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम निर्माताओं को उच्च रेटिंग अर्जित करने के लिए उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियां प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

7 दिसंबर 1987 के संकल्प 42/112 द्वारा, महासभा ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया।

- यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त एक अंतरराष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के अपने दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति है।

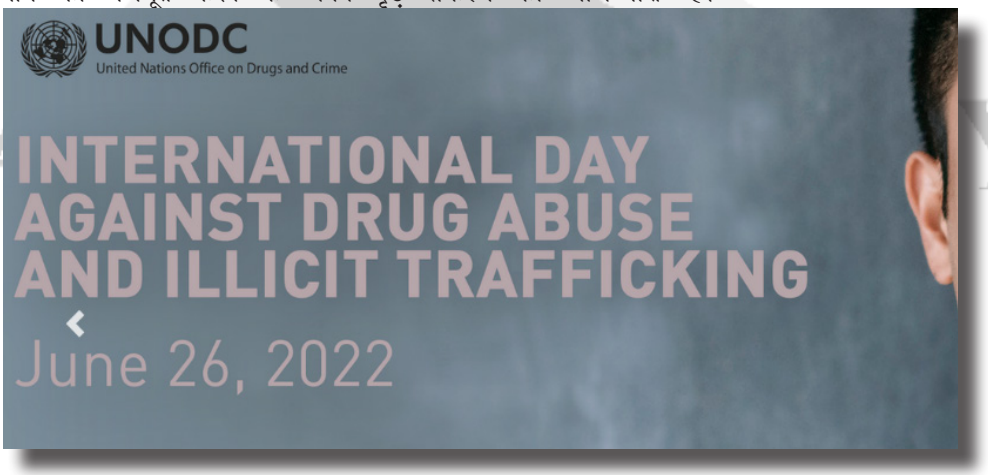

प्रमुख बिंदु

- इस वर्ष का विषय "स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान" है।
- उद्देश्य तथ्यों को साझा करके और उपचार, रोकथाम और देखभाल के तरीके प्रदान करके गलत सूचना से लड़ना है।
- समाज पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके बिना एक दुनिया बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE-L), शिक्षा मंत्रालय ने 2018-19 और 2019-20 के लिए जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI-D) जारी किया।

- यह व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी में से एक है।
  - ♦ इसमें लगभग 15 लाख स्कूल, 97 लाख शिक्षक और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26 करोड़ छात्र हैं।
- DoSE-L ने राज्यों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) तैयार किया और संदर्भ वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए रिपोर्ट जारी की।
- राज्य पीजीआई की सफलता के आधार पर, 83-संकेतक आधारित पीजीआई फॉर डिस्ट्रिक्ट (पीजीआई-डी) को स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को ग्रेड देने के लिए डिजाइन किया गया है।
- आंकड़ों को जिलों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है।
- पीजीआई-डी से राज्य के शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने और विकेन्द्रीकृत तरीके से उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
- संकेतक-वार पीजीआई स्कोर उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां एक जिले को सुधार करने की आवश्यकता है।
- पीजीआई-डी संरचना में 83 संकेतकों में 600 अंकों की कुल भार आयु शामिल है।
- इन संकेतकों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है:
  - ♦ परिणाम,
  - ♦ प्रभावी कक्षा लेनदेन,
  - ♦ अवसंरचना सुविधाएं और छात्र की पात्रताएं,
  - ♦ स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण,
  - ♦ डिजिटल लर्निंग,
  - ♦ शासन प्रक्रिया।
- इन श्रेणियों को आगे 12 डोमेन में विभाजित किया गया है।
- पीजीआई-डी जिलों को दस ग्रेड में वर्गीकृत करता है।
  - ♦ उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड दक्ष है, जो उस श्रेणी या समग्र में कुल अंकों के 90% से अधिक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए है।

RAO'S ACADEMY
YOUR SUCCESS OUR PRIORITY

- ♦ पीजीआई-डी में निम्नतम ग्रेड को आकांक्षा-3 कहा जाता है जो कुल अंकों के 10% तक के स्कोर के लिए होता है।

भारत की टमटम और प्लेटफार्म अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट

नीति आयोग ने 'इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की।

- रिपोर्ट अपनी तरह का पहला अध्ययन है जो भारत में गिग-प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट क्षेत्र के वर्तमान आकार और रोजगार सृजन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति संबंधी दृष्टिकोण प्रदान करती है।
- यह उभरते हुए क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
- यह विभिन्न कैट (7.7 मिलियन) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत करता है जो गिग इकॉनमी में लगे हुए थे।
- उन्होंने भारत में गैर-कृषि कार्यबल का 2.6% या कुल कार्यबल का 1.5% का गठन किया।
- गिग कार्यबल के 2029-30 तक 2.35 करोड़ (23.5 मिलियन) श्रमिकों तक विस्तारित होने की उम्मीद है।
- 2029-30 तक भारत में गिग श्रमिकों के गैर-कृषि कार्यबल का 6.7% या कुल आजीविका का 4.1% होने की उम्मीद है।
- वर्तमान में, लगभग 47% गिग कार्य मध्यम कुशल नौकरियों में, लगभग 22% उच्च कुशल नौकरियों में और लगभग 31% कम कुशल नौकरियों में है।
- भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी कम रही है, जो पिछले कुछ वर्षों में 16 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच रही है।
- इसी तरह, विकलांग व्यक्तियों, जो भारत की आबादी का 2.11 प्रतिशत हैं, की श्रम शक्ति भागीदारी दर 36 प्रतिशत है।
- रुझान से पता चलता है कि मध्यम कौशल में श्रमिकों की एकाग्रता धीरे-धीरे घट रही है और कम कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

महत्वपूर्ण सिफारिशें

- गिग-प्लेटफॉर्म क्षेत्र की क्षमता का दोहन करने के लिए, रिपोर्ट विशेष रूप से प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों के माध्यम से वित्त तक पहुँच में तेजी लाने की सिफारिश करती है।
- व्यवसायों के लिए कर-विराम या स्टार्टअप अनुदान जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं।
- रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा उपायों जैसे आय सहायता, पेड सिक लीव्स, बीमा और पेंशन योजनाओं का विस्तार करने की भी सिफारिश की गई है।
- ऐसी योजनाएं और नीतियां बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी में एक फर्म द्वारा विशिष्ट रूप से डिजाइन की जा सकती हैं।
  - ♦ इसे सरकार के सहयोग से भी पेश किया जा सकता है, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत परिकल्पित है।

गिग इकोनॉमी क्या है?

गिग इकॉनमी में, अस्थायी, लचीली नौकरियां आम हैं और कंपनियां पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों को काम पर रखती हैं।

- सीधे शब्दों में कहें, तो पद अल्पकालिक हैं और कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक जुड़ाव रखते हैं।
- गिग इकॉनमी में काम के लचीलेपन और दुनिया में कहीं से भी दूर से काम करने के विकल्प सहित कई ड्राइविंग कारक हैं।
- इसके अलावा, गिग कार्यकर्ता निश्चित शुल्क (अनुबंध करते समय) मॉडल, समय और प्रयास मॉडल आदि पर काम करते हैं।
- स्टार्ट-अप संस्कृति ने फ्रीलांसिंग और संविदात्मक कार्य के विचार को भी बढ़ावा दिया है।
- इस तरह के रोजगार की समस्या सामाजिक सुरक्षा, काम करने की स्थिति और काम करने के अधिकार आदि की कमी है।
- यह काफी हद तक अनियमित है जिसके परिणामस्वरूप कम नौकरी की सुरक्षा और नाममात्र का लाभ मिलता है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

7 अंतरराष्ट्रीय संबंध

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौते

भारत और यूरोपीय संघ ने भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की।

- दूसरे दौर की वार्ता सितंबर 2022 में ब्रुसेल्स में होने वाली है।

भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार के बारे में

- 2021-22 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 116.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वैश्विक व्यवधानों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार ने 2021-22 में 43.5% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि हासिल की।
- वर्तमान में यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।

सेशेल्स स्वतंत्रता दिवस में भारत की भागीदारी

भारतीय नौसेना की टुकड़ी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सेशेल्स रक्षा बल (SDF) के कर्मियों और सेशेल्स गणराज्य के नागरिकों में शामिल हुई।

- INS कोलकाता, भारतीय नौसेना का एक स्वदेश निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में तैनात किया गया था।

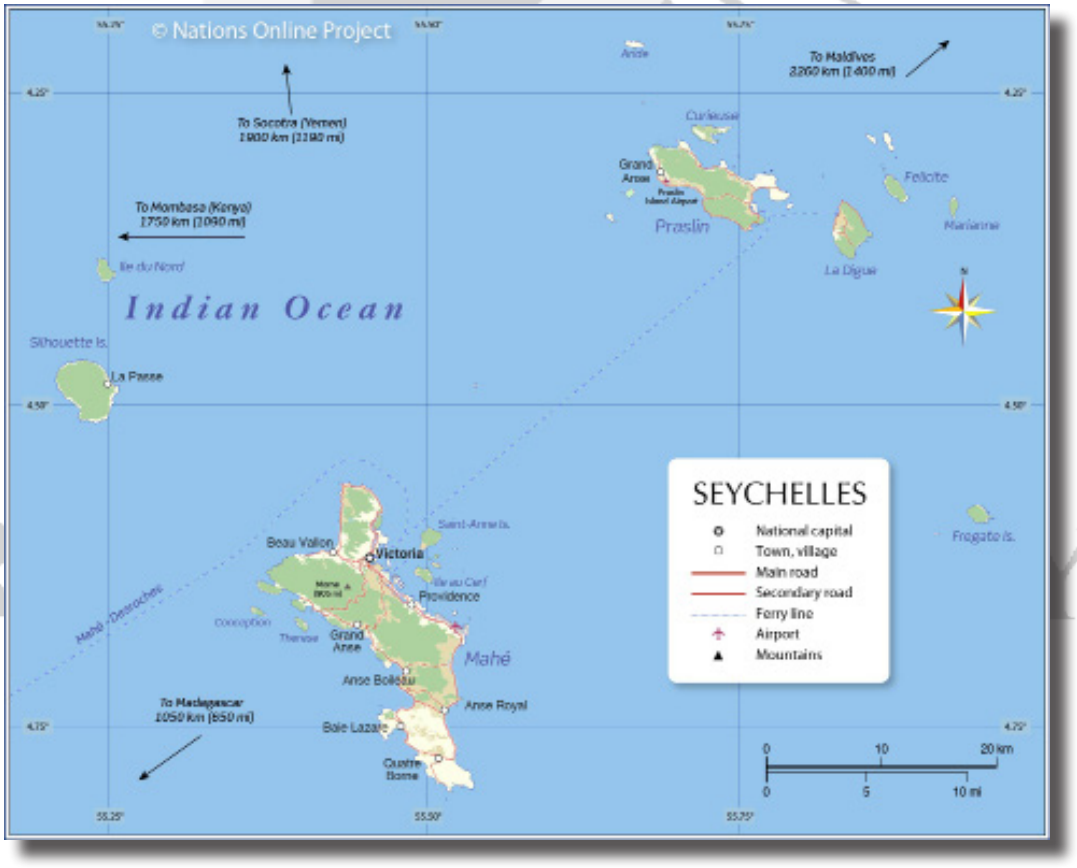

सेशेल्स के बारे में

- सेशेल्स मेडागास्कर के उत्तर-पूर्व हिंद महासागर में लगभग 100 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
- प्रमुख द्वीप माहे, प्रस्लिन और ला डिग्यू हैं।
- राजधानी और सबसे बड़ा शहर (2011 स्था.): विक्टोरिया
- मौद्रिक इकाई: सेशल्स रुपया
- भाषाएं: सेशेलोइस क्रियोल (आधिकारिक) 89.1%, अंग्रेजी (आधिकारिक) 5.1%, फ्रेंच (आधिकारिक) 0.7%, और अन्य 3.8%।
- जातीयता/जाति: मिश्रित फ्रेंच, अफ्रीकी, भारतीय, चीनी और अरब।

38वां भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती

भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 38वां भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (IND-INDO CORPAT) अंडमान सागर और मलक्का जलडमरूमध्य में आयोजित किया गया था।

- 38वां कॉर्पेट दोनों देशों के बीच महामारी के बाद का पहला समन्वित गश्ती दल (कॉर्पेट) है।
- दोनों नौसेनाएं 2002 से अपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के साथ-साथ कॉर्पेट का संचालन कर रही हैं।
- इससे दोनों नौसेनाओं के बीच समझ और अंतर्संचालनीयता बनाने में मदद मिली है।
- इसने अवैध गैर-रिपोर्टेड अनियमित (IUU) मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद आदि को रोकने और दबाने के उपायों को भी सुगम बनाया है।
- सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के भारत सरकार के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में - मुख्यालय ANC (अंडमान और निकोबार कमान) के तत्वावधान में नौसेना घटक अंडमान सागर के अन्य तटीय देशों के साथ समन्वित गश्त करता है।

I2U2 शिखर सम्मेलन

भारत के प्रधान मंत्री ने इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पहली बार I2U2 वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

- इस समूह का उल्लेख पहली बार पिछले साल अक्टूबर में एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने किया था।

प्रमुख बिंदु

- I2U2 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के लिए खड़ा है, और भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अहमद अल्बन्ना द्वारा इसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' के रूप में भी संदर्भित किया गया था।
- इसका घोषित उद्देश्य ष्पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों, हमारे संबंधित क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करनेष पर चर्चा करना है।
- देशों द्वारा परस्पर सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की गई है।
  - ♦ वे जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा हैं।
- संयुक्त अरब अमीरात ने पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की भी घोषणा की।

निवेश का उद्देश्य दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करना होगा।

- ये एकीकृत फूड पार्क खाद्य अपशिष्ट और खराब होने को कम करने, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल करेंगे।
- I2U2 समूह गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को भी आगे बढ़ाएगा।
  - ♦ इस परियोजना में 300 मेगावाट (मेगावाट) पवन और सौर क्षमता शामिल होगी, जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा पूरक होगी।

कोलंबो में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र

प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा (टीटीएफ) की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी है।

- टीटीएफ बिम्सटेक के अधीन है और कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- बिम्सटेक TTF का मुख्य उद्देश्य बिम्सटेक सदस्य राज्यों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में समन्वय, सुविधा और सहयोग को मजबूत करना है। यह प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देने, अनुभवों को साझा करने और क्षमता निर्माण द्वारा किया जाएगा।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
  - ♦ जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी,
  - ♦ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी,
  - ♦ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग,
  - ♦ कृषि प्रौद्योगिकी,
  - ♦ फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी स्वचालन,
  - ♦ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्वचालन,
  - ♦ समुद्र विज्ञान,
  - ♦ परमाणु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग,
  - ♦ ई-कचरा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी,
  - ♦ स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी,
  - ♦ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित प्रौद्योगिकियां।
- टीटीएफ का एक शासी बोर्ड होगा और टीटीएफ की गतिविधियों का समग्र नियंत्रण शासी बोर्ड में निहित होगा।
  - ♦ शासी बोर्ड में प्रत्येक सदस्य राज्य से एक नामित व्यक्ति शामिल होगा।

बिम्सटेक के बारे में

- बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (बिम्सटेक) एक क्षेत्रीय संगठन है।
- इसमें सात सदस्य राज्य शामिल हैं जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और आस-पास के क्षेत्रों में स्थित हैं और एक निकटवर्ती क्षेत्रीय एकता का गठन करते हैं।
- यह उप-क्षेत्रीय संगठन बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया।
- यह सात सदस्य राज्यों का गठन करता है:
  - ♦ बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, और सहित दक्षिण एशिया से आने वाले पांच
  - ♦ म्यांमार और थाईलैंड सहित दक्षिण पूर्व एशिया से दो।
- प्रारंभ में, चार सदस्य राज्यों के साथ आर्थिक ब्लॉक का गठन किया गया था, जिसका संक्षिप्त नाम 'BIST-EC' (बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग) था।
- बैंकाक में एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान 1997 में म्यांमार को शामिल करने के बाद, समूह का नाम बदलकर 'बिम्स-ईसी' कर दिया गया। (बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग)।
- छठी मंत्रिस्तरीय बैठक (2004, थाईलैंड) में नेपाल और भूटान के प्रवेश के साथ, समूह का नाम बदलकर BIMSCTEC कर दिया गया।
  - ♦ 'बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल' (बिम्सटेक)।
- क्षेत्रीय समूह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का गठन करता है और इन देशों के बीच

संबंधों के सुदृढ़ीकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

- बिम्सटेक ने सार्क और आसियान सदस्यों के बीच अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मंच भी स्थापित किया है।
- बिम्सटेक क्षेत्र लगभग 1.5 बिलियन लोगों का घर है जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 22% है।
- पिछले पांच वर्षों में, बिम्सटेक सदस्य राज्य वैश्विक वित्तीय मंदी के बावजूद औसतन 6.5% आर्थिक विकास प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने में सक्षम रहे हैं।

14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

भारत के प्रधान मंत्री ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

- ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

प्रमुख बिंदु

- शिखर सम्मेलन का विषय "उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत" है।
- राष्ट्राध्यक्षों ने यूक्रेन और उसके आसपास मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की।
- भ्रष्टाचार को सुरक्षित पनाहगाह से वंचित करने पर ब्रिक्स पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी क्षमता निर्माण को और मजबूत करना है।
- ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क पर भी चर्चा हुई।
- शिखर सम्मेलन ने दुनिया में नशीली दवाओं की गंभीर स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की।

ब्रिक्स के बारे में

- ब्रिक्स- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है।
- गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओश्नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा।
- ब्रिक देशों के नेता पहली बार जुलाई 2006 में जी8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिले।
- उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद, पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।
- सितंबर 2010 में BRIC समूह का नाम बदलकर BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) कर दिया गया।
- यह न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद हुआ था
- ब्रिक्स सदस्य देशों में विश्व की जनसंख्या का 41%, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सा है।

RAO'S ACADEMY

G7 शिखर सम्मेलन

भारत के प्रधान मंत्री जर्मनी के 'लॉस एल्मौ' में ग्रुप ऑफ सेवन (G7) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी में हैं।

- 2022 में जर्मनी के पास G7 की अध्यक्षता है।

प्रमुख बिंदु

- G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक अनौपचारिक मंच है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि हमेशा G7 के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की वार्षिक बैठक में उपस्थित होते हैं।
- जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका के साथ 2022 के शिखर सम्मेलन में भागीदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है।
- WTO,WHO और IMF जैसे कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया।

G6, G7, G8 के बारे में

- पहला "विश्व आर्थिक शिखर सम्मेलन", जो बाद में G7 बन गया, 1975 में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था।
- जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुख - छह का एक समूह - फ्रांस में मिले।
- प्रतिभागियों ने 1970 के दशक की आर्थिक समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- 1976 में, कनाडा को समूह में जोड़ा गया, और पहला G7 प्यूर्टो रिको में मिला।
- 1980 के दशक में, विदेश और सुरक्षा नीति के मुद्दों को शामिल करने के लिए G7 के हित का विस्तार हुआ।
- तत्कालीन सोवियत महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव को 1991 में लंदन शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था।
- 1998 में रूस के सदस्य बनने पर आठ के समूह का गठन किया गया था।
- 2014 में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन के बाद रूस को समूह से हटा दिया गया था।
- जर्मनी इस वर्ष 7वीं बार G7 की अध्यक्षता कर रहा है।
- जापान 2023 में अध्यक्ष होगा।
- 2022 तक, G7 देश दुनिया की आबादी का 10%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 21% हिस्सा बनाते हैं।
- चीन और भारत, दुनिया के सबसे बड़े सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के साथ दो सबसे अधिक आबादी वाले देश, इस समूह का हिस्सा नहीं हैं।

8 आंतरिक सुरक्षा

स्वायत्त फ्लाइंग विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

- उड़ान परीक्षण वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक से किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- पूरी तरह से स्वायत्त मोड में संचालन करते हुए, विमान ने टेक-ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और एक सहज टचडाउन सहित एक आदर्श उड़ान का प्रदर्शन किया।
- यह उड़ान भविष्य के मानवरहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख मील का पत्थर है।
- ऐसी सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
- मानवरहित हवाई वाहन को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (ADE), बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
  - ♦ यह DRDO की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है।
- यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है।
- वायुयान के लिए प्रयुक्त एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किए गए थे।

अग्निपथ योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा देने के लिए भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है।

- योजना को अग्निपथ कहा जाता है और इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निपथ कहा जाएगा।

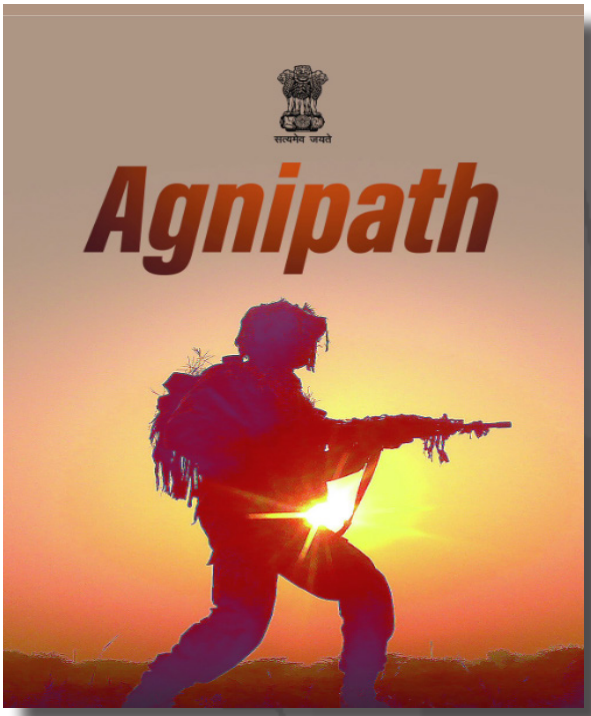

प्रमुख बिंदु

- अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों के युवा प्रोफाइल को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- यह उन युवाओं को अवसर प्रदान करेगा जो वर्दी पहनने के इच्छुक हो सकते हैं।
- ये युवा रक्त समकालीन तकनीकी प्रवृत्तियों के अनुरूप होने की उम्मीद है।
- यह परिकल्पना की गई है कि इस योजना के कार्यान्वयन से भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 4-5 वर्ष कम हो जाएगी।

अग्निशामकों को लाभ

- अग्निशामकों को तीन सेवाओं में लागू जोखिम और कठिनाई भत्ते के साथ एक आकर्षक अनुकूलित मासिक पैकेज दिया जाएगा।
- 4 वर्ष की अवधि पूरी होने पर, अग्निवीरों को एकमुश्त 'सेवा निधि' पैकेज का भुगतान किया जाएगा। पैकेज में उनका योगदान शामिल होगा जिसमें उस पर अर्जित ब्याज और सरकार से मिलते-जुलते योगदान शामिल होंगे।
- 'सेवा निधि' को आयकर से छूट प्राप्त होगी।
- ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा।
- अग्निशामकों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- राष्ट्र की सेवा की इस अवधि के दौरान, अग्निशामकों को विभिन्न सैन्य कौशल और अनुभव प्रदान किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व गुण, साहस और देशभक्ति भी पैदा होगी।
- चार साल के इस कार्यकाल के बाद, अग्निशामकों को नागरिक समाज में शामिल किया जाएगा जहां वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान दे सकते हैं।

RAO'S ACADEMY

- प्रत्येक अग्निवीर द्वारा प्राप्त कौशल को उसके अद्वितीय बायोडाटा का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रमाण पत्र में पहचाना जाएगा।
- इसके अलावा, लगभग 11.71 लाख रुपये की सेवा निधि अग्निवीर को वित्तीय दबाव के बिना अपने भविष्य के सपनों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
- सशस्त्र बलों में नियमित संवर्ग के रूप में नामांकन के लिए चुने गए व्यक्तियों को न्यूनतम 15 वर्षों की अतिरिक्त कार्य अवधि के लिए सेवा देने की आवश्यकता होगी।

वे भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों की सेवा के मौजूदा नियमों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

Year	Customised Package (Monthly)	In Hand (70%)	Contribution to Agniveer Corpus Fund (30%)	Contribution to corpus fund by GoI
	All figures in Rs (Monthly Contribution)			
1st Year	30000	21000	9000	9000
2nd Year	33000	23100	9900	9900
3rd Year	36500	25580	10950	10950
4th Year	40000	28000	12000	12000
Total contribution in Agniveer Corpus Fund after four years			Rs 5.02 Lakh	Rs 5.02 Lakh
Exit After 4 Year			Rs 11.71 Lakh as Seva Nidhi Package (Including, interest accumulated on the above amount as per the applicable interest rates would also be paid)	

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- अग्निपथ योजना के तहत, अग्निपथ को चार साल की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत बलों में नामांकित किया जाएगा।
- वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे, जो कि किसी भी मौजूदा रैंक से अलग है।
- चार साल की सेवा पूरी करने पर, अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में स्थायी नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- इन आवेदनों पर उनकी चार साल की कार्य की अवधि के दौरान प्रदर्शन सहित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर केंद्रीकृत तरीके से विचार किया जाएगा।
- उसके बाद, अग्निशामकों के प्रत्येक विशिष्ट बैच के 25% को सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में नामांकित किया जाएगा।
- नामांकन 'ऑल इंडिया ऑल क्लास' के आधार पर होगा और पात्र आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होगी।

नोटः सरकार ने फैसला किया है कि 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती चक्र के लिए एकमुश्त छूट दी जाएगी।

- तदनुसार, 2022 के लिए अग्निपथ योजना के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है।
- ऐसा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान भर्ती करना संभव नहीं हो पाया है।

YOUR SUCCESS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

9 विविध

आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), करनाल (हरियाणा) के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया।

आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के बारे में

करनाल, हरियाणा में आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) डेयरी क्षेत्र के प्रमुख संस्थानों में से एक है।

- एनडीआरआई की वंशावली इंपीरियल इंस्टिट्यूट फॉर एनिमल हसबेंडरी एंड डेयरिंग से जुड़ी है जिसकी स्थापना 1923 में बंगलौर में की गई थी।
- महात्मा गांधी और 'भारत रत्न' पंडित मदन मोहन मालवीय को 1927 में संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया।
  - ♦ वे दोनों पशु प्रबंधन के आधुनिक तरीकों से परिचित होना चाहते थे।
- 1936 में इसका विस्तार किया गया और इसका नाम बदलकर इम्पीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया और 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना गया।
- 1955 में संस्थान मुख्यालय को करनाल में स्थानांतरित करने पर, बेंगलुरु में स्थापना एनडीआरआई के दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में जारी रही।
- संस्थान देश के डेयरी उद्योग की जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेयरी शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने में अग्रणी संस्थान है।

परिमनः एनसीआर के लिए जियो-पोर्टल सार्वजनिक किया गया

रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक के प्रभावी उपयोग के उद्देश्य से एक वेब जियो-पोर्टल विकसित किया गया था।

- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा शुरू में एनसीआर भाग लेने वाले राज्यों और एनसीआरपीबी के कार्यालय द्वारा उपयोग के लिए विकसित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- यह जियो-पोर्टल एनसीआर क्षेत्र में विकेंद्रीकृत योजना और प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- पोर्टल में विभिन्न क्षेत्रों के विवरण को शामिल करते हुए लाइन, पॉइंट और पॉलीगॉन फीचर के रूप में प्रस्तुत लगभग 179 परतें शामिल हैं।
  - ♦ क्षेत्रों में भूमि उपयोग, परिवहन, उद्योग, जल, बिजली, स्वास्थ्य, आश्रय, विरासत और पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- अब, जनहित में संसाधनों के इष्टतम उपयोग के इरादे से, एनसीआरपीबी ने जियो-पोर्टल को जनता के लिए खोल दिया है।
- एनसीआर के लिए जियो-पोर्टल को 'परिमन' के रूप में जाना जाता है और इसे अगस्त, 2021 में लॉन्च किया गया था।

YOUR SUCCESS IS OUR PRIORITY
RAO'S ACADEMY

नीति आयोग ने अपने सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर का स्वागत किया

परमेश्वरन अय्यर, जिन्होंने प्रमुख 20 बिलियन अमरीकी डालर के स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया था, ने NITI Aayog के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला।

- उन्हें जल और स्वच्छता के क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
- उत्तर प्रदेश कैडर के 1981-बैच के आईएएस अधिकारी, श्री अय्यर ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ काम किया है।
- वे 2016-20 के दौरान नई दिल्ली में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव थे।

कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस)

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कागज आयात निगरानी प्रणाली (PIMS) की शुरुआत की है।

- यह प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति को 'मुफ्त' से संशोधित करके 'पीआईएमएस के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुफ्त' कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पीआईएमएस 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगा।
- हालांकि, पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा 15 जुलाई 2022 से उपलब्ध होगी।
- पीआईएमएस 201 टैरिफ लाइन को कवर करने वाले कागज उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक घरेलू क्षेत्र, क्षेत्र इकाई द्वारा आयात पर लागू होगा।
  - ♦ उत्पादों में न्यूजप्रिंट, हाथ से बने कागज, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो और ऑफसेट पेपर, टिशू पेपर, टॉयलेट पेपर, कार्टन, लेबल आदि शामिल होंगे।
- हालांकि, कागज उत्पादों जैसे करेंसी पेपर, बैंक बांड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि को अनिवार्य पंजीकरण से बाहर रखा गया है।
- पीआईएमएस के अनुसार, एक आयातक को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- यह आयात खेप के आगमन की संभावित तिथि से पहले 75वें दिन से पहले और 5वें दिन के बाद नहीं किया जाना चाहिए।
- स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
- अनुमत मात्रा के लिए पंजीकरण की वैधता अवधि के भीतर एक ही पंजीकरण संख्या में एकाधिक खेप बिल ऑफ एंट्री (बीओई) की अनुमति दी जाएगी।
- घरेलू कागज उद्योग की मांग के आधार पर, पीआईएमएस की शुरूआत का उद्देश्य "अन्य" श्रेणी टैरिफ लाइनों के तहत आयात को रोकना है।
- यह इस श्रेणी के तहत 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर' पहल को भी बढ़ावा दे सकता है।

भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा

कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिर्डी तक थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा ने अपनी यात्रा शुरू की।

- इसके साथ, दक्षिण रेलवे 'भारत गौरव' योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता पाने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है।

भारत गौरव ट्रेन के बारे में

- भारतीय रेलवे ने नवंबर 2021 के महीने में थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन के संचालन की शुरुआत की थी।
- इस थीम का उद्देश्य भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक

विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन करना है।

- इस योजना का उद्देश्य भारत की विशाल पर्यटक क्षमता का दोहन करने के लिए थीम-आधारित रेलगाड़ियों को चलाने के लिए पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की मुख्य शक्तियों का लाभ उठाना भी है।
- यह योजना आईआरसीटीसी की थीम आधारित पर्यटक ट्रेनों जैसे रामायण एक्सप्रेस के समान है।
- कोई भी परिचालक विशेष पर्यटन पैकेज के रूप में थीम आधारित सर्किट पर चलने के लिए रेलगाड़ियों को रेलवे से पट्टे पर ले सकता है।
- ऑपरेटर को मार्ग, हॉल्ट, प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सबसे महत्वपूर्ण, टैरिफ तय करने की स्वतंत्रता है।
- भारत गौरव ट्रेनों का उपयोग करने के लिए, एक संभावित सेवा प्रदाता को भारत गौरव ट्रेनों के रेक की मांग रखने के लिए पंजीकरण करना होगा।
- सेवा प्रदाता कम से कम दो साल की अवधि के लिए और कोचों के शेष जीवन तक की अधिकतम अवधि के लिए ट्रेनों की कस्टडी ले सकता है।
- रेलवे लोको और गार्ड मुहैया कराएगा।
- भारत गौरव योजना दो प्रमुख मामलों में महत्वपूर्ण है -
- पहला यह है कि यह पर्यटन क्षेत्र में डोमेन ज्ञान रखने वाले निजी खिलाड़ियों को इन विशेष ट्रेनों को चलाने की अनुमति देता है।
  - ♦ अब तक आईआरसीटीसी द्वारा इसका ध्यान रखा जाता था।
- दूसरा यह है कि रेलवे को व्यवसाय की एक नई धारा से एक वृद्धिशील राजस्व प्राप्त होता है।
  - ♦ इससे कार्गो और यात्री दोनों ट्रेनों के संचालन में और अधिक निजीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

नोटः साउथ स्टार रेल पंजीकृत सेवा प्रदाता है जो इस भारत गौरव ट्रेन को कोयंबटूर से शिरडी और वापस जाने के लिए संचालित करती है।

रक्षा मंत्रालय ने एक शीर्ष समिति का गठन किया

रक्षा मंत्रालय ने एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की है जिसमें रक्षा सचिव के अध्यक्ष के रूप में एक शीर्ष समिति शामिल है।

- इसका उद्देश्य इसकी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में एक प्रदर्शन और दक्षता लेखा परीक्षा आयोजित करना है।

प्रमुख बिंदु

- यह मौजूदा लेनदेन-आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा से परिणाम-आधारित निष्पादन/दक्षता लेखापरीक्षा करने के लिए एक प्रमुख बदलाव है।
- इसका उद्देश्य समग्र दक्षता को बढ़ाना है।
- इस प्रकार की लेखापरीक्षा से मंत्रालय के शीर्ष प्रबंधन को विशिष्ट कमियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलने की उम्मीद है।
- समिति के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ♦ तीनों सेनाओं के उप प्रमुख,
  - ♦ सचिव रक्षा (वित्त),
  - ♦ एकीकृत कर्मचारी समिति (CISC) के प्रमुख,
  - ♦ रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए),
  - ♦ महानिदेशक (अधिग्रहण),
  - ♦ रक्षा मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।
- निष्पादन और दक्षता लेखापरीक्षा के संचालन के लिए जिन व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ♦ रक्षा पूंजी खरीद,
  - ♦ रसद, सूची स्तर,
  - ♦ प्लेटफॉर्म/संपत्तियों का रखरखाव, मुहरबंद विवरण (AHSP) रखने वाले प्राधिकरण की भूमिका और प्रदर्शन आदि।
- रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली समिति सीजीडीए द्वारा प्रदर्शन और लेखा परीक्षा के संचालन के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करेगी।
  - ♦ यह निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों और उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी में मदद करेगा।
- यह रक्षा मंत्री को अपनाए जाने वाले उपचारात्मक उपायों के साथ-साथ समग्र सुधार के उपायों पर भी सलाह देगा।
- यह आंतरिक निरीक्षण और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला

जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग के तत्वावधान में केंद्रीय जल आयोग बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

- कार्यशाला का उद्देश्य बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना और भारत में बांध सुरक्षा शासन पर विचार-मंथन करना है।

प्रमुख बिंदु

- भारत में 5334 बड़े बांध मौजूद हैं जबकि अन्य 411 बड़े बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।
- बांधों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र 2394 बांधों के साथ आगे है जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात दूसरे

और तीसरे स्थान पर हैं।

- भारत के बांधों में सालाना लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है।
- लगभग 80% बांध 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और 227 से अधिक बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं।
- बांधों की उम्र बढ़ने और बांध के आस्थगित रखरखाव ने बांध की सुरक्षा को चिंता का विषय बना दिया है।
- बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 30 दिसंबर 2021 से प्रभावी हुआ।
- अधिनियम का उद्देश्य निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
- यह बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम में मदद करेगा और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) के गठन को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।
- यह समिति अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में होगी।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) भी स्थापित किया गया है।
- यह बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा।
- अधिनियम व्यापक रूप से मौजूदा और साथ ही जलवायु परिवर्तन आदि जैसे नए मुद्दों के तहत महत्वपूर्ण बांध सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करता है।
- इसके प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ♦ बांधों का नियमित निरीक्षण;
  - ♦ बांधों का जोखिम वर्गीकरण;
  - ♦ आपातकालीन कार्य योजना;
  - ♦ एक स्वतंत्र पैनल द्वारा व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा;
  - ♦ समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए धन;
  - ♦ संचालन और रखरखाव मैनुअल;
  - ♦ घटनाओं और विफलता का रिकॉर्ड;
  - ♦ जोखिम मूल्यांकन अध्ययन;
  - ♦ जल-मौसम विज्ञान और भूकंपीय नेटवर्क सहित बांध उपकरण;
  - ♦ एजेंसियों की मान्यता;
  - ♦ आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली; तथा
  - ♦ अपराध और दंड।

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के बारे में

केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है।

- यह वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण, भारत सरकार के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
- केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव की स्थिति के साथ एक अध्यक्ष होता है।
- इसकी स्थापना 1945 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य (श्रम) डॉ बी आर अम्बेडकर की सलाह

पर सरकार द्वारा की गई थी।

- **आयोग को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:**
  - ♦ संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से योजनाओं की शुरुआत, समन्वय और आगे बढ़ना,
  - ♦ देश में जल संसाधन के उपयोग का संरक्षण और नियंत्रण करना
  - ♦ बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई गतिविधियों, पेयजल आपूर्ति, जलविद्युत उत्पादन आदि के क्षेत्रों में सहायता।

44वां शतरंज ओलंपियाड

भारत के प्रधान मंत्री ने इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया।

- इस मशाल को चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में अंतिम समापन से पहले 40 दिनों की अवधि में 75 शहरों में ले जाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- हर स्थान पर राज्य के शतरंज के ग्रैंडमास्टरों को मशाल मिलेगी।
- 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।
- 1927 से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी भारत में पहली बार और 30 वर्षों के बाद एशिया में की जा रही है।
- 189 देशों के भाग लेने के साथ, यह किसी भी शतरंज ओलंपियाड में सबसे बड़ी भागीदारी होगी।

योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

योग के विकास और संवर्धन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2021 के लिए की गई थी।

- इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार 21 जून, 2016 को चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर भारत के प्रधान मंत्री द्वारा की गई थी।

RAO'S ACADEMY

प्रमुख बिंदु

- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश विकसित किए थे।
- एक स्क्रीनिंग कमेटी (प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए) और मूल्यांकन समिति (अंतिम मूल्यांकन के लिए जूरी) के माध्यम से दो चरणों की चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
- MyGov प्लेटफॉर्म पर एक खुले विज्ञापन के माध्यम से 2021 के पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे।
- वर्ष 2021 के लिए योग के विकास और संवर्धन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार के पुरस्कार विजेता निम्नलिखित हैं:

- ♦ श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स, साओ पाउलो, ब्राजील-अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति
- ♦ ब्रिटिश व्हील ऑफ योग, यूनाइटेड किंगडम- अंतर्राष्ट्रीय संगठन
- ♦ श्री भिक्खु संघसेना, लेह, लद्दाख- राष्ट्रीय व्यक्ति
- ♦ द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश, उत्तराखंड- राष्ट्रीय संगठन

- लेह के भिक्षु संघसेना इस वर्ष पुरस्कार प्राप्त करने वाले चार प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। वह लद्दाख के एक बौद्ध भिक्षु हैं।
- विजेताओं को एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक नकद पुरस्कार का मूल्य 25 लाख रुपये होगा।

1.30 लाख छात्र योग प्रशिक्षक के रूप में

समग्र कल्याण के लिए योग को बढ़ावा देने के लिए, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (B-WSSC) ने 8वें अंत. राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया।

- ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (B-WSSC) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तत्वावधान में काम कर रही है।

प्रमुख बिंदु

- आयोजन का विषय था 'योग को हाँ और रोग को ना'।
- कार्यक्रम के बाद कौशल भारत मिशन के तहत बी एंड डब्ल्यूएसएससी के अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए "दीक्षांत समारोह" का आयोजन किया गया।
- एमएसडीई योग के क्षेत्र में विभिन्न करियर संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बी एंड डब्ल्यूएसएससी के साथ मिलकर काम कर रहा है।
  - ♦ यह विचार युवाओं को एक आशाजनक भविष्य के लिए उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **B-WSSC योग के लिए तीन विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करता है –**
  - ♦ योग प्रशिक्षक (बी एंड डब्ल्यू) एनएसक्यूएफ 4,
  - ♦ योग ट्रेनर (बी एंड डब्ल्यू) एनएसक्यूएफ 5,
  - ♦ वरिष्ठ योग प्रशिक्षक (बी एंड डब्ल्यू) एनएसक्यूएफ 6।
- आर्ट ऑफ लिविंग, योग संस्थान और पतंजलि जैसी संस्थाएं सेक्टर स्किल काउंसिल से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने इसकी सफलता में योगदान दिया है।
- निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले आठ वर्षों में देश भर में 1.30 लाख से अधिक छात्रों को योग प्रशिक्षकों और प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।
- B-WSSC के अनुसार, सबसे अधिक कुशल योग छात्रों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि हैं।
- क्षेत्र कौशल परिषद में कक्षा XI और XII से शुरू होने वाले सीबीएसई स्कूलों के लिए योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी हैं।

बी एंड डब्ल्यूएसएससी के बारे में

- सौंदर्य और कल्याण क्षेत्र कौशल परिषद (बी एंड डब्ल्यूएसएससी) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा स्थापित स्वायत्त उद्योग के नेतृत्व वाले निकायों में से एक है।
- यह सीआईआई द्वारा प्रवर्तित लाभ के लिए नहीं संगठन है।
- इसका उद्देश्य सौंदर्य और स्वास्थ्य उद्योग में कौशल विकसित करने और प्रदान करने के लिए एक प्रभावी और कुशल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना है।

RAO'S ACADEMY

" विद्याधनं सर्व धनं प्रधानम् "

RAO'S ACADEMY
for Competitive Exams
(A unit of **RACE**)

आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता

ADDRESS: **R-26, Zone-II, Opp, Railway Track, M.P. Nagar, Bhopal**
CONTACT: **0755-7967814, 7967718, +91 83196 18002**
EMAIL: info@theracefoundation.com
WEBSITE: **www.theracefoundation.com**